राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिये केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं, उसके कार्यक्रमों और विजन का सारांश में खुलासा किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में पीएम मोदी की राजग सरकार की उन परियोजनाओं की प्रशंसा की, जिन्हें देश की जनता बखूबी जानती है, भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ये जनादेश है कि भारत को विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करे। लेकिन भारत में आर्थिक असमानताएं काफी व्यापक हैं। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति आय 1.75 लाख रुपये भी नहीं है। आज भी 22-25 करोड़ भारतीय ऐसे हैं, जो हर रोज़ 350 रुपये ही कमा पाते हैं। इसलिए मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा यह है कि वह विकास के सभी स्तंभों की बुनियाद मजबूत करे। आज भी अगले चरण के आर्थिक सुधार, विधिक सुधार, शिक्षा सुधार, श्रम सुधार, पुलिस और प्रशासनिक सुधार लंबित पड़े हैं, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे पाई है। अभिभाषण में महंगाई, मणिपुर हिंसा और घुसपैठ, रेल हादसों, कश्मीर में आतंकवाद सरीखे मुद्दों को का जिक्र नहीं है। अभिभाषण का विश्लेषण करता आजकल का यह अंक...

अभिभाषण में भविष्य का विजन

विश्लेषण
सुशील राजेश
वरिष्ठ पत्रकार

राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत सरकार का ही दस्तावेजी वक्तव्य होता है। भारत सरकार का उपसचिव या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी यह अभिभाषण लिखता है। संविधान के अनुच्छेद 87(1) में राष्ट्रपति अभिभाषण का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। संसद को उनके आह्वान के कारण बताएंगे। हर साल के आरंभ में भी राष्ट्रपति संसद की साझा बैठक को संबोधित करेंगे। संवैधानिक प्रावधान है कि अभिभाषण को लेकर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद ज्ञापन के तौर पर प्रधानमंत्री पूरी चर्चा का जवाब देंगे। यह संसदीय और संवैधानिक बाध्यता है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत सरकार का ही दस्तावेजी वक्तव्य होता है। भारत सरकार का उपसचिव या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी यह अभिभाषण लिखता है और राष्ट्रपति उसे पढ़ते हैं, क्योंकि सरकार राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होती है। यह गणतंत्र की एक परंपरा है कि राष्ट्रपति संसद की साझा बैठक को संबोधित करते हैं। अभिभाषण के मायने स्पष्ट हैं कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं, उसके कार्यक्रमों और विजन का सारांश में खुलासा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसी गरिमामय परंपरा का निर्वाह किया है। उन्होंने मोदी सरकार की उन परियोजनाओं की प्रशंसा की, जिन्हें देश की जनता बखूबी जानती है, लेकिन विपक्ष उनसे सहमत नहीं है या ऐसे अभिभाषण को 'ढोलपिटाई' मानता है। विपक्ष उन्हें लीपापोती भी मानता है अथवा झूठे आंकड़े करार देता है। मसलन-गरीबी से बाहर निकालने वाले लोगों का डाटा सवालिया है। देश की जनता परियोजनाओं से इसलिए भी वाकिफ है, क्योंकि वह ही लाभार्थी है। राष्ट्रपति मुर्मू का फोकस नई सरकार के जरिये देश के आर्थिक समृद्धि और सुधारों पर अधिक रहा है। यकीनन देश की आर्थिक विकास दर 7-8 फीसदी रही है और भारत का औसत विकास विश्व में सर्वाधिक है। भारत जल्द विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होगा, सरकार का यह संकल्प है। यानी जापान और जर्मनी भी भारत से पीछे होंगे। राष्ट्रपति का उल्लेख कोई नया नहीं है। सत्तारूढ़ पक्ष अक्सर ऐसे दावे करता रहा है। आम चुनाव के दौरान ऐसे डाटा की भरमार रही, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रपति के जरिये यह खुलासा कराया है, लिहाजा उसे विश्वसनीय मानना चाहिए।

संवैधानिक प्रावधान

बहरहाल संविधान के अनुच्छेद 87(1) में राष्ट्रपति अभिभाषण का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र के आरंभ में समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। संसद को उनके आह्वान के कारण बताएंगे। हर साल के आरंभ में भी राष्ट्रपति संसद की साझा बैठक को संबोधित करेंगे। संवैधानिक प्रावधान है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बिंदुओं पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी व अंत में प्रधानमंत्री पूरी चर्चा का जवाब देंगे। यह संसदीय और संवैधानिक बाध्यता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण में कई मुद्दों का उल्लेख किया है। उनमें नीट, पेपर लीक भी एक है, जिस पर राष्ट्रपति ने शुचिता और पारदर्शिता की अपेक्षा की है। उनकी इच्छा है कि पेपर लीक जैसी हरकतों, ऐसे नेटवर्क, माफिया, संगठनों पर एक कड़ा कानून सख्त और दंडात्मक कार्रवाई हो। इस संदर्भ में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सांसदों को काम करना चाहिए, यह राष्ट्रपति मुर्मू का विनम्र आग्रह रहा, लेकिन नीट पर विपक्ष की ऐसी राजनीतिक जिद सामने आई है कि संसद की कार्यवाही ही ठप हो गई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उपनेता प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद 'वेल' में आ गए। उपराष्ट्रपति एवं सभापति जगदीप धनखड़ को उसे 'काला दिन' करार देना पड़ा, क्योंकि पहली बार नेता प्रतिपक्ष 'वेल' में आए थे और उनके साथी सांसद नारेबाजी कर रहे थे। लोकसभा में भी कांग्रेसी सांसद स्पीकर के आसन तक आ गए और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने माइक बंद किए जाने का आरोप दोहराया। स्पीकर ने उन्हें समझाया कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भी नीट का उल्लेख है। आप अभिभाषण पर बोलें और नीट पर भी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे, क्योंकि उन्हें नीट पर राजनीति हासिल करनी थी। सुर्खियां 'माइक बंद' की बनीं।

यह सवाल भी सुर्खियों में

यह सवाल भी सुर्खियों और बहसों में छाया रहा कि पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा की जानी चाहिए थी अथवा नीट, पेपर लीक सरीखे मुद्दे पर चर्चा बहुत जरूरी थी? राष्ट्रपति ने सिर्फ नीट का ही मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि मोदी सरकार के आर्थिक विज़न पर भी फोकस रखा। बेशक नीट को लेकर सड़कों पर छात्र, युवा आंदोलित, आक्रामक हैं, लेकिन संसद में सन्नाटा पसरा, क्योंकि दोनों सदनों में हंगामे और जिद के कारण कार्यवाही सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी। क्या पीठासीन अध्यक्षों को, संसदीय बाध्यता तोड़ते हुए, नीट पर चर्चा की अनुमति दे देनी चाहिए थी? मैं 1997 से संसद की कार्यवाही कवर करता रहा हूं, लिहाजा संसदीय नियमों, परंपराओं, मर्यादाओं को बखूबी जानता और समझता हूं। नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपने विचार रखते हुए विस्तार से नीट, पेपर लीक, 37 लाख से अधिक युवाओं के अनिश्चित भविष्य, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के भ्रष्टाचार और अपंगता पर बोल सकते थे। समय की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक अड़यिलपन ने ऐसा अवरोध पैदा किया कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर संसद का एक पूरा दिन नष्ट हो गया। संभवतः विपक्षी सांसद भी जानते होंगे कि संसद की एक मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं। एक घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपये है। लोकसभा के एक दिन संचालन पर 9 करोड़ रुपये और राज्यसभा पर 5.5 करोड़ रुपये खर्च होता है। यह पैसा किसी की जिद का नहीं, बल्कि देश के औसत करदाता का है। यह सत्र 3 जुलाई तक का है। प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई को लोकसभा और 3 जुलाई को राज्यसभा को संबोधित करेंगे। उसी के साथ अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दोनों सदनों के अध्यक्ष सिर्फ नीट व पेपर लीक पर चर्चा के लिए एक पूरा दिन निश्चित कर दें। सत्र को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दें। क्या विपक्ष इस पर सहमत होगा?

बजट का प्रारूप भी रखा

बहरहाल राष्ट्रपति मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में पेश किए जाने वाले बजट का एक विजन भी रखा कि वह भारत की जनता की आकांक्षाओं और ज़रूरतों के अनुसार होगा। संसद के जुलाई सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा, वह वाकई जनवादी होगा। उसमें सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विज़न के साथ-साथ ऐतिहासिक कदम भी उठाए जाएंगे। बेशक राष्ट्रपति भी उन कदमों का खुलासा नहीं कर सकती थीं, क्योंकि बजट की गोपनीयता का तकाजा था। यह गौरतलब रहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति के सौजन्य से यह सिद्धांत स्पष्ट करा दिया कि देश का विकास, उसके राज्यों के विकास पर ही, आश्रित है, क्योंकि तभी एक राष्ट्र के समग्र विकास का आकलन किया जा सकता है और एक राष्ट्रीय तस्वीर सामने आती है। इस विकास में प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए और सहकारिता का भाव भी रहना चाहिए। यही भारत का सच्चा संघीयवाद है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कुछ ऐसे क्षेत्रों का भी उल्लेख किया है, जो 'सूर्योदय' की तरह माने जाते हैं। मसलन-विद्युत वाहन, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी आदि। इन क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रगति के प्रतीक साबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन का भी जिक्र किया, जो बराबर की चुनौती है और सरकार उस संदर्भ में लगातार सक्रिय है। यह भी वैश्विक चुनौती है जो किसी महामारी से कम खतरनाक नहीं है। दरअसल जो सड़कें, पुल, राजमार्ग, एक्सप्रेस वे आदि बनाए जा रहे हैं, रेल और हवाई यात्रा का विस्तार किया गया है, कमोबेश उन्हें मोदी सरकार का 'हॉलमार्क' माना जाता है। ऐसे बुनियादी ढांचे से कुछ गंभीर हादसे भी जुड़े रहे हैं। उनके गर्भ में भ्रष्टाचार मिला है। सरकार उन पर नियंत्रण लाए। यह साख के लिए भी जरूरी है।

लड़ाई अभी लंबी है

यकीनन भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, लेकिन विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे गरीब देश भी होगा। यह लड़ाई अभी बहुत लंबी है। भारत में आर्थिक असमानताएं काफी व्यापक हैं। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति आय 1.75 लाख रुपये भी नहीं है। आज भी 22-25 करोड़ भारतीय ऐसे हैं, जो हर रोज़ 350 रुपये ही कमा पाते हैं। दरअसल मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा यह है कि वह विकास के सभी स्तंभों की बुनियाद मजबूत करे। आज भी कई आर्थिक सुधार, विधिक सुधार, शिक्षा सुधार, रोज़गार एवं श्रम सुधार, पुलिस और प्रशासनिक सुधार ऐसे लंबित पड़े हैं, जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे पाई है। खासकर कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को इतना मजबूत करना जरूरी है, ताकि वे व्यापक रोज़गार और नौकरियां पैदा कर सकें और करोड़ों बेरोज़गारों को माकूल काम दिया जा सके। भारत की एक नाजुक और गंभीर समस्या का हल भी उसी से संभव है। उसी से आर्थिक विकास बढ़ता है। सवाल यह भी किया जाना चाहिए कि सरकार ने महंगाई, मणिपुर हिंसा और विदेशी घुसपैठ, रेल हादसों, कश्मीर में अब भी सक्रिय आतंकवाद और दलित अत्याचार सरीखे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रपति अभिभाषण में शामिल क्यों नहीं किया? राष्ट्रपति मुर्मू से 1975 के आपातकाल को 'काला अध्याय' करार दिलाया गया, संविधान पर सबसे घातक हमला कहलवाया गया, लेकिन इस बिन्दु पर सरकार खामोश क्यों रही कि संविधान बदला नहीं जा सकता। लोकतंत्र भारत की आत्मा में है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रपति टिप्पणी करतीं और देश को आश्वस्त करतीं, तो विपक्ष का एक फर्जी नैरेटिव समाप्त किया जा सकता था।

निरंतरता का संदेश दे रही मोदी सरकार

अभिभाषण
अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के अब तक के कार्य व्यवहार को देखते हुए सामान्य तौर पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि इसमें कोई रेखांकित करने वाला मौलिक बदलाव है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी सरकार, विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है। मोदी सरकार जब भी विरासत की बात करती है उसे हिंदुत्व एवं उसकी विचारधारा से जोड़ा जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के आरंभ में ये पंक्तियां डाली गई हैं तो साफ है कि सरकार संदेश देना चाहती है कि भले भाजपा को बहुमत नहीं मिला, राजग को मिला, लेकिन यह गठबंधन भी चुनाव पूर्व का है और हमारे कार्यों, हमारी घोषणाओं को स्वीकार करते हुए हुआ है, इसलिए हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। किसी साथी दल ने सरकार को पूर्व एजेंडे में कुछ बदलाव करते हुए नए सिरे से न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की मांग नहीं की है। माना जा रहा है कि कुछ बिंदुओं को छोड़कर भाजपा अपने घोषणा पत्र पर ही आगे बढ़ रही है। अभिभाषण में इसकी झलक मिलती है। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है और यही सरकार के भविष्य की दिशा व दशा काफी हद तक स्पष्ट करने में सहायक होंगे।

चुनाव परिणामों की व्याख्या

इनमें पहला है, 2024 लोकसभा चुनाव के परिणामों की व्याख्या। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। ...मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत को विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करे। विपक्ष अभिभाषण को चाहे जितना निरर्थक बताए सरकार के लिए महत्वपूर्ण है साथी दलों का किसी प्रकार की आपत्ति न करना। स्पष्ट संदेश है कि जनादेश हमको अपने पूर्व कार्यों और दिशा के आधार पर मिला है, इसलिए हम वही करेंगे जो कर रहे थे।

दूसरा प्रमुख बिंदु

इसका दूसरा प्रमुख बिंदु है, आगामी बजट के बारे में संकेत। राष्ट्रपति के अभिभाषण के द्वारा सरकार ने कहा कि आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधारों की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनियाभर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। इतनी स्पष्टता के साथ बजट, सुधार, आर्थिक नीति, सामाजिक निर्णय आदि के बारे में बोलने के बाद कोई संदेह नहीं पैदा होता कि सरकार की अर्थ नीति और सुधार गति में रुकावट आएगी या गठबंधन सरकार एवं विपक्ष के दबाव से बदलाव किया जाएगा।

विकास पर प्रभावों की व्याख्या

अभिभाषण का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अस्थिर सरकारों के देश के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत व्याख्या। अभिभाषण में कहा गया है कि अक्सर विरोधपरक मानसिकता और संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना का बहुत अहित हुआ है। इसका प्रभाव संसदीय प्रणाली पर भी पड़ता है और देश की विकास यात्रा पर भी पड़ता है। देश में कई दशकों तक अस्थिर सरकारों के दौर में कई सरकारें चाहते हुए भी न सुधार कर पाईं और न ही आवश्यक निर्णय ले पाईं। भारत की जनता ने निर्णायक बनकर इस स्थिति को बदला है। बीते 10 वर्ष में ऐसे अनेक सुधार हुए हैं, जिनका बहुत लाभ देश को आज मिल रहा है।

जब ये सुधार किए जा रहे थे, तब भी इनका विरोध किया गया था, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सारे सुधार समय की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। आगे भाषण में आप देखेंगे तो भारत के बैंकों को 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मुनाफे तथा विश्व में बेहतर बैंकिंग व्यवस्था के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी भारतीय नीतियों की सफलता का कहीं उद्घोष है। कुल मिलाकर सरकार ने अस्थिर सरकारों या दूसरे शब्दों में कहें तो गठबंधन सरकारों की आलोचना की है। यह नाम ना लेते हुए कांग्रेस या मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीएस सरकार की आलोचना है। यानी उसे सरकार ने कई प्रकार के दबाव में तथा संकीर्णता के कारण निर्णय करने से बचती रही,आवश्यक कदम नहीं उठाए और सुधार नहीं किए जिससे देश की आर्थिक दशा खराब हुई। बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई। दूसरी ओर जब हमने करना शुरू किया तो इन लोगों ने विरोध किया, गलतफहमी पैदा कर वातावरण को नकारात्मक बनाने की कोशिश की। अगर हमारी नीतियों, कदमों और निर्णयों के अच्छे परिणाम आए तो साफ है ये सब अपनी संकीर्ण मानसिकता और कुत्सित राजनीति के तहत ऐसा कर रहे थे। यह विपक्ष के वर्तमान रवैया पर भी कटाक्ष है।

युवा और शिक्षा नीति पर वक्तव्य

अभिभाषण में चौथा अहम पहलू है, युवा और शिक्षा नीति को लेकर दिया गया वक्तव्य। अभिभाषण के अनुसार सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए ज़रूरी माहौल बनाने में जुटी है। आगे देखिए,'पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करते थे, उनके साथ अन्याय की स्थिति थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर, इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। युवाओं को अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प भी मिला है।' किसी भी देश के समग्र विकास का आधार शिक्षा नीति ही होती है। विपक्ष ने सरकार की नई शिक्षा नीति की आलोचना की, लेकिन देश ने इसे स्वीकार किया है। हालांकि इसकी गति धीमी रही है, पर इस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। अभिभाषण में घोषणा है कि सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। युवाओं ने इन कदमों का पूरा समर्थन किया है। उदाहरण के लिए इसमें अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों को युवाओं का सामर्थ्य बढ़ाने वाला बताते हुए कहा गया है कि इन्हीं प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम बन चुका है।

नीतियों में बदलाव नहीं

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगर शिक्षा नीति का स्पष्ट समर्थन किया गया है तो कम से कम तत्काल यह मानने का कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में सरकार अपने पूर्व दिशा को बदलने जा रही है। मोदी सरकार की शिक्षा नीति को ही भगवाकरण और सेकुलर विरोधी तथा हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाला बताया जाता रहा है। इसमें जब बदलाव नहीं होगा तो शेष मामलों में इस तरह के वैचारिक विरोध का माहौल भी नहीं। इस तरह कुल मिलाकर मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब हमारी नीतियों का लाभ देश को हर क्षेत्र में मिला है तो हम उसे बदलने वाले नहीं है। अभिभाषण में कहा भी गया है कि हम विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे तथा हमारा लक्ष्य आगे विश्व की प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बनना है। यानी प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने तथा इसी कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था का जो संकल्प व्यक्त किया सरकार उस पर काम करती रहेगी। विदेश नीति में भारत की प्रखरता से लेकर आंतरिक सुरक्षा आदि की प्रशंसा और इस दिशा में बढ़ाने का संकल्प बताता है कि भले सरकार गठबंधन की हो लेकिन इसकी दिशा, गति और चरित्र में नैरंतर्य रखने की कोशिश होगी। विपक्ष क्या कहता है इसका लोकतांत्रिक दृष्टि से संज्ञान लेना सरकार का दायित्व है, किंतु सरकार का बने रहना या उसकी नीतियों का आगे बढ़ना विपक्ष पर नहीं, गठबंधन के साथियों पर निर्भर करता है। ऐसा लगता है कि सरकार के रणनीतिकार मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने गठबंधन के साथियों से स्पष्ट किया है कि हम काम करने के लिए सरकार में आए हैं, भारत का व्यापक और दूरगामी लक्ष्य बनाकर हम जो कर रहे थे उसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसी में देश का भला है। उनसे उनकी राय भी पूछी होगी। इस कारण सरकार अभी निश्चिंतता से आगे बढ़ेगी।

विकास को गति देने का संकल्प

अभिभाषण
नीलम महाजन सिंह
राजनीतिक विश्लेषक

18वीं लोकसभा के संयुक्त संसद सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजग सरकार का विजन देश के सामने रखा। राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता के रूप में इस बार मजबूत भूमिका में है। राष्ट्रपति के संबोधन में अनेक बातें हैं, जिसमें खास संदेश है। इसमें भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें, हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। यह आवश्यक है कि नीतियों पर सार्थक संवाद होना चाहिए।

देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए हैं। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेज़ी से विकसित होती हुई 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अब तीसरी बनने का लक्ष्य है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। सरकार ने सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों - विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गांवों में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज़ आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है।

आज का भारत, दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है। विश्व-बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज - श्री अन्न - की पहुंच सुपरफूड के तौर पर दुनिया के कोने-कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। आने वाला समय हरित युग का है। इसके लिए सरकार हर ज़रूरी कदम उठा रही है। हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब्स भी बढ़े हैं। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे पर सरकार बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रही है। भारत ग्रीन एनर्जी कर बड़ा हब बनने जा रहा है। सरकार ग्रीन हाईड्रोजन में सरकारी व निजी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 10 वर्षों में आबंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

जुलाई की पहली तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेज़ी राज में गुलामों को दंड देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के

अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही।

इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी राजग सरकार ने ही करके दिखाया है। अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। आज जब देश, अलग-अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पा रहा है, तब ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और ये स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है।

आज के समय में एआई समेत टेक्नॉलॉजी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की है। पिछले 10 वर्षों में जो सुधार हुए हैं, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, उससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं।

हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा न हो, ये हम सभी का दायित्व है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध, दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहां स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसलिए भरोसा है कि संसद के पल-पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगी। अभिभाषण में संसद में हंगामा पर चिंता व्यक्त की गई है।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम' से डिजिटल स्पेस और अधिक सुरक्षित होने वाला है। जम्मू-कश्मीर आरक्षण कानून से, वहां भी जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। परंतु अभी भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आर्मी व अन्य सशक्त पुलिस दल कार्यरत हैं। नीट परीक्षाओं की धांधली का क्या हुआ? नेशनल टेस्ट अथॉरिटी की निष्पक्षता पर अंकुश लग गया है। कोई भी राष्ट्र, तेज़ गति से तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह पुरानी चुनौतियों को परास्त करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य- निर्माण में लगाए। नीति आयोग के अनुसार, सरकार के एक दशक के कार्यकाल में, करीब 25 करोड़ देशवासी ग़रीबी रेखा से बाहर निकले हैं। मानव केंद्रित विकास पर बल देना चाहिए है। हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। यही सामाजिक न्याय की हमारी अवधारणा है। संविधान के हर अनुच्छेद का संदेश भी यही है।

हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें 'समानो मंत्रः समितिः समानी' की प्रेरणा दी है। अर्थात, हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें। यही इस संसद की मूल भावना है। हम जब 2047 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे, तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, संकल्पों में जो निष्ठा है, ये इस बात का प्रमाण हैं कि आने वाला दौर भारत का है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अभिभाषण के अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सबको साथ लेकर चलेगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

महापुरुष इस दुनिया से जाने पर ऐसी ज्योति छोड़ जाते हैं, जो उनके दुनिया से जाने के बाद भी कई युगों तक जगमगाती रहती है।

– लांगफेलो

लगता नहीं कुछ बदला

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

यह वही मंत्रिमंडल है, इसमें वही मंत्री हैं, वही-वही मंत्रालय संभाल रहे प्रमुख मंत्री हैं, वही अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री के वही प्रधान सचिव हैं, वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, खुफिया ब्यूरो के वही प्रमुख हैं, इसमें वही सरकारी विधि अधिकारी और बाकी बहुत सारे लोग हैं।

मा ननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपानीत सरकार ने 9 जून, 2024 को शपथ ली। इसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। मोदी को तेदेपा और जद (एकी) नेताओं के साथ मुख्य मंच साझा करना पड़ा और उन्हें तथा अन्य सहयोगियों को विभाग आबंटित करने पड़े। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में उन्हें पंचायत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सरकार के मुखिया के रूप में अपने बाईस वर्षों में मोदी के लिए ये दोनों ही अनुभव असामान्य थे।

कई झटके

सरकार बनने के बाद बीस दिनों के भीतर उसे कई झटके लगे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ध्वस्त हो गई और इसकी आग ने लाखों छात्रों की आकांक्षाओं को जलाकर राख कर दिया। जलपाईगुड़ी में एक भयानक रेल हादसा हुआ। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहे। टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 39, 41 और 43 फीसद की वृद्धि हुई। सेंसेक्स और निफ्टी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए, जबकि डालर-रुपया विनिमय दर ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई। राजमार्गों पर टोल टैक्स में 15 फीसद की वृद्धि की गई। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने स्पष्ट रूप से भर्त्सना करते हुए उन लोगों को फटकार लगाई जिन्होंने 'अहंकार' प्रदर्शित किया; भाजपा के नेतृत्व ने घबराहट में फैसला किया कि दिलेरी ही बेहतर अक्लमंदी है। भाजपा की कई राज्य इकाइयों में स्थानीय विद्रोह भड़क उठे।

संसद के पहले सत्र में, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और राष्ट्रपति के अभिभाषण को छोड़कर, कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं हुआ। मगर नियमित कामकाज में भी विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। परंपरा के अनुसार, निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करने के लिए ऐसे संसद सदस्य को 'प्रोटेम स्पीकर' नामित किया जाता है, जो सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए चुना गया हो। वह व्यक्ति, निर्विवाद रूप से, कांग्रेस के केरल से निर्वाचित के. सुरेश हो सकते थे, जो एक बार के व्यवधान को छोड़ कर आठवीं बार सांसद चुने गए हैं। मगर, सरकार ने ओड़ीशा से भाजपा के निर्वाचित सदस्य बी महताब को इस पद के लिए नामित किया, जबकि वे केवल सात बार निर्वाचित हुए हैं (छह बार बीजद के टिकट पर और, पार्टी छोड़ने के बाद, सातवीं बार भाजपा के टिकट पर)।

भाजपा ने इस अनावश्यक विवाद को क्यों जन्म दिया? इसके संभावित उत्तर हैं : भाजपा यह संकेत देना चाहती थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उसके सर्वोच्च नेता के कामकाज के तरीके पर कोई असर नहीं पड़ा है, यानी, 'यही मेरा मार्ग या राजमार्ग है'। इसका एक दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि विवादों में घिरे संसदीय मामलों के नए मंत्री के रिजीजू अपने आगमन का संकेत देना चाहते थे। सबसे उचित उत्तर यह है कि महताब का नामांकन उनके बीजद से भाजपा में शामिल होने और ज्यादा से ज्यादा सांसदों को भाजपा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार था।

बासी आश्वासन

हालांकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव एक खटास भरे नोट पर संपन्न हुआ, लेकिन शेष सत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मगर माननीय अध्यक्ष ने उस समय और कड़वाहट बढ़ा दी, जब उन्होंने उनचास वर्ष पहले (हां, उनचास वर्ष, पचास नहीं) आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया! इसके बाद, संसद 1947 में कश्मीर पर आक्रमण के लिए पाकिस्तान, 1962 में युद्ध के लिए चीन और 1971 में भारत को डराने के वास्ते विमानवाहक पोत भेजने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा करके इतिहास के अन्य पाठ पढ़ा सकती है। प्रस्ताव एक अनुचित उकसावे वाला था।

दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण गलत शुरुआत के बाद शिष्टाचार बहाल करने का एक अवसर हो सकता था, लेकिन वह अवसर भी चूक गया। अभिभाषण में लोकसभा की बदली हुई संरचना को रेखांकित किया जाना चाहिए था, यह तथ्य स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि अग्रणी पार्टी (भाजपा) बहुमत से 32 सीट से पीछे है, कि प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार के प्रमुख हैं और दस साल बाद, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। मगर अफसोस कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बदली परिस्थितियों का कोई संदर्भ नहीं था।

यह अभिभाषण भाजपा द्वारा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान किए गए दावों की विरुदावली भर था। इन दावों को अधिकांश लोग खारिज कर चुके हैं। नई सरकार भाजपा की नहीं, बल्कि गठबंधन की सरकार है। भाजपा ने इस कड़वे-मीठे तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रपति ने भी उसी दृष्टिकोण को दोहराया। 'गठबंधन' शब्द अभिभाषण में नहीं आया। इसके अलावा अन्य शब्द, जो इस अभिभाषण में गायब रहे, पर उनकी गूंज स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती रही, उनमें 'आम सहमति', 'मुद्रास्फीति' और 'संसदीय समिति' जैसे शब्द शामिल थे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का संदर्भ तो था, मगर अन्य सभी- विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों- को 'सामाजिक और धार्मिक समूहों' के दायरे में रखा गया था। मणिपुर की त्रासदी का कोई जिक्र नहीं था। एक छोटी-सी दया के रूप में भी 'अग्निवीर' या 'समान नागरिक संहिता' का कोई संदर्भ नहीं था। अंत में, भारत अब 'विश्व गुरु' नहीं रहा, वह 'विश्व बंधु' बनकर संतुष्ट है!

एकरूपता का आधिक्य

जाहिर है, भाजपा के विचार में, कुछ भी नहीं बदला है, यहां तक कि लोगों का मिजाज भी नहीं।

इसलिए, यह वही मंत्रिमंडल है, इसमें वही मंत्री हैं, वही-वही मंत्रालय संभाल रहे प्रमुख मंत्री हैं, वही अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री के वही प्रधान सचिव हैं, वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, खुफिया ब्यूरो के वही प्रमुख हैं, इसमें वही सरकारी विधि अधिकारी और बाकी बहुत सारे लोग हैं।

इसके अलावा, मुझे बताया गया है कि सोशल मीडिया उन्हीं 'भाड़े के ट्रोल' से भरा पड़ा है, जो अर्ध-शिक्षित, ध्यान भटकाने वाले, गंदगी के विज्ञान में पारंगत और स्पष्ट रूप से हारे हुए हैं। मुझे डर है कि यह इस बात का निर्णायक सबूत है कि लोगों के फैसले के बावजूद कुछ भी नहीं बदला है!

बजट की भागमभाग में, सबसे अधिक बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को लेकर लोगों की चिंताएं बनी हुई हैं। 'सीएसडीएस' के मतदान बाद सर्वेक्षण (25 जून, 2024, द हिंदू) के अनुसार, 'मूल्य वृद्धि/ मुद्रास्फीति' और 'बढ़ती बेरोजगारी' को भाजपा सरकार के सबसे 'अलोकप्रिय' कार्यों के रूप में क्रमशः 29 फीसद और 27 फीसद लोगों ने चिह्नित किया। इन दो प्रमुख चिंताओं के संदर्भ में देखें तो, मंत्रिमंडल के गठन और राष्ट्रपति के अभिभाषण ने लोगों को निराश किया है। क्या जुलाई में आने वाला 2024-25 का बजट मोदी सरकार को कुछ जगाएगा? संसदीय शिष्टाचार का तकाजा है कि फिलहाल हम अपना दिल थाम कर बैठें।

बहस के मुद्दे

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री की जवाबदेही नहीं बनती है संसद में? खासतौर पर तब जब उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है! जब क्रोधित विद्यार्थी उनके दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, तब उन्होंने स्वीकार की अपनी जिम्मेवारी। गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए को ही हटा कर किसी दूसरी संस्था द्वारा परीक्षाएं करानी चाहिए।

मैं अगर उन नौजवानों में से होती, जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है परीक्षाओं को लेकर तो नई लोकसभा के इस पहले सत्र को देख कर बहुत मायूस होती। उनमें से नहीं हूं, लेकिन फिर भी मायूस हुई लोकसभा में पक्ष-विपक्ष की गतिविधियों को देख कर। समझ में नहीं आता कि जो समस्या इन दिनों आपातकालीन रुख ले चुकी है, उसको नई लोकसभा में हमारे नव-निर्वाचित सांसदों ने क्यों सबसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। सोचा था मैंने कि विपक्ष में नई ताकत आने के बाद वे पहले दिन ही पहुंचते काले झंडे हाथों में लिए इस मांग को लेकर कि चूंकि देश के लाखों युवाओं के सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए इस पर पहले विशेष बहस होनी चाहिए। इसके बदले विपक्ष के नए सांसद दिखे उसी जगह जहां अक्सर दिखते हैं हर संसद सत्र में, यानी लोकसभा के अंदर नहीं, बल्कि लोकसभा के बाहर अपने हाथों में संविधान को लिए हुए। किस वास्ते? क्या उनको इस बार लोकसभा में ज्यादा सीटें मिलीं, इसके बावजूद वही करने के लिए जो पिछले दशक से करते आए हैं? विरोध प्रदर्शन अगर करते परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर तो भी कुछ अच्छा करते, लेकिन संविधान को क्या उन बच्चों से ज्यादा खतरा है, जिनके सारे सपने चूर-चूर हो गए हैं? मेरी नजर में तो नहीं।

लोकसभा के अंदर पहुंचे तो कुछ क्षणों के लिए लगा कि इस बार संसद ठीक से चलने वाला है। जब ओम बिरला दोबारा अध्यक्ष चुने गए तो राहुल गांधी ने बड़ी तमीज से उनको बधाई दी और आश्वासन दिया कि उनका इरादा है संसद को ठीक से चलने में पूरी सहायता करने का, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार वे निष्पक्षता से अपना काम करें। हम भी यहां हैं जनता की आवाज को उठाने के लिए, कहा लोकसभा के नए विपक्ष के नेता ने। जब इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया तो मुझे लगा कि वास्तव में संसद के अंदर कुछ गंभीरता से बहस होने वाली है देश के असली मुद्दों पर।

ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। शायद ऐसा होने वाला भी नहीं है। सारी तमीज, सारी अच्छी बातें हवा में उड़ गईं जब ओम बिरला ने इंदिरा गांधी के उस आपातकाल को याद करके प्रस्ताव पारित करना चाहा। आपातकाल की उनचासवीं बरसी थी उस दिन, इसलिए क्यों न याद किया जाए उस काले दौर को जब एक प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को ताक पर रख कर अपने आपको तानाशाह बना दिया था? मगर कांग्रेस के सांसदों को आपातकाल को याद करना पसंद नहीं है, सो खूब शोर मचाने लगे उस समय भी जब दो मिनट के मौन में उनको याद किया गया, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ अपनी जान पर खेल कर आवाज उठाई थी।

यह सिलसिला समाप्त हुआ तो विपक्ष की तरफ से मांग उठी कि 'सेंगोल' को संसद से बाहर निकालना चाहिए। उसकी जगह किसी संग्रहालय में होनी चाहिए, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं, क्योंकि वह याद दिलाता है राजा-महाराजाओं के जमाने की। हो सकता है उनकी यह बात ठीक है, लेकिन क्या 'सेंगोल' पर विवाद करने का यह समय है जब लाखों नौजवान भारतीय अपनी किस्मत पर रो रहे हैं? राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रश्न पत्र बाहर आने की बात की अपने भाषण में, लेकिन यह काफी नहीं था। विपक्ष की मांग वाजिब थी कि राष्ट्रपति के भाषण पर बाद में चर्चा हो सकती है, पहले विशेष बहस करने की जरूरत है परीक्षाओं में घोटाले की। इस बार शोर सत्तापक्ष से हुआ।

सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री की जवाबदेही नहीं बनती है संसद में? खासतौर पर तब जब उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है! जब क्रोधित विद्यार्थी उनके दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, तब उन्होंने स्वीकार की अपनी जिम्मेवारी। अब हम जान गए हैं कि गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए को ही हटा कर किसी दूसरी संस्था द्वारा परीक्षाएं करानी चाहिए। अब मालूम यह भी हुआ है कि इस बड़े घोटाले में ऊपर से नीचे तक धोखेबाज शामिल थे, इस हद तक कि उनका जाल पूरे देश में छाया हुआ है। इसमें अध्यापक, कोचिंग केंद्र, सरकारी अफसर, राजनेता और हर तरह के चोर शामिल हैं। जवाबदेही बनती है मोदी सरकार की। जवाब मांगना संसद में विपक्ष का काम है। लोकसभा अध्यक्ष को बहस की इजाजत देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों?

संविधान को कोई खतरा नहीं है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का '400 पार' वाला सपना अगर पूरा हुआ होता, तब भी संविधान को कूड़ेदान में फेंक कर नया संविधान लाना उनके लिए आसान नहीं होता। संविधान को एक ही बार असली खतरा था और वह था इंदिरा गांधी के आपातकाल में जब संविधान की प्रस्तावना को बदल कर उसमें 'सेक्युलर, समाजवादी' शब्द डाल दिए गए थे। इतना ही नहीं, इंदिराजी ने संविधान में संशोधन लाकर यह भी प्रावधान डाल दिया था कि लोकसभा में पारित कानूनों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

कहने का मतलब है कि अगर विपक्ष को इतनी चिंता है संविधान के बदले जाने की तो आपातकाल पर बहस करवाएं और खुलकर बताएं देश को कि क्या उनकी नजरों में आपातकाल लगा कर इंदिराजी ने देश के साथ अच्छा किया था या बुरा। लेकिन यह बहस बाद में भी हो सकती है। नई लोकसभा के इस पहले सत्र में सबसे बड़ी जरूरत है परीक्षाओं में घोटाले पर बहस करने की। भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद होता रहा तो देश का भविष्य भी बर्बाद होगा।

विविधता की राजनीतिक संस्कृति

चुनावी सरगर्मी में विश्लेषण मत विभाजन और सामाजिक समीकरणों तक सिमट कर रह जाता है। तब के लिए यह यथेष्ट है। पर जिस समाज में जनतांत्रिक मूल्यों को लेकर उठापटक चल रही हो और परिपक्व जनतंत्र तक पहुंचने में अनेक बाधाएं साफ-साफ दिखाई पड़ रही हों, उसमें चिंतन का विस्तार होना जरूरी है। चुनाव के बाद यह सबसे उपयुक्त समय है। इसमें अल्पता या न्यूनता का कारण भारत के बुद्धिजीवियों और उनके मंचों पर राजनीतिक-वैचारिक ध्रुवीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव है, जिससे चिंतन-विश्लेषण की सीमा तय हो जाती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच की अवधि बिना किसी निर्णायक योगदान के बीत जाती है। राजनीतिक दल अपना काम बखूबी करते हैं। यह वोटो की संख्या पर केंद्रित होता है। यही रचनात्मक और विध्वंसात्मक कार्यों के लिए उत्प्रेरक की तरह होता है। पर 'थिंक टैंक' और अकादमिक जगत से जुड़े लोग 'न तीन के न तेरह के' बनकर रह जाते हैं। आलोचना स्वयं में निदान नहीं होती है, पर उसमें समाधान की जमीन अवश्य तलाशी जा सकती है।

भारतीय जनतंत्र की स्थिति दुनिया के अन्य हिस्सों, चाहे यूरोप हो या अफ्रीका, भिन्न है। इसका कारण विविधता आधारित जीवन मूल्य और दर्शन है। जिस आयाम को देखें, वहीं अनेक परत और प्रवृत्तियां मिल जाती हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चेतना का परिणाम राजनीति में स्वाभाविक रूप से प्रतिबिंबित होता है। उस चेतना की बहुलता और सामाजिक वर्गों की विपुलता को कैसे जनतांत्रिक धारा में परिवर्तित किया जाए, यह कठिन चुनौती होती है। इसमें उन ताकतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, जो राजनीतिक प्रक्रिया में होते हैं, पर चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं। इसका उदाहरण जयप्रकाश-विनोबा के व्यक्तित्व से समझा जा सकता है। देश की नीतियों, राजनीतिक गतिविधियों आदि से ये विरक्त नहीं थे, पर चुनावी अंकगणित और समीकरणों से दूर थे। उनकी वैचारिक भूमि भी तटस्थ या उदासीन नहीं थी, पर वह उनकी निष्पक्ष भूमिका और राजनीतिक चेतना को सुदृढ़ करने में व्यवधान नहीं बनता था। समाज में उनकी विश्वसनीयता थी। राज्य के संसाधनों पर उनकी निर्भरता नहीं थी। यह आसान नहीं होता है। उन जैसे लोगों ने समाज के स्रोतों से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इसलिए उनकी आंखों में पानी भी था और व्यक्तित्व में फौलादी संघर्ष की क्षमता भी। इसीलिए सुदूर गांवों को चुनकर वे जनतांत्रिक प्रतिमानों को स्थापित करते रहे। प्रयोगशाला हमेशा छोटी होती है, प्रयोग का असर बड़ा और व्यापक होता है।

पचास-साठ के दशक में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो पीढ़ी आई, उनमें आदर्श के सपने और व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता बनाए रखने की आकांक्षा पर्याप्त मात्रा में थी। आज शहर केंद्रित बुद्धिजीवी स्वयं चौहद्दी लांघने की स्थिति में नहीं हैं। फिर तो 'चलता है' संस्कृति ही राजनीति की राह बनाती रहेगी।

प्रथम आमचुनाव मार्गदर्शिका है। तिरपन दल चुनाव मैदान में थे। अधिकांश वैचारिक पृष्ठभूमि वाले थे। इसमें जमींदार पार्टी से लेकर हिस्टोरिकल रिसर्च (ऐतिहासिक शोध) जैसी पार्टियां भी थी। अगले चुनाव (1962) में सत्ताईस दल थे तो तीसरे आम चुनाव (1967) में संख्या पंद्रह रह गई। भारत में वैचारिक बुनियाद के आधार पर विमर्श और राजनीति का यह स्वर्णिम काल था। भारतीय जनसंघ उस दौर में कांग्रेस, कम्युनिस्ट-सोशलिस्ट समूहों के समांतर एक वैचारिक-राजनीतिक ताकत के रूप में विकसित हुआ। उनके नेता जितने राजनीति में डूबे थे, उतने ही सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नों पर सजग थे। वैचारिक विरोधों में पल रहे वे व्यक्तित्वों में समानार्थक स्वरूप प्रस्तुत करते थे। आचार्य जेबी कृपलानी, राममनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और संपूर्णानंद एक मंच पर नहीं थे, पर इनकी सार्वजनिक जीवन के योद्धा की छवि थी। भारतीय समाज कैसा हो, इसे ये संबोधित करते थे। इसने सामाजिक विभाजन को आर्थिक-सांस्कृतिक धारा में मिलाने का काम किया।

भारत की विरासत से जो बात उभरकर आती है, वह है परिवर्तन, बौद्धिकता और चेतना सृजन का केंद्र कभी भी शहर या महानगर नहीं रहा है, न ही बड़े नाम वाले लोग रहे हैं। इसका केंद्र अनाम स्थान रहा जो अपने सामाजिक-राजनीतिक या बौद्धिक योगदान के बाद ऐतिहासिक बन गया। नालंदा, नादिया, वर्धा, पवनार, कौआकोल कुछ ऐसे ही नाम हैं।

संदर्भ

राकेश सिन्हा

भारतीय जनतंत्र की स्थिति दुनिया के अन्य हिस्सों, चाहे यूरोप हो या अफ्रीका, भिन्न है। इसका कारण विविधता आधारित जीवन मूल्य और दर्शन है। सामाजिक-सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चेतना का परिणाम राजनीति में स्वाभाविक रूप से प्रतिबिंबित होता है। उस चेतना की बहुलता और सामाजिक वर्गों की विपुलता को कैसे जनतांत्रिक धारा में परिवर्तित किया जाए, यह कठिन चुनौती होती है।

क्या हमारी विविधता जनतंत्र पर बोझ बन जाएगी? यह प्रश्न लाजिमी है। राजनीति विचारों, व्यक्तित्वों और व्यवहारों से पहचानी जाती है। जितनी समग्रता और सर्वसमावेशी क्षमता उसमें होती है वह विविधताओं को पिरो लेती है, कटुता या प्रतिस्पर्धा नहीं बनने देती है। जब बड़ी क्षमता और अवसर वाले लोग, जिन्हें 'छोटी जगह' और 'छोटे लोग' कहा जाता है, के साथ संवाद और सत्संग करते हैं, तो वही 'छोटे लोग' और 'छोटे स्थान' विचारों और राजनीति की मरुभूमि से हरितभूमि बन जाते है। वे ही परिवर्तन के सारथी बनते हैं। भारतीय जनतंत्र ने अपनी प्रयोगधर्मिता से यही सिखाया और दिखाया है। पश्चिम मे बैठे कोई धनपति भले सोचते हों कि धन जनतंत्र की नियति तय करता है, पर भारत इसे सदैव नकारता रहा है। वर्तमान पीढ़ी को निष्क्रियता से निकलकर सामाजिक-आर्थिक जमीन को समृद्ध करना होगा। अन्यथा जनतंत्र बेलगाम, बेआकार और व्यथित बना रहेगा।

नया संविधानवाद

बाखबर

सुधीश पचौरी

बहुत दिन बाद विपक्ष को अपना नेता मिला। फिर विपक्ष का नेता चुने जाने के बाद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के साथ जाकर लोकसभा अध्यक्ष से हाथ मिलाकर उनका स्वागत करने के दृश्य दो मिनट की 'सुंदर सहमति' के दृश्य की तरह दिखे।

लगता है कि दुर्भाग्य सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा। कोई न कोई आफत आती ही रहती है! एक ओर 'नीट पेपर लीक' और 'नेट पेपर लीक' है, दूसरी ओर राम मंदिर की छत तक में 'लीक' की खबर है। उधर दिल्ली के हवाईअड्डे 'टी-1' की छत के एक हिस्से के गिरने की खबर है। इधर ऐसे दृश्य, उधर विपक्ष आक्रामक! प्रवक्ता कहिन कि ये कैसी सरकार है जो कोई भी काम कायदे से नहीं कर सकती! हर चैनल पर पर्चाफोड़ की चर्चा। आंकड़ेबाज बताते कि अब तक साठ से अधिक पर्चाफोड़ की घटनाएं हुईं।

अपेक्षाकृत मजबूत विपक्ष 'फार्म' में कि शिक्षामंत्री शपथ लिए तो करने लगा मांग कि शिक्षामंत्री इस्तीफा दो। 'लीक प्रकरण' के साथ-साथ कुछ बहसें 'एनसीईआरटी' की नई किताबों पर भी रहीं। एनसीईआरटी का पक्ष बताता रहा कि 'बाबरी मस्जिद' के जिक्र की जगह 'तीन गुंबदों वाला ढांचा' लिखा गया है और दंगों में हिंसा के विवरण हटा दिए गए हैं, ताकि बच्चों पर उस हिंसा का असर न हो, जबकि आलोचक पक्ष कहता रहा कि इतिहास को 'सेनिटाइज' करना ठीक नहीं। जो हुआ है, उसे न बताना और भी गलत बात है।

लोकसभा में 'प्रोटेम अध्यक्ष' पर पंगा रहा। सत्ता पक्ष ने अपना 'नामित' दे दिया तो विपक्ष ने भी अपना पत्ता खेल दिया। फिर भी सत्ता पक्ष के 'नामित' ही 'प्रोटेम अध्यक्ष' बने! इसी तरह लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर भी पंगा रहा। एक संविधानविद् कहिन कि लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाता है, फिर भी विपक्ष ने चुनाव पर जोर दिया, लेकिन आधे दिल से। जब 'प्रोटेम अध्यक्ष' ने 'ध्वनिमत' से सत्ता दल के नामित ओम बिरला को विजयी घोषित कर दिया तब विपक्ष ने सदन में 'मत विभाजन' की मांग नहीं की।

इस बीच राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुने गए! बहुत दिन बाद विपक्ष को अपना नेता मिला। फिर विपक्ष का नेता चुने जाने के बाद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के साथ जाकर लोकसभा अध्यक्ष से हाथ मिलाकर उनका स्वागत करने के दृश्य दो मिनट की 'सुंदर सहमति' के दृश्य की तरह दिखे।

प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में लोकसभा अध्यक्ष महोदय की पिछले पांच बरस की उपलब्धियां गिनाईं और आगे की भूमिका को रेखांकित किया तो विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को संविधान के अनुसार कार्य करने को कहा और यह भी चेताया कि जरा-सी बात पर सांसदों के निलंबन की कार्रवाई से परहेज करना चाहिए। और सदैव 'मुदित मुख' ओम बिरला सारी आलोचना और सलाहों पर मुस्कुराते रहे।

फिर आए विपक्षी सांसदों द्वारा संविधान के 'लाल कवर' के 'पाकेट संस्करण' को हाथ में लेकर 'जय संविधान' कह कर शपथ लेने के दृश्य! इसके बाद लोकसभाध्यक्ष महोदय का आपातकाल की निंदा करने वाला प्रस्ताव आया तो कुछ हंगामा हुआ, लेकिन कुछ शांति भी रही। विपक्ष के एक हिस्से में आपातकाल की आलोचना प्रस्ताव पर 'एतराज' दिखा।

फिर आया एक सपा सांसद का 'सेंगोल' पर सीधा हमला कि ये राजतंत्र का प्रतीक है, जनतंत्र के मंदिर में इसका क्या काम... इसकी जगह संविधान की बड़ी-सी प्रति रखी जाए। जवाब में सत्ता प्रवक्ता 'सेंगोल' के बचाव में ही लगे रहे। वे बताते रहे कि यह राजतंत्र का प्रतीक न होकर 'इंडिक सभ्यता' के 'न्याय' का प्रतीक है, जबकि विपक्ष कहता रहा, यह तानाशाही का प्रतीक है।

विपक्ष के एक नेता ने तो चुटकी भी ली कि जब लगा था तो प्रधानमंत्री ने प्रणाम भी किया था, लेकिन इस बार भूल गए। उनके सांसद शायद यही याद दिलाना चाहते हैं। विपक्ष की इस 'कूट चातुरी' का जवाब भाजपा प्रवक्ताओं के पास नहीं दिखा। वे वही पुराने तर्क देते रहे कि 'सेंगोल' अगर राजतंत्र का प्रतीक है तो अशोक का 'धम्मचक्र' किसका प्रतीक है? क्या उसे भी हटाएं? भाजपा प्रवक्ता के ऐसे मासूम तर्क सुनकर एक पत्रकार ने कहा कि विपक्ष के लिए 'सेंगोल' तो बहाना है, असली इरादा भाजपा की छवि को 'संविधान विरोधी' बताना है।

बहरहाल, नई संसद के सांसदों की शपथ के दृश्यों ने भी कुछ 'नई जनतांत्रिक ऊंचाइयां' छुईं। एक सांसद ने शपथ के बाद कह दिया 'जय फिलिस्तीन' तो सत्ता पक्ष से आई- 'हाय-हाय'। जब एक और सांसद जी ने शपथ के बाद कह दिया कि 'जय हिंदूराष्ट्र' तो विपक्ष से आई 'हाय-हाय'। फिर मांग हुई कि 'जय फिलिस्तीन' को रिकार्ड से निकाला जाए और सांसद के खिलाफ कार्रवाई हो। बहसों में सत्ता प्रवक्ता बार-बार कहते रहे कि आप फिलिस्तीन के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन संसद में शपथ लेते वक्त किसी दूसरे देश का 'महिमामंडन' नहीं कर सकते।

शुक्रवार के दिन विपक्ष के नेता ने चाहा कि संसद पहले 'नीट घोटाला' पर चर्चा करे, लेकिन जब अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण एजंडे पर है तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और फिर सत्र को स्थगित कर दिया गया।

www.readwhere.com

इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन फिर भी इसमें रवानगी तो होती ही है।

- मार्क ट्वेन।

नई जमीन

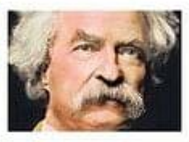

मूलत: 'नालंद' और प्रचलित 'नालंदा' की गौरव गाथा ऐसे ही अमिट नहीं बनी, उसके पीछे उसे विद्या का केंद्र बनाने की अद्भुत इच्छा शामिल थी। इतिहास लेखन के लिए प्राय: द्वितीयक स्रोतों का सहारा लेकर और प्राथमिक स्रोतों को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने से इतिहास और वर्तमान, दोनों के साथ अन्याय होता है।

फिर नालंद की ओर

इसकी चहारदीवारी के प्रधान द्वारों के सामने पंडितों की नियुक्ति की गई थी। उन्हें द्वार पंडित कहते थे। वे विविध विषयों के विशेषज्ञ थे। प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों की योग्यता तथा प्रतिभा की परीक्षा लेने के लिए वे कड़े प्रश्न पूछते थे। समुचित उत्तर देने के बाद ही उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश की आज्ञा मिलती थी।

डॉ. ज्ञानेंद्र नारायण राय
शताब्दी फेलो, भारत अध्ययन केंद्र, बीएचयू

नालंद के विद्या केंद्र को देखते हुए इसे विश्वविद्यालय नगर की संज्ञा प्रदान करें, तो संभवत: इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ह्वेनसांग के विवरण में इसके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में एक उल्लेख मिलता है, जो बौद्ध परंपराओं पर आधारित है। इसके अनुसार, गौतम बुद्ध अपने एक पूर्व जन्म में इस क्षेत्र के सम्राट थे। उनकी ख्याति चतुर्दिक अथक दानी (न-अलम-दा, अर्थात दान देने से न संतुष्ट होने वाले) के रूप में थी। इस कारण यह स्थान नालंद के नाम से प्रख्यात हुआ। मज्झिम निकाय (1.377) के अनुसार, यह राजगृह के पास एक छोटा-सा ग्राम था। जैन ग्रंथों में यह राजगृह के सीमांत क्षेत्र के रूप में वर्णित है। यहां पर महावीर ने 14 वर्ष व्यतीत किए थे। अशोक के काल के पूर्व यहां पर सारिपुत्र की स्मृति में एक स्तूप बनवाया गया था।

फाह्यान के समय तक विद्या के केंद्र के रूप में नालंद की कोई ख्याति नहीं थी। फाह्यान के लगभग तीन शताब्दियों के बाद जब ह्वेनसांग नालंद आया, उस समय यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का विद्या केंद्र था। ह्वेन सांग के अनुसार, इस विद्या केंद्र की स्थापना शक्रादित्य नामक नरेश द्वारा की गई थी। 'शक्र' शब्द इंद्र का पर्याय है तथा मुद्रा साक्ष्य के अनुसार महेंद्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम से उसका एका संभाव्य है। इस आधार पर नालंद विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया जाना स्थापित होता है। शक्रादित्य के बाद बुद्धगुप्त, तथागतगुप्त, बालादित्य वज्र तथा हर्षादि ने नालंद में भवन आदि का निर्माण करवाया तथा विद्या केंद्र को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। हर्ष ने यहां पर पीतल का एक विहार तथा उसके चारों ओर एक दीवार बनवाने के साथ ही एक संघाराम का भी निर्माण किया, जिसमें 40 भिक्षुओं के भोजन की व्यवस्था की गई थी। ह्वेनसांग लिखता है कि उसके आगमन पर शक्रादित्य द्वारा निर्मित विहार जीर्णावस्था को प्राप्त हो चुका था। लेकिन नालंद महाविहार के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े हमें कई ताम्रलेख प्राप्त हैं, जिनमें से कुछ का प्रकाशन हीरानंद आदि विद्वानों ने *एपीग्राफिया इंडिका* के वॉल्यूम 20 और 21 में *नालंद ऐंड इट्स एपीग्रैफिक मैटेरियल्स* शीर्षक से प्रकाशित किया है। उनमें से एक के अनुसार, वहां कई विहार एक ही पंक्ति में थे, जिनके शिखर गगनचुंबी थे।

यस्याम्बुधरावलेहिशिखरश्रेणी विहारावली।
मालेवोर्ध्वविराजिनी विरचिता धात्रा मनोज्ञा भुव:।।

इत्सिंग भी पुष्टि करता है कि वहां के भवन बादलों को छूते हुए से लगते थे। नालंद के विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन, वस्त्र के साथ शिक्षा दी जाती थी। ह्वेनसांग इस महाविहार को भारतीय राजाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि इसे दो सौ गांव आर्थिक सहायता के लिए प्रदान किए गए थे। विश्वविद्यालय की अपनी निजी मुद्रा थी, जिस पर 'श्री नालंदा महाविहार-आर्य-भिक्षु-संघस्य' लेख उत्कीर्ण है। इस विश्वविद्यालय से देश-विदेश के कई अन्य विद्यालय भी संबद्ध थे और उनकी अलग-अलग मुद्राएं थीं।

हर्ष के बाद भी कतिपय भारतीय नरेशों ने इस विद्या केंद्र को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। यशोवर्मदेव नाम के सम्राट के एक मंत्री ने नालंद को इतना अधिक दान दिया था, जिससे इसके भिक्षुओं को कई वर्षों तक प्रतिदिन भोजन दिया जा सकता था। बंगाल के पाल नरेशों ने भी नालंद के इस विद्या केंद्र में रुचि ली थी। देवपाल के एक शिलालेख में विदेशी राजा द्वारा अपने राजदूत के माध्यम से इस विश्वविद्यालय के लिए अनुदान का संदर्भ प्राप्त होता है। राजाओं के अनुदान तथा जनसहभागिता के साथ-साथ यह विश्वविद्यालय खेती एवं गो-पालन के द्वारा स्वयं भी अन्न तथा दूध का उत्पादन करता था।

इस विद्या केंद्र को लब्धप्रतिष्ठित विद्वान सुशोभित करते थे। ह्वेनसांग ने अपने समकालीन नालंद के आचार्यों का उल्लेख किया है। इस समय शीलभद्र इस केंद्र के कुलपति थे, जो इस चीनी यात्री के आचार्य रह चुके थे। ह्वेनसांग ने धर्मपाल नामक आचार्य का भी उल्लेख किया है, जो शीलभद्र के पहले नालंद के कुलपति रह चुके थे। उन्होंने आचार्य चंद्रगोमिन के व्याकरण पर संस्कृत में 'वर्ण-सुत्र-वृत्ति-नाम' नामक एक व्याकरण टीका लिखी थी। ह्वेनसांग ने अन्य आचार्यों का भी उल्लेख किया है, जिनमें चंद्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र तथा ज्ञानचंद्र प्रमुख हैं। शिक्षकों में शीलभद्र, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु और दिङ्नाग जैसे विद्वान आचार्य भी थे। राधाकुमुद मुखर्जी लिखते हैं कि यहां अध्ययन के विषय के दृष्टिकोण से उदारता प्रकट होती है। ब्राह्मण धर्म एवं बौद्ध धर्म के ग्रंथ, धार्मिक और आमुष्मिक विषय, कला व विज्ञान, शिल्प व उद्योग की शिक्षा की व्यवस्था थी। हेतुविद्या (तर्क), शब्द विद्या (व्याकरण), चिकित्सा विद्या (भैषज्य), सांख्य, योग, न्याय और सर्वास्तिवाद, माध्यमिक आदि बौद्ध दर्शनों की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध था।

ह्वेनसांग के वर्णन से लगता है कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना दुष्कर था। इसके प्रधान द्वारों के सामने पंडितों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें द्वार पंडित कहा जाता था। वे विविध विषयों के विशेषज्ञ हुआ करते थे। प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों की योग्यता की परीक्षा लेने के लिए वे दार्शनिक विषयों तथा जटिल समस्याओं पर कड़े प्रश्न पूछते थे। समुचित उत्तर देने के बाद ही उन्हें प्रवेश की आज्ञा मिलती थी। ह्वेनसांग लिखता है कि करीब बीस प्रतिशत विद्यार्थी ही बड़ी मुश्किल से सफल हो पाते थे। विदेशी छात्र बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियों को प्रस्तुत करने तथा ज्ञानोपार्जन में संलग्न रहते थे। अध्ययन के पश्चात ये विद्यार्थी स्वदेश जाकर नालंद की ख्याति को प्रसारित करते थे।

{ धूप आने दो

दुर्भाग्यवश इधर कुछ वर्षों से इस विद्या केंद्र के विध्वंस की घटना को ब्राह्मणों तथा बौद्धों के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाने लगा है। प्रो. डीएन झा के लेख 'प्राचीन बौद्ध स्थलों का विनाश' को साझा करते हुए कहा जा रहा है कि 'हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा लगाई गई आग में नालंदा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी इसके विनाश का श्रेय मामलूक कमांडर बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। हालांकि खिलजी ने पास के एक विहार को ध्वस्त किया था, लेकिन नालंदा नहीं गया था।' प्रोफेसर झा ने यह बात सबसे पहले 2006 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के अधिवेशन में ब्राह्मण-बौद्ध संघर्ष की चर्चा करते हुए कही थी। प्रो. झा द्वारा जिन संदर्भों का सहारा लिया गया है, उनकी समीक्षा आवश्यक है। पहला संदर्भ उन्होंने सुंपा खान पोयेसे पाल जोर की पुस्तक *पैग सैम जॉन जांग* से लिया है, जो नालंद की विनाशकारी घटना के लगभग 500 वर्ष बाद 1704-88 के बीच लिखी गई थी। दूसरा वह लिखते हैं कि 'एक तिब्बती परंपरा में कहा गया है कि 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा कर्ण ने मगध में कई बौद्ध मंदिरों व मठों को नष्ट किया था', और *पैग सैम जॉन जांग* में कुछ 'हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा नालंदा के पुस्तकालय को जलाने का उल्लेख है।'

विश्वविद्यालय की निजी मुद्रा

लेकिन सच्चाई यह है कि पहले संदर्भ के लिए प्रयुक्त अंश का प्रतिष्ठित बौद्ध विद्वान गेशे दोरजी दामदुल द्वारा अनुवाद किया गया। अनुवाद में कहा गया है कि 'नालंदा में राजा के एक मंत्री, काकुतसिता द्वारा एक मंदिर निर्माण के उत्सव के दौरान, कुछ शरारती नौसिखिए भिक्षुओं ने दो गैर-बौद्ध भिक्षुओं पर (बर्तन) धोने के पानी के छींटे डाले और दोनों को दरवाजे और दरवाजे की चौखट के बीच में दबा दिया। इससे क्रोधित होकर, एक (भिक्षु) जो उस भिक्षु का सेवक था, जिसने सूर्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 साल तक एक गहरे गड्ढे में बैठकर तपस्या की थी। सिद्धि प्राप्त करने के बाद, उसने अग्नि पूजा (हवन) की राख को 84 बौद्ध मंदिरों पर फेंक दिया। वे सब जल गए। विशेष रूप से, शास्त्रों को आश्रय देने वाले नालंदा के तीन धर्मगंजों में भी आग लग गई, तब रत्नाधाती मंदिर की नौवीं मंजिल पर रखे *गुह्यसमाज* और *प्रज्ञापारमिता* ग्रंथों के ऊपर से पानी की धाराएं नीचे चलीं, जिससे कई शास्त्र बच गए... अपने आप हुए बलिदान के कारण उन दोनों भिक्षुओं की मौत हो गई।'

दरअसल, प्रोफेसर झा ने जिस घटना के लिए लगभग 500 वर्ष बाद लिखी हुई पुस्तक का संदर्भ लिया है, उसमें एक काल्पनिक कथा को आधार बनाया गया है। जबकि नालंद विनाश की घटना के समकालीन मौलाना मिन्हाज-उद-दीन की लिखी हुई पुस्तक *तबकात-ए-नासिरी* के वॉल्यूम-1 (अंग्रेजी अनुवाद) के पृष्ठ संख्या 552 पर स्पष्ट उल्लेख है कि मुहम्मद बख्तियार खिलजी 200 घुड़सवार सैनिकों के साथ नालंदा में पहुंचा, ब्राह्मणों के सिर मुंडवाकर उन्हें मार डाला और विद्या स्थान, जिसे हिंदवी भाषा में विहार कहते हैं, नष्ट किया। इतने स्पष्ट और समकालीन प्रमाण को अनदेखा करते हुए वह इस घटना को नालंद का मानने से ही इन्कार कर देते हैं और इसे ओदंतपुरी की घटना बताते हैं, जबकि बिहार में ओदंतपुरी की कोई स्पष्ट मार्किंग ही नहीं हो सकी है। आखिर कोई भी मार्क्सवादी-तर्कवादी इतिहासकार अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए सिद्धि प्राप्ति, राख से अग्निकांड, किताबों से पानी बहने, स्वत: आत्मदाह जैसे चमत्कारों पर कैसे भरोसा कर सकता है?

19-20वीं सदी से लेकर आज तक के इतिहासकार, जिन्होंने प्राथमिक स्रोतों एवं पुरातात्विक सामग्री के आधार पर इतिहास लेखन किया है, नालंद के संदर्भ में एकमत हैं कि इसके विनाश का मुख्य कारण मोहम्मद बख्तियार खिलजी ही है। विंसेंट ए. स्मिथ ने समकालीन दस्तावेजों के हवाले से लिखा है कि कैसे खिलजी ने नालंद को जलाकर नष्ट कर दिया था और वहां के सभी ब्राह्मणों को सिर मुंडवाकर मार डाला। यही बात डॉ. बीआर आंबेडकर, प्रसिद्ध इतिहासकार विल डुरंट तथा हार्टमुट शार्फे भी कहते हैं। इतिहास लेखन के लिए प्राय: द्वितीयक स्रोतों का सहारा लेकर और प्राथमिक स्रोतों को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने से इतिहास और वर्तमान, दोनों के साथ अन्याय होता है।

इतिहास को इतिहास की तरह लें

प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्‌घाटन करते वक्त पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की याद दिलाते हुए कहा, 'नालंदा इस सत्य का उद्‌घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकतीं।' इस भाषण पर इतिहास को लेकर ही बहस छिड़ गई।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि न केवल नालंदा, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल स्थित कई विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट किया था। कुछ इतिहासकार इसके उलट दावा करते हैं कि नालंदा को आग के हवाले हिंदुओं ने ही किया। हालांकि इन विचारों का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। एक प्रमुख इतिहासकार रोमिला थापर ने भी एक जगह तुर्कों के ही आक्रमण के बाद से नालंदा के विनाश की बात प्रकारांतर से कही है।

इस संबंध में डॉ. भीमराव आंबेडकर लिखते हैं (अंबेडकर समग्र भाग 3; पृ. 232-33)-'मुसलमान आक्रमणकारियों ने नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दला, ओदंतपुरी आदि के बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। उन्होंने उन बौद्ध मठों को मटियामेट कर दिया, जिनसे देश भरा था। मुस्लिम आक्रमणकारियों की तलवार से बौद्ध पुरोहित वर्ग किस प्रकार नष्ट हो गया, यह स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने दर्ज किया है।...यह इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा किया गया बौद्ध पुरोहितों का कत्लेआम था। जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारी गई, क्योंकि पुरोहित वर्ग की हत्या करके इस्लाम ने बौद्ध धर्म की हत्या कर दी। यह भारत में बुद्ध के धर्म पर आई सबसे बड़ी आपदा थी।... बौद्ध धर्म की लौ जलाए रखने वाला कोई नहीं बचा।

विंसेंट स्मिथ कहते हैं (भारत का प्रारंभिक इतिहास (1924, पृष्ठ 419-420): 'बिहार के किले (नालंदा विश्वविद्यालय) पर केवल दो सौ घुड़सवारों के एक दल ने कब्जा कर लिया था। बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम इतना पूर्ण था कि जब विजेता ने मठों के पुस्तकालयों में पुस्तकों की सामग्री को समझाने में सक्षम किसी व्यक्ति की तलाश की, तो एक भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला, जो उन्हें पढ़ने में सक्षम हो। पुस्तकालय मे आग लगा दी गई।' जाहिर है, अब नालंदा के अतीत के नाम पर बेवजह वितंडा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है।

-प्रो. मक्खन लाल, इतिहासकार

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

विश्वकर्मा ने कहा, दक्षिणी समुद्र के तट से लगभग एक सौ योजन की दूरी पर त्रिकूट नामक एक पर्वत है। उस शिखर पर मैंने देवराज इंद्र के लिए स्वर्ण नगरी का निर्माण किया था। आप चाहें, तो वहां रह सकते हैं।

राक्षसों को कैसे मिली सोने की लंका

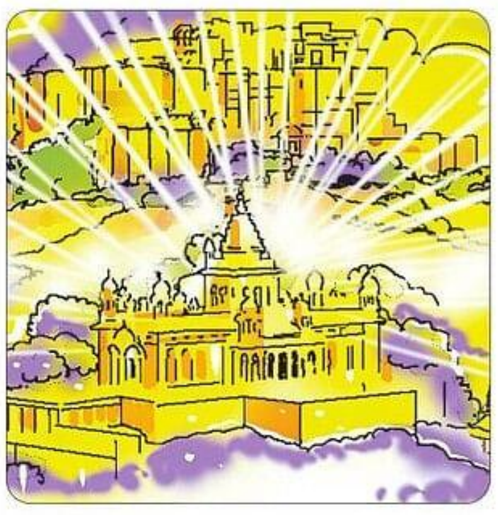

सृष्टि की संरचना के समय ब्रह्मा ने जलचर प्राणी उत्पन्न किए और उनसे कहा, 'जल, सृष्टि का सबसे उपयोगी तत्व है। इसकी पूजा और रक्षा, दोनों आवश्यक हैं। इसकी रक्षा करने वाले प्राणी 'रक्ष' तथा जल का यक्षण (पूजन) करने वाले प्राणी 'यक्ष' कहलाएंगे।' इस तरह रक्ष (राक्षस) एवं यक्ष जातियां अस्तित्व में आईं।

राक्षस जाति में हेति और प्रहेति नाम के दो भाई हुए। कुछ समय बाद प्रहेति ने संन्यास ले लिया, तो राक्षसों के नेतृत्व का भार हेति पर आ गया। हेति ने काल की बहन, भया से विवाह किया। उनका एक पुत्र हुआ–विद्युत्केश। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकटंकटा से हुआ।

सालकटंकटा कामी स्वभाव की थी और सदैव पति के साथ रति-क्रीड़ा में मग्न रहती थी। सालकटंकटा जब गर्भवती हुई, तो उसे चिंता सताने लगी कि संतान होने के बाद वह विद्युत्केश के साथ प्रेमालाप कैसे करेगी। कुछ दिन बाद सालकटंकटा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर विद्युत्केश तो प्रसन्न हुआ, किंतु सालकटंकटा को अपना ही पुत्र प्रेमालाप में बाधा लगने लगा। आखिर एक दिन उसने खीजकर कहा, 'मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती...मैं इसे त्याग रही हूं।'

विद्युत्केश ने पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर, सालकटंकटा के कहने पर विद्युत्केश ने अपने नवजात पुत्र को एक पर्वत-शिखर पर मरने के लिए छोड़ दिया। वह बालक भूख-प्यास से बिलखता रहा। संयोग से, शिव और पार्वती कहीं जा रहे थे। उन्होंने शिशु के रोने का स्वर सुना, तो तुरंत उसके पास पहुंच गए। बालक को ऐसी करुण दशा में देखकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया।

'प्रभु, यह बालक कौन है?' पार्वती ने महादेव से पूछा।

शिव ने पार्वती को बालक और उसके माता-पिता के विषय में बताया। पार्वती ने क्रोध में राक्षस जाति को शाप दे दिया : 'मेरा शाप है कि राक्षस कुल में शिशु जन्म लेते ही तत्काल वयस्क हो जाएंगे!'

● शिव-पार्वती ने शिशु के पालन-पोषण का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। पार्वती ने उसके सुंदर केश देखकर उसका नाम 'सुकेश' रख दिया।

सुकेश, महादेव और पार्वती के संरक्षण में अत्यंत बलशाली और ज्ञानवान बन गया। एक दिन पार्वती और शिव ने सुकेश को बुलाया और कहा, 'पुत्र, तुम्हारे पिता विद्युत्केश के दुर्बल नेतृत्व में राक्षसों की प्रतिष्ठा कम हुई है। तुम अब बड़े हो गए हो। इसलिए राक्षसों का नेतृत्व करो और वंश के गौरव को पुनर्स्थापित करो।'

सुकेश ने तुरंत राक्षसों को संगठित करने का कार्य आरंभ कर दिया। उसके नेतृत्व में राक्षस फिर से साधन-संपन्न एवं शक्तिशाली हो गए और उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हो गई। फिर सुकेश ने देववती नाम की गंधर्व कन्या से विवाह किया। देववती से तीन पराक्रमी पुत्र हुए-माल्यवान, सुमाली और माली। तीनों बहुत बलवान थे।

● तीनों भाई भयंकर तप करके ब्रह्मा से शक्तियां अर्जित कर अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने देवताओं तक पर नियंत्रण पा लिया।

एक दिन तीनों भाई, देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले, 'हम राक्षसों के लिए एक भव्य नगरी का निर्माण कराना चाहते हैं, जो ऐसे स्थान पर हो, जहां कोई शत्रु न पहुंच सके।'

विश्वकर्मा ने विचार करके कहा, 'दक्षिणी समुद्र के तट से एक सौ योजन की दूरी पर त्रिकूट नामक एक पर्वत है। वह इतना ऊंचा है कि पक्षी भी उड़कर वहां तक नहीं पहुंच सकते। वह स्थान दुर्जेय है। मैंने उस शिखर पर देवराज इंद्र के लिए अद्‌भुत और विशाल स्वर्ण नगरी का निर्माण किया था। परंतु इंद्र को पसंद नहीं आई। इसलिए वह स्वर्ण नगरी वीरान पड़ी है। आप चाहें, तो वहां रह सकते हैं।'

'उस नगरी का क्या नाम है?' माल्यवान ने पूछा।

'लंका!' विश्वकर्मा ने उत्तर दिया।

इस तरह इंद्र के लिए बनाई गई लंका, राक्षसों की हो गई।

अध्ययन कक्ष

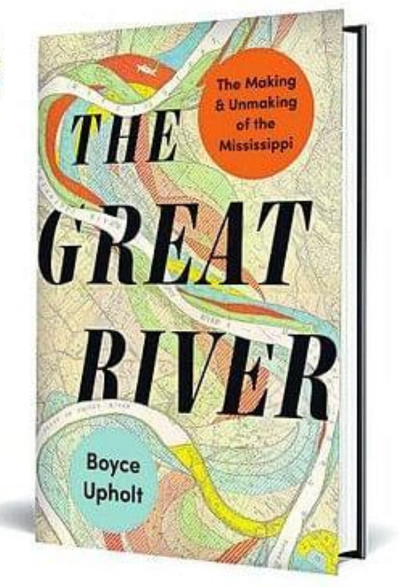

द ग्रेट रिवर
द मेकिंग ऐंड अनमेकिंग ऑफ द मिसिसिपी

लेखक-बॉयस उफोल्ट।

प्रकाशक- डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्टन ऐंड कंपनी।

मूल्य-29.99 डॉलर।

जब एक नदी बंधी

लेखक-पत्रकार बॉयस उफोल्ट गुस्सैल नदी मिसिसिपी की कहानी बताते हुए कहते हैं कि सदियों से इस नदी को बांधने की कोशिश हुई, फिर भी इसने अपनी आदत नहीं बदली।

अमेरिका और मिसिसिपी नदी का रिश्ता सहज नहीं रहा है। अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति और लंबाई के कारण ही यह एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट बनी। दूर तक फैली इसकी जलोढ़ मिट्टी को दुनिया के सबसे उर्वर प्रदेश के रूप में आंका जाता रहा है, लेकिन ऐसे असंख्य इलाके सालों-साल इसकी बाढ़ में डूबकर नष्ट हो जाने के लिए भी अभिशप्त रहे हैं।

मिसिसिपी की जलधाराएं आधे अमेरिका तक फैली हैं। इटास्का झील से अपनी यात्रा शुरू कर 2,350 मील दूर मेक्सिको की खाड़ी में गिरने तक यह नदी अमेरिका के 31 और कनाडा के दो राज्यों से होकर गुजरती है, और इस दौरान एक लाख से अधिक सहायक नदियां और मिसौरी तथा ओहियो जैसी बड़ी नदियां भी इसमें मिलती हैं। इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उत्तर अमेरिका के आदिवासी समुदाय ने इसे 'मिसि-जीबी' नाम दिया, जिसका अर्थ है महान नदी।

सोलहवीं सदी में यूरोपीय सैलानियों ने इस विशाल नदी में सोने की खोज की, तो मार्क ट्वेन की पहल से इसके तट पर राष्ट्रीय साहित्य का सृजन हुआ। मिसिसिपी नदी के तट पर जैज और ब्लू जैसे संगीत की धुन बनी और गूंजी। लेखक-पत्रकार बॉयस उफोल्ट इस गुस्सैल नदी की कहानी बताते हैं कि सदियों से इस नदी को बांधने की कोशिश हुई, फिर भी मिसिसिपी ने अपनी आदत नहीं बदली।

हजारों वर्षों से मिसिसिपी की जलधाराएं अमेरिका के लाखों आदिवासी लोगों का आवास रही हैं, जो इस 'महान नदी' के क्रोध और बार-बार दिशा बदलने की इसकी आदत से अवगत होने के बावजूद इसे आदर देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने मिसिसिपी की बाढ़ के अनुरूप अपना जीवन ढाल लिया है। आखिर मिसिसिपी सदियों से इन्हें जीवन और जीविका, दोनों देती रही थी। इसकी जलधाराओं और बाढ़ में आई मिट्टी ने अमेरिकी उद्यमियों के साथ-साथ इसके तट पर बस गए ब्रिटिशों तक को आकर्षित किया है। आखिर वे यूरोपीय इंजीनियर ही थे, जिन्होंने पहली बार इसे बांधने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि वह दलदली जमीन गायब हो गई, जो पहले मिसिसिपी के उद्दाम बहाव पर अंकुश लगाती थी। बड़े बांध के निर्माण से बड़े पैमाने पर स्थानीय अमेरिकियों की खेती डूब गई। थॉमस जेफरसन के समय से आज के पर्यावरण सजग दौर तक मिसिसिपी नदी पर अधिकार जमाने, इसे बांधने और इसकी दिशा बदलने की कोशिशों ने इस नदी का स्वरूप ही बदल दिया है। उफोल्ट सिर्फ मिसिसिपी का इतिहास ही नहीं, बल्कि यह भी बताते हैं कि इस पर विजय पाने की कोशिश में किस तरह स्थानीय मूल निवासियों और गरीबों की अनदेखी हुई। शुरुआती दौर में मिसिसिपी के निचले इलाके में मलेरिया की मार ने कम पैसे वाले बागान मालिकों और बांध बनाने में लगे मजदूरों को वहां से बाहर कर दिया। ऐसे में, सिर्फ समृद्ध लोगों को मिसिसिपी से लाभ उठाने का मौका मिला। यानी मिसिसिपी को बांधने की कोशिशों का सिर्फ पर्यावरणीय नुकसान ही नहीं हुआ, इसने गरीब मूल निवासियों को भी विस्थापित कर दिया।

अभियान

किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जवाबों से नहीं, बल्कि उसके सवालों से करना चाहिए।
-वोल्टेयर, महान दार्शनिक

amarujala.com
अमर उजाला

गोल चबूतरा

Hindi@mithelesh

■ मिथिलेश बारिया

हर साल बारिश में सड़क खराब हो जाती है,
इतने साल हो गए, न बारिश बदली
न सड़क...

जरा सरककर बैठो न,
मोहब्बत को भी तो जगह चाहिए...

ऐसे मिली परमाणु ऊर्जा की राह

झरोखा

30 जून

आज के ही दिन सन 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने जर्मनी की एक भौतिकी पत्रिका 'एनालेन डेर फिजिक' में चलती वस्तुओं के 'इलेक्ट्रोडायनामिक्स' को लेकर 'जूर इलेक्ट्रोडायनामिक बेवेग्टर कॉर्पर' शीर्षक से अपना एक शोध प्रकाशित कराया था। यह एक अद्भुत शोध था। आइंस्टीन ने 1902 से 1909 तक बर्न स्थित स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में भी काम किया था। वहां उनके दिमाग में जिन विचारों ने जन्म लिया, वे 1905 में एक के बाद एक लिखे गए पांच सैद्धांतिक शोध पत्रों में प्रकाशित हुए, जिन्होंने बीसवीं सदी के विज्ञान में क्रांति पैदा की। आइंस्टीन का पहला शोध पत्र 'फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव' पर था, जिसके लिए उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे शोध पत्र में आणविक आकार का निर्धारण, तीसरे में ब्राउनियन गति की गणितीय व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। आइंस्टीन के चौथे शोध पत्र को भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाशित सबसे महत्वपूर्ण शोध माना जाता है, जिसमें सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज के दूरगामी परिणाम सामने आए और इसने ही परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु बम के निर्माण के लिए मंच तैयार किया।

■ सीतापुर से ज्ञान विवेक

हर साल कुछ घंटों की बारिश में ही दिल्ली समेत कई महानगर पानी से भर जाते हैं और बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इस कुव्यवस्था के लिए शासन-प्रशासन जितने जिम्मेदार हैं, उससे कम जिम्मेदार एक आम नागरिक भी नहीं है।

हर साल इस बारिश का रोना

पहले से क्यों नहीं करते तैयारी?

चिट्ठी 1

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गईं। कई जगह नाव चलीं और कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। बारिश की वजह से ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर पिकअप-ड्रॉप एरिया की छत और सपोर्टिंग पिलर गिर गया। इसमें कई कारें दब गईं और जान-माल का नुकसान हुआ। पिछले साल हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों में बरसात ने बहुत कहर बरपाया था। दिल्ली में लाल किला, राजघाट जैसे वीआईपी इलाके बारिश के पानी में डूब गए थे।

अगर समय रहते बरसात से बचाव के लिए तैयारी कर ली जाए तो यह मौसम इतनी आफत न बरसाए। हाल ही में मौसम विभाग ने सामान्य बारिश होने की भविष्यवाणी की है, इसलिए केंद्र और राज्यों को मानसून से निपटने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए, ताकि इस बार फिर से मानसून आफत न बने।

बरसात तो हर वर्ष आती है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए नाकाम ही दिखती हैं। एक या दो बारिश के बाद ही जगह-जगह पानी के तालाब बन जाते हैं। लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस जाता है। गंदे पानी से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन सरकारें इसके प्रति भी गंभीर नजर नहीं आतीं। कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं, जहां के बहुत से स्थानों की सीवरेज व्यवस्था सुचारू नहीं है। हर प्रदेश और केंद्र सरकार को चाहिए कि वह साफ-सफाई की उचित व्यवस्था कराए। लेकिन इसी के साथ हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात का ध्यान रखें कि नालियां हमारी वजह से जाम न हों। नालियों में पॉलिथीन न फेंकें।

■ राजेश कुमार चौहान, जालंधर

अब मच्छर भी सोने नहीं देंगे !

चिट्ठी 2

आज भारत ही नहीं, बल्कि सारा विश्व मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण करने के लिए चिंचित है। विश्व स्तर पर बढ़ता मच्छरों का प्रकोप हर वर्ष लाखों लोगों की जान ले रहा है। भारत में गरमी और बरसात का यह संधिकाल मच्छरों के प्रजनन का समय है। इस समय मच्छर कूलर, पानी की टंकी, गड्ढों में जमा पानी और नाले आदि स्थानों पर अपने लार्वा को सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। बस यहीं से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जाता है। मच्छर खुद को जीवित रखने के लिए मानव शरीर से रक्त चूसकर, फिर दूसरे-तीसरे मानव को काटकर कई तरह के संक्रमणों को जन्म देता है। ये मच्छर जीका, वेस्ट नाइल, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, पीला बुखार, फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं और पूरे विश्व में हाहाकार मचा रहे हैं।

जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि मादा मच्छर ज्यादा खतरनाक होती हैं। मादा मच्छर का जीवन 42 से 56 दिन और नर मच्छर का जीवन 10 दिन का होता है। बरसात के दिनों में मच्छरों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए हमें अपने घर से ही सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है। मच्छरों से बचाव करके ही बरसात में होने वाले रोगों को रोका जा सकता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण मच्छरों के पनपने की संभावना रहती है। प्रशासन और सामाजिक संगठनों का सहयोग लेकर हम मच्छरों से निजात पा तो सकते हैं, लेकिन खुद की पहल ज्यादा जरूरी है।

■ अशोक वार्ष्णेय, हल्द्वानी

अफवाहों पर अंकुश जरूरी

चिट्ठी 3

सोशल मीडिया आज के समय में सामाजिक रूप में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस पर आप स्वयं को समाज से साझा करते हैं, लेकिन वहीं पर असामाजिक तत्व भी हैं, जो सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर हो या भ्रामक पहचान बनाकर भावनाओं को भड़काना, या फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इन सबमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर उपयोग किया जाता है।

किसी एक पक्ष को लेकर बेहद संवेदनशीलता और आग्रह, अन्य के प्रति पूरी तरह संवेदनहीनता एवं दुराग्रह, पूर्वाग्रह से ग्रस्त या अपने जैसी विचारधारा के लोगों का गुट बनाकर किंगमेकर बनने का प्रयास, जिससे कुछ लोगों को चढ़ाया जा सके और कुछ को गिराया जा सके, फिर ऐसे गुटों के माध्यम से मास रिपोर्टिंग और ट्रोलिंग करना, यहां तक कि दंगे, उपद्रव कराने में भी सोशल मीडिया का अहम किरदार है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 50 प्रतिशत बातें सत्य से कोसों दूर होती हैं। कई बार झूठी अफवाहें फैलाकर दंगे भड़काया जाते हैं। सरकार हो या पुलिस, पूरा नियंत्रण न होने के कारण कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स समाज में जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। इन सब मामलों पर सरकार की ठोस रणनीति के साथ ही कानूनन पुलिस साइबर सक्रियता हो, जो तुरंत सकारात्मक कार्रवाई करे और दंगे, उपद्रव, उन्माद होने से रोक सके, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स धीमे जहर का काम कर रहे हैं।

■ लक्ष्मण पुंडीर, श्रीनगर गढ़वाल

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

लखनऊ से निखिल रस्तोगी, सिरमौर से हेमराज राणा, लोएडा से लक्ष्मी नारायण, बरेली से दिलीप कुमार गुप्ता, झांसी से डॉ. अतुल गोयल, अमरोहा से डॉ. महताब अमरोहवी, फिरोजाबाद से शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, अलीगढ़ से अनुपमा अग्रवाल, मिर्जापुर से सलिल पांडेय, बेतीताल से डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, नई दिल्ली से विजय किशोर तिवारी, रायपुर से संजीव ठाकुर।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

एक तरफ 'लूका' दूसरी तरफ 'इस्ला'

स्कॉटलैंड में लड़कों के लिए 'लूका' और लड़कियों के लिए 'इस्ला' नाम सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

वैसे तो कहते हैं, नाम में क्या रखा है। लेकिन स्कॉटलैंड आकर देखें, यहां बच्चों के नाम पर 'घमासान' मचा हुआ है। नेशनल रिकॉर्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड (एनआरएस) के नए आंकड़ों के अनुसार, 2023 में पहली बार स्कॉटलैंड में लड़कों के लिए 'लूका' सबसे पसंदीदा नाम रहा। वहीं लड़कियों के नामों में 'इस्ला' 2020 के बाद पहली बार शीर्ष स्थान पर रहा।

स्कॉटलैंड में पिछले साल बच्चों को रिकॉर्ड संख्या में नए नाम दिए गए, जिनमें बड़ी संख्या में बैंक्सी, डेमन और जिहाद जैसे नाम शामिल रहे। लड़कों को दिए गए 2,362 अनोखे नामों में बॉय, डेमिगॉड, हॉवेल और शेडी भी शामिल थे। लड़कियों के लिए 2,983 अनोखे नामों में अलॉय, कॉस्टली और पेस्टी शामिल थे।

रिसर्चर फिलिपा हैक्सटन के अनुसार, एनआरएस को स्कॉटलैंड में 2023 में रखे गए सभी नए नामों में एक अलग किस्म का नयापन देखा गया। वैसे भी पिछली पीढ़ियों की तुलना में लोग नए नामों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं।

यही वजह रही कि लड़कों के लिए अलग-अलग नामों की संख्या 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। साथ ही वर्ष में केवल एक बच्चे को कई-कई नामों से पुकारने का चलन भी बढ़ा। लड़कियों के नामों के लिए भी यही पैटर्न देखा गया और उनके नामों में विविधता अब भी लड़कों की तुलना में अधिक पाई गई।

कुछ नाम जो तेजी से प्रचलन में आ रहे हैं, वे फिल्मों से जुड़े हुए हैं। 'लूका' जो अब स्कॉटलैंड में बच्चों के लिए सबसे लोकप्रिय नाम है, 2021 में इसी नाम की फिल्म की रिलीज के बाद लोगों की पसंद में आगे आता गया। इस बीच ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'ओपेनहाइमर' और 'बार्बी' के किरदारों के नामों की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई। इनमें 'सिलियन' और 'मार्गोट' बहुत लोकप्रिय हुए। चर्चित नए नामों की सूची में 'ओकले' और 'मेबेल' भी लोगों की पसंद में अचानक शामिल हो गए।

■ ऋतु मिश्रा, चंडीगढ़

वैज्ञानिक की पाठशाला

यह तस्वीर 1930 की है। इसमें भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं।

■ हिसार से देवीनंदन

ग्रामोफोन

साहिबा खुश होती रही और जमाना सुनता रहा

1993 में एक फिल्म आई थी- 'साहिबा'। इसके गीत लिख रहे थे आनंद बख्शी, जिनकी धुन बनाने की जिम्मेदारी मिली थी पंडित शिवकुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यानी शिव-हरि की जोड़ी को। फिल्म का एक शीर्षक गीत भी लिखा जाना था। इसके लिए आनंद बख्शी ने गीत लिखा- 'साहिबा मेरी साहिबा'। अब इसकी धुन बनने की बारी थी। शिव-हरि को 1953 में आई फिल्म 'आंसू' के गीत 'सुन मेरे साजना' की धुन बहुत अच्छी लगती थी। इस गीत की धुन पंजाबी शैली की अभिव्यक्ति थी, जिसे हुस्नलाल-भगतराम की जोड़ी ने उभारा था। काफी सोच-विचार और मंथन के बाद शिव-हरि ने 'साहिबा मेरी साहिबा' की धुन भी हुस्नलाल-भगतराम के गीत के नोट्स पर तैयार की। फिल्म का गीत-संगीत तो हिट हुआ ही, लेकिन यह शीर्षक गीत सुपरहिट हुआ। इस गीत को गाने के लिए शिव-हरि ने अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाजें लीं। परदे पर इसे माधुरी दीक्षित और ऋषि कपूर ने गाया।

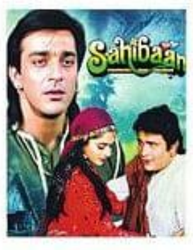

■ मंजू सिंह, बरेली

जातिगत भेदभाव पर लोहिया

लोहिया इस बात को बखूबी समझते थे कि भारतीय समाज में 'जाति' एक महत्वपूर्ण कारक है। जो लोग इसे सैद्धांतिक रुप से नहीं मानते हैं, वे इसे व्यावहारिक तौर पर स्वीकार करते हैं।

ब्रिटिश शासन के अंतिम दशकों की बात करें तो भारत में समाजवादी और कम्युनिस्ट नेता उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति में सक्रिय थे। उसके बाद आजादी के पहले के दशकों में ये दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बने रहे। समाजवादियों और कम्युनिस्टों की शुरुआती पीढ़ियों में साहस और आदर्श के अलावा दूसरे कई गुण भी थे। फिर भी उनमें एक कमी थी- भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव के बारे में जागरूकता की कमी। लेकिन इस मामले में समाजवादी विचारक और राजनीतिज्ञ राम मनोहर लोहिया एक अपवाद थे।

जातिगत भेदभाव के ऊपर लोहिया ने जो लिखा, उसे प्रशंसकों ने इकट्ठा कर उनके जीवनकाल में ही एक किताब के रूप में हैदराबाद से प्रकाशित कराया था। हालांकि वह किताब लंबे समय से अब प्रिंट में नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र प्रकाशक ने उसका संशोधित संस्करण जरूर निकाला। संयोग की बात यह है कि वह प्रकाशन संस्थान भी हैदराबाद में ही स्थित था। लोहिया ने अपने वामपंथी साथियों के बारे में लिखा था कि वे ईमानदारी से, लेकिन गलत तरीके से यह सोचते हैं। वे मानते हैं कि सिर्फ आर्थिक असमानता को खत्म करने के परिणामस्वरूप जातिगत असमानता अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्हें आर्थिक और जातिगत असमानता रूपी राक्षस को खत्म करना था, पर वे इसे समझ पाने में असफल रहे।

लोहिया इस बात को बखूबी समझते थे कि भारतीय समाज में 'जाति' एक महत्वपूर्ण कारक है। जो लोग इसे सैद्धांतिक रूप से नहीं मानते हैं, वे इसे व्यावहारिक तौर पर इसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत में 'जन्म, मृत्यु, विवाह, दावत जैसे अनेक अनुष्ठान' जातिगत ढांचे के अनुसार ही चलते हैं। इस व्यवस्था को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि "ऊंची जातियों के लोग राजनीतिक और आर्थिक, दोनों तरह से अपना शासन बनाए रखें। वे अकेले इस व्यवस्था को बंदूक के दम पर नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्हें उन लोगों में हीनता की भावना को भरना था, जिन पर वे राज करना चाहते थे या जिनका शोषण करना चाहते थे।"

यद्यपि लोहिया दलितों के विरुद्ध भेदभाव को नजरअंदाज नहीं करते। उनका ध्यान उन सवर्ण या उच्च जातियों पर केंद्रित है, जहां से राजनीतिक, प्रशासनिक, पेशेवर, व्यावसायिक और बौद्धिक अभिजात्य वर्ग आते थे और छोटी जातियों का सत्ता और उच्च पदों पर बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व नहीं था। 1958 में उन्होंने लिखा था कि सवर्ण, भारत की आबादी के पांचवें हिस्से से भी कम हैं। इसके बाद भी वे राष्ट्रीय गतिविधियों, व्यापार, सेना, सिविल सर्विस या फिर राजनीतिक पार्टियों में आसानी से आ जाते हैं। राष्ट्र की प्रगति के लिए इस असंतुलन को सही करना होगा। लोहिया चाहते थे कि उनके साथी समाज के निचले वर्गों, जैसे कि महिलाओं, पिछड़ों , हरिजन, मुस्लिम और आदिवासियों को ऊपर लाने के लिए संघर्ष करें, भले ही उनकी योग्यता आवश्यक रूप से कम हो। वे मानते थे कि सदियों पुराने इतिहास में जो कुछ हुआ, उसे अब खत्म किया जाना चाहिए।

समाजवादियों से लोहिया की अपेक्षा थी कि वे

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

अंतरजातीय, खासतौर से अलग-अलग वर्णों के बीच होने वाले विवाह को बढ़ावा दें। वे लिखते हैं, "अगर जाति के बंधन को तोड़ दिया जाए या उसमें थोड़ी ढील दी जाए तो उच्च जाति के बहुत से युवा पिछड़ी जातियों की महिलाओं की ओर आकर्षित होंगे और अपने साथ-साथ देश के लिए खुशियां लाएंगे। ठीक इसी तरह पिछड़ी जातियों के लड़के उच्च जातियों की महिलाओं की जिंदगी में प्रवेश कर सकेंगे।"

1960 में लोहिया ने जाति के अध्ययन और पिछड़ेपन को समझने के लिए संघ के गठन की बात कही थी। उन्होंने इस संघ के आठ मुख्य उद्देश्य बताए, जिनमें से दो के बारे में बताता हूं। पहला यह कि धर्म के साथ-साथ उसकी प्रथाओं को भी जाति दोष से मुक्त किया जाए, इस विश्वास के साथ कि अंतरजातीय विवाह करने से जातियां खत्म हो सकती हैं। दूसरा यह कि सरकारी पदों, राजनीतिक दलों, व्यापार और सशस्त्र सेवा में कानून या परंपरा के तौर पर 60 प्रतिशत पदों को पिछड़ी जाति, महिलाओं, हरिजन और आदिवासियों के लिए सुरक्षित करने की मांग की जाए।

पुस्तक के एक दिलचस्प हिस्से में 1955-56 में एक तरफ डॉ. लोहिया और उनके सहयोगियों तथा दूसरी तरफ डॉ. भीमराव आंबेडकर के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों की एक शृंखला को पुनः प्रस्तुत किया गया है। यहां इन दोनों नेताओं और उनके अनुयायियों को एक-दूसरे के करीब लाने का प्रयास किया गया था, शायद इस उद्देश्य से कि उनकी दोनों पार्टियां 1957 के आम चुनावों में एक साझा मंच पर लड़ें। लोहिया और आंबेडकर के बीच जब पत्र-व्यवहार की शुरुआत हुई थी, लोहिया ने आंबेडकर से कहा था, "मैं चाहता हूं कि सहानुभूति के साथ गुस्सा भी जुड़ जाए और आप न सिर्फ पिछड़ी जातियों के, बल्कि भारतीय लोगों के भी नेता बनें।" आंबेडकर ने लोहिया के पत्र का जवाब देते हुए लिखा, "आप मुझसे 2 अक्तूबर को दिल्ली में आकर मिलें।" यह गांधी का जन्मदिन था और शायद यह महज एक संयोग था। दुर्भाग्य से लोहिया के घुमक्कड़ जीवन और आंबेडकर के खराब स्वास्थ्य के कारण दोनों क्रांतिकारी सुधारक व्यक्तिगत रूप से मिलकर संभावित सहयोग पर चर्चा नहीं कर पाए।

6 दिसंबर, 1956 को आंबेडकर का निधन हो गया। लोहिया ने अपने साथी समाजवादी मधु लिमये को लिखा, "आंबेडकर भारतीय राजनीति के महान व्यक्ति थे। गांधी के साथ-साथ वे भी सबसे बड़े हिंदू थे। इस तथ्य ने मुझे हमेशा से एक संबल और विश्वास दिया है कि हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था एक दिन खत्म हो सकती है।" उन्होंने आगे लिखा, "डॉ. आंबेडकर विद्वान, ईमानदार, साहसी और स्वतंत्र व्यक्ति थे। उन्हें बाहरी दुनिया में ईमानदार भारत के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन वे थोड़े सख्त थे। उन्होंने गैर-हरिजन का नेता बनने से मना कर दिया।"

लोहिया ने सोचा कि आंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्हें डॉ. आंबेडकर ही बना रहने दिया जाए। जातिगत भेदभाव के प्रति लोहिया की गहरी जागरूकता उन्हें अपने समय के अन्य समाजवादियों से अलग करती है और यही बात उनके 'नारीवाद' पर भी लागू होती है। वे लिखते हैं, "अगर भारतीय लोग पृथ्वी पर सबसे दुखी हैं, तो जातिगत भेदभाव और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण इस पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।" लोहिया ने लिखा है, "एक पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा होता है कि महिला का स्थान रसोई में है। ऐसे में समाजवादियों को इस बात का विरोध करते हुए कहना चाहिए कि ऐसे में तो पुरुषों की जगह नर्सरी में होनी चाहिए। साठ सालों से यह तर्क दिया जा रहा है कि बच्चों के पालन-पोषण में पति और पिता को बराबरी के साथ हिस्सा लेना चाहिए। यह एक आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कहीं दिखता नहीं।"

इस कॉलम में उद्धृत लेख, पत्र और भाषण 1953 और 1961 के बीच लिखे गए थे। ऐसा हो सकता है कि अभी ब्राह्मणवाद राजनीति और प्रशासन पर उतना हावी न हो, जितना 1950 के दशक में था। फिर भी संस्कृति और आर्थिक जीवन में वे आबादी में अपने हिस्से के अनुपात से कहीं ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसलिए कई मामलों में जाति पर लोहिया के विचार और शब्द एक अद्भुत समकालीनता रखते हैं।

शायरी की एक हस्ती को याद करते हुए

बीते चार से ज्यादा दशक यानी तीन पीढ़ियां गजल सम्राट जगजीत सिंह की गजल 'प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है' सुनती रही है और आने वाली पीढ़ियां भी सुनती रहेंगी। ऐसी असंख्य बेहतरीन गजलें लिखने वाले 78 वर्षीय शायर हस्तीमल हस्ती गुजरी 24 जून को इस फानी दुनिया से अलविदा कह गए।

11 मार्च, 1946 को राजस्थान के आमेर में राजसमंद शहर के एक व्यावसायिक परिवार में जन्मे हस्तीमल के परिवार का दूर-दूर तक साहित्य से कोई वास्ता नहीं था। स्कूल के जमाने से ही अखबारों के जरिये साहित्य के प्रति लगाव के फलीभूत हस्तीमल ने लिखने की शुरुआत कहानी से की थी। पुश्तैनी रूप से सोने-चांदी के आभूषणों का व्यापार करने वाले परिवार से हस्तीमल को सोने, चांदी और हीरे की पहचान का धंधा घुट्टी में मिला था। पुश्तैनी धंधे को मुंबई में जीवन भर बखूबी संभालते हुए हस्तीमल ने अपनी लगन, इच्छाशक्ति और संकल्प के दम पर कहानी लेखन को छोड़ शायरी की दुनिया में प्रवेश किया और ऐसा मुकाम हासिल किया कि जौहरी हस्तीमल से वह हस्तीमल हस्ती हो गए।

राजेन्द्र शर्मा

स्मृति शेष

हस्तीमल हस्ती

सब कहते हैं कि हिंदी में पाठकों की कमी है तो यह बात चौंकाने वाली है कि हस्तीमल हस्ती के तीनों गजल संग्रह हाथों-हाथ बिक गए और अब आउट ऑफ स्टॉक हैं।

प्यार से सरोबार, सादा तबियत इन्सान और बेहद सादा लफ्जों में कमाल के शे'र कह देने का हुनर रखने वाले हस्तीमल हस्ती की गजलों को जगजीत सिंह, पंकज उधास, पीनाजी मसानी ने अपने स्वरों से सजाया था।

अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने के पक्षधर हस्तीमल ने छोटी बहर में ऐसी-ऐसी बेहतरीन गजलें लिखीं, जो मील का पत्थर मानी जाती हैं। एक बानगी देखिए- 'उस जगह सरहदें नहीं होतीं, जिस जगह नफरतें नहीं होतीं। उसका साया घना नहीं होता, जिसकी गहरी जड़ें नहीं होतीं।'

हस्तीमल हस्ती बतौर शायर ऐसा लिखने भर के लिए नहीं लिखते थे, उनके व्यक्तित्व में भी ये सारी बातें शुमार थीं। महत्वाकांक्षाओं की राजधानी मुंबई में हमेशा सफेद झक कपड़े पहनने वाले शायर हस्तीमल हस्ती निजी जीवन में भी हमेशा सफेद झक बने रहे। उनके तीन गजल संग्रह 'कुछ और इस तरह से भी', 'क्या कहें किससे कहें' और 'प्यार का पहला खत' प्रकाशित हो चुके हैं। इस दौर में, जहां यह कहा जाता है कि हिंदी में पाठकों की कमी है, क्या यह बात चौंकाने वाली नहीं है कि हस्तीमल हस्ती के तीनों गजल संग्रह हाथो-हाथ बिक गए और आउट ऑफ स्टाक हैं! उनके जाने से एक शून्य-सा पैदा हो गया है, लेकिन उनकी गजलें हमेशा उन्हें अमर रखेंगी।

https://t.me/AllNewsPaper

सुख व्यक्ति के अहंकार और दुख धैर्य की परीक्षा लेता है

नए आपराधिक कानून

अंग्रेजों के जमाने की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने और न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर अमल की तैयारी के बीच विरोध के स्वर उभरने पर हैरानी नहीं। अपने देश में सदैव ऐसा ही होता है। पिछले कुछ समय से ऐसा कुछ ज्यादा ही होने लगा है। सुधार के हर कदम का विरोध किया जाता है। कई बार तो उस कदम के गुण-दोष का संज्ञान लिए बिना। ऐसा विरोध के लिए विरोध की राजनीति के तहत किया जाता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि जहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। विपक्षी दलों के कुछ और नेताओं ने भी इन नए आपराधिक कानूनों को लागू किए जाने का विरोध करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। विरोध के लिए वही घिसे-पिटे तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे यह कि नए कानूनों को लागू करने के पहले पूरी तैयारी नहीं की गई है। स्पष्ट है कि यह तर्क देने वाले जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि इन कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद से लाखों पुलिस कर्मियों समेत जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। इससे इन्कार नहीं कि तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के क्रम में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो हर नई व्यवस्था पर अमल करते समय होता है। जितना बड़ा बदलाव होता है, चुनौतियां भी उतनी ही अधिक होती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि चुनौतियों से बचने के लिए पुरानी और कष्टकारी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। कोई भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि अंग्रेजी सत्ता की ओर से बनाए गए आपराधिक कानून न्याय देने में सहायक नहीं बन रहे। छोटे-छोटे मामलों में भी न्याय पाने में आवश्यकता से अधिक समय और संसाधन खपाना पड़ता है। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनमें से कुछ का तो अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिनके बारे में अभी किसी को आभास न हो। ऐसे में सरकार को आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ताकि लोगों को समय पर सुगम तरीके से न्याय मिल सके। इन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का मूल उद्देश्य भी यही है। नए आपराधिक कानूनों के लागू करने के क्रम में यह प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा कि वे न्यायिक तंत्र के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी छवि को सुधारने में सक्षम होते हैं या नहीं?

वायु में घुलता जहर

हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है तो इसका अच्छा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। वायु, जल व खाद्य पदार्थ आदि यदि शुद्ध मिलते हैं तो हमारी सेहत बेहतर रहती है। अक्सर खाद्य पदार्थों में मिलावट की बातें उजागर होती रहती हैं। समय-समय पर छापेमारी में मिलावटी दूध, पनीर, तेल, रिफाइंड निर्माण के मामले सामने आते रहते हैं। प्रदेश के कई जिलों में जल में आर्सेनिक व अन्य घातक तत्व के होने को लेकर चिंता जाहिर की जाती है। इस बीच बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा राज्य के छह प्रमुख शहरों की हवा के अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार, पटना के वातावरण में लेड की उच्चतम मात्रा दर्ज की गई है। गया की हवा में आर्सेनिक की मात्रा राज्य में सर्वाधिक पाई गई। निकेल की सर्वाधिक सांद्रता मुजफ्फरपुर में रिकार्ड हुई। छह शहरों के तुलनात्मक अध्ययन में राजगीर की हवा सर्वाधिक बेहतर पाई गई। वहां पर तीन धातुओं की स्थिति मानक से काफी नीचे पाई गई। कारण बताया गया कि पेंट एवं बैट्री से तथा उद्योगों से भी वातावरण में लेड की मात्रा बढ़ रही है। वहीं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, धातु गलाने वाले संयंत्रों से वातावरण में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। बिजली उत्पादन संयंत्र, वाहन एवं उद्योगों से वातावरण में निकेल की मात्रा में वृद्धि हो रही है। लेड, आर्सेनिक एवं निकेल तीनों भारी धातु की श्रेणी में शामिल हैं। इनका मानव जीवन पर अत्यंत घातक प्रभाव होता है। इन धातुओं की बढ़ रही मात्रा नियंत्रित करने को जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ उद्योगों के लिए भी तय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

वायु में जो मानवजनित घातक अशुद्धता बढ़ी है उस पर नियंत्रण के लिए ठोस व कारगर कार्ययोजना की आवश्यकता है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले भारतीय क्रिकेट टीम अधिक मजबूत है?

आज का सवाल
क्या दिल्ली में रिकार्ड बारिश जलवायु परिवर्तन का नतीजा है?

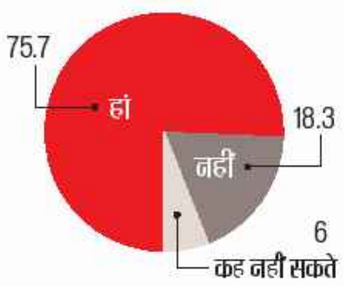

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विपक्ष की अनावश्यक आक्रामकता

संजय गुप्त

आखिर कोई दल आपातकाल के स्मरण का विरोध करते हुए यह दावा कैसे कर सकता है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है?

नई लोकसभा के गठन के साथ ही नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार की तीसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। इस सरकार का नेतृत्व संभालने के पहले से कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार बनी, उसे बहुमत हासिल नहीं है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है कि जनता ने भाजपा के चार सौ पार के नारे को ठुकरा दिया, इसलिए यह प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक और राजनीतिक हार है। यह सही है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस का यह दावा भी तो सही नहीं साबित हुआ कि उसके नेतृत्व वाले गठबंधन यानी आइएनडीआइए को 295 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस नेता इस तथ्य की अनदेखी कर रहे हैं कि भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ बहुमत हासिल किया। भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर वैसे ही चुनाव लड़ा था, जैसे कांग्रेस ने अपने घटक दलों के साथ।

चूंकि कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले लगभग दोगुनी सीटें मिली हैं, इसलिए उसका उत्साहित होना समझ में आता है, लेकिन आखिर वह यह माहौल क्यों बना रही है कि लोकसभा चुनावों में आइएनडीआइए की जीत हुई और राजग अर्थात एनडीए की हार? अपने संख्याबल में वृद्धि के चलते कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, लेकिन यह जताना उसकी एक राजनीतिक भूल है कि उसने भाजपा को मात दे दी है। यह माहौल बनाने में वह राहुल गांधी भी जुटे हुए हैं, जो लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष बन गए हैं। यदि मोदी की हार हुई है तो फिर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों स्वीकार कर लिया? लगता है राहुल गांधी यह मानकर चल रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जितना अधिक हमलावर होंगे और राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए आक्रामक बने रहेंगे तो इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। यदि राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यही रवैया रहा तो इसके आसार कम ही हैं कि वह अपनी इस नई भूमिका में कोई सकारात्मक राजनीति कर सकेंगे और सरकार को रचनात्मक सहयोग देने में कोई सार्थक भूमिका निभा सकेंगे।

जैसी आशंका थी, नई लोकसभा का कार्यकाल विपक्ष की आक्रामकता के साथ शुरू हुआ। विपक्ष का आक्रामक रवैया लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी दिख रहा है। पिछले दिनों तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सभापति के आसन के समक्ष पहुंच गए। लोकसभा में भी विपक्ष ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। इससे आने वाले दिनों में संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल के आसार नहीं। इसकी एक

अवधेश राजपूत

झलक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के संबोधन के समय भी मिली। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के उन बिंदुओं पर भी आपत्ति जताई, जिन पर आपत्ति का कोई मतलब नहीं बनता था। सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव की झलक तब भी मिली, जब लोकसभा स्पीकर के चुनाव की नौबत आ गई। यह नौबत कांग्रेस के अनावश्यक आक्रामक रवैये के कारण ही आई। नई लोकसभा में नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विपक्षी नेताओं ने जिस तरह संविधान की प्रतियां लहराते हुए उसे बचाने का नैरेटिव गढ़ा, उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संविधान को कोई खतरा नहीं।

यह ठीक है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यह जो झूठा नैरेटिव गढ़ा कि यदि राजग को 400 सौ से अधिक सीटें मिल गईं तो भाजपा संविधान बदल देगी, उससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिला, लेकिन झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। कांग्रेस की झूठ की राजनीति की तब पोल भी खुल गई, जब कांग्रेस संविधान बचाने का दावा करने के साथ ही आपातकाल के स्मरण पर अपनी आपत्ति जताने लगी। ध्यान रहे संविधान तब खतरे में पड़ा था जब 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी संसद सदस्यता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया था। आपातकाल के दौरान विपक्ष और मीडिया का जमकर उत्पीड़न किया गया। इससे भी खराब बात यह हुई कि संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया गया। यह हैरानी की बात है कि जिस कांग्रेस को आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों और संविधान से की गई छेड़छाड़ को इंदिरा गांधी की एक बड़ी राजनीतिक भूल के तौर पर देखना चाहिए था, वह उसका दबे-छिपे स्वरों में बचाव कर रही। उसने पहले लोकसभा अध्यक्ष की ओर से आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर हंगामा किया और फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल की चर्चा का भी विरोध किया।

कांग्रेस आपातकाल को लेकर किस तरह चोरी और सीनाजोरी वाले रवैये का परिचय दे रही है, इसका पता लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव लाने के फैसले का राहुल गांधी की ओर से विरोध करना रहा। अच्छा तो यह होता कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा साबित हुए आपातकाल को गलत ठहराती। यदि वह ऐसा करने का साहस नहीं जुटा सकी तो अच्छा होता कि वह आपातकाल के स्मरण पर मौन साधे रहती। आपातकाल के स्मरण पर कांग्रेस ने जिस तरह अपनी आपत्ति जताई, उससे यह और भी आवश्यक हो जाता है कि आपातकाल को कभी भूला नहीं जाना चाहिए। आखिर कोई दल आपातकाल के काले कारनामों के स्मरण का विरोध करते हुए यह दावा कैसे कर सकता है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है? कांग्रेस ने अपने रवैये से यही साबित किया कि उसके नेता जिस संविधान की प्रतियां लहरा रहे हैं, उसके प्रति उनके मन में कोई आदर भाव नहीं।

कांग्रेस इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया, उसका उसके ही कुछ सहयोगी दलों ने समर्थन किया। उनके लिए इस प्रस्ताव का विरोध करना संभव ही नहीं था, क्योंकि आपातकाल के दौरान उनके भी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को यह आभास होना चाहिए कि तमाम प्रयासों के बाद भी वह 99 सीटें ही हासिल कर सकी है, जबकि भाजपा ने दस साल सत्ता में रहने के बाद भी 240 के आंकड़े को छू लिया। अब जब कांग्रेस को विपक्षी दल का दर्जा हासिल हो गया है, तब फिर अच्छा यह होगा कि वह संसदीय कार्यवाही के संचालन और देश के विकास में सकारात्मक योगदान दे।

response@jagran.com

चिंतन की तलाश में भटकते चिंतक

हास्य-व्यंग्य

अतुल कुमार राय

बहुत सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि आस-पास का माहौल ही मौलिक चिंतन लायक नहीं है

चिंतक जी के पास एक छोटी-सी सरकारी नौकरी थी। जहां सरकार उनको काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपना काम दूसरे से करवाने के लिए पैसे दे रही थी और चिंतक जी का जीवन मजे में कट रहा था। एक दोपहर चिंतक जी के एक शुभचिंतक मित्र उनसे मिलने सरकारी कार्यालय पधारे और गर्मी से नहीं, बल्कि चिंतक जी की आराम की नौकरी से जलते हुए बोले, 'भाई साहब, सातों जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है, तब जाकर आदमी को आप जैसी आराम की नौकरी मिलती है। कहिए तो एक नेक सलाह दूं?' चिंतक जी ने बेमुरव्वत भरे लहजे में पान खाकर कहा, 'पहली बात तो यह है कि कार्यालय में हम किसी की सलाह नहीं मानते हैं, पर आप ठहरे शुभचिंतक आदमी इसलिए आपको बोलने की अनुमति देता हूं।' शुभचिंतक जी ने कहा, 'प्रिय चिंतक, आप इस तरह से कार्यालय की कुर्सी पर निकम्मे की तरह बैठकर सरकार का बजट क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस खाली समय का उपयोग बौद्धिक चिंतन-मनन में कीजिए। देश को आपको बड़ी जरूरत है। देश रसातल में जा रहा है।'

शुभचिंतक जी द्वारा दिया गया चिंतन-मनन का यह विचार बड़ा ही मौलिक और क्रांतिकारी था। हाथ के इशारे से कार्यालय का हर काम करने वाले चिंतक जी ने सिगरेट बुझाकर झट से पूछा, 'तो बताओ मैं किस चीज का चिंतन करूं?' शुभचिंतक जी ने बताया, 'गुरु, आप ठहरे ज्ञानी आदमी। अपने ज्ञान को सिगरेट के धुएं में उड़ाकर देश की हवा और आसपास के लोगों के फेफड़े खराब करना बंद कीजिए और ज्ञान का धुआं उड़ाइए। देखिए कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। महंगाई रोकने से नहीं रुक रही है। नेता तिकड़मबाजी में व्यस्त हैं, अफसर जुगाड़ में। इस कठिन समय में आप आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा?'

चिंतक जी ने अपनी कुर्सी थोड़ी आगे खिसका ली और पूछा, 'यह सब तो ठीक है गुरु, पर मुझे चिंतन करने के लिए क्या करना होगा?' शुभचिंतक जी ने कहा, 'भीड़ से दूर एकांत में बैठकर मनन करना होगा। अपने मौलिक विचार हर कहीं और खासकर एक्स, फेसबुक आदि पर रखने होंगे।' चिंतक जी ने कहा, 'लेकिन मुझे तो ये सब प्लेटफार्म चलाने नहीं आते। मैंने तो अपने खाते तक नहीं बना रखे।' शुभचिंतक जी ने कहा, 'कोई बात नहीं, जिनको साइकिल चलानी नहीं आती, वे सरकार तक चला रहे हैं। मैं आपका इंटरनेट मीडिया चला लूंगा। आप बस चिंतन पर फोकस कीजिए।'

शुभचिंतक मित्र की इस सलाह के बाद चिंतक जी के ज्ञान चक्षु खुल गए। घर लौटे तो देखा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ली हुईं तमाम डिग्रियां, मेडल, फेलोशिप और पुरस्कार रो रहे हैं। किताबें तो खुलने के इंतजार में धूल फांककर मुरझा गई हैं और पूछ रही हैं कि हे चिंतक, हमारा अंतिम संस्कार अपने ही साथ करोगे या पहले करोगे? चिंतक जी को अपनी बौद्धिक संपदा का हश्र देखकर सचमुच रोना आ गया। ऐसा लगा सरकारी नौकरी की टूटी कुर्सी ने सच में उनके बौद्धिक चश्मे को तोड़ दिया है। आलस्य-प्रमाद और भौतिकवादी जीवन ने उन्हें आत्मकेंद्रित बना दिया है, लेकिन अब नहीं। अब चिंतन करना होगा, देश बदलना होगा।

चिंतक जी चिंतन की तलाश में देर रात तक बालकनी में टहले फिर भी चिंतन न उपजा। उसके बाद छत पर टहले, फिर भी कोई मौलिक विचार न आया। अलबत्ता पत्नी ने जरूर देख लिया और अपना पत्नी धर्म निभाते हुए ऊंची आवाज में ताना मारा, 'आपको घर की चिंता छोड़कर देश की इतनी ही चिंता है तो हिमालय क्यों नहीं चले जाते हैं?' पत्नी के तानों की त्वरा देखकर चिंतक जी का कलेजा कांप गया। वह हिमालय जाने के बजाय सीधे बेडरूम में आ गए। तब समझ में आया कि उनके आस-पास का माहौल ही मौलिक चिंतन लायक नहीं है। इस उबाऊ माहौल में कहां से मौलिक विचार आएंगे? अगर चिंतन करना है तो माहौल को ढंग का बनाना पड़ेगा। तभी मौलिक विचार आएंगे। फिर वह ढंग का माहौल बनाने निकल पड़े।

response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर दर्शन

धर्मग्रंथों में देवता और दानव, दोनों का उल्लेख है। अधिकांशतः लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, व्रत-उपवास रखते हैं एवं यज्ञ-अनुष्ठान आदि भी करते रहते हैं। कभी-कभी बहुत से लोग धर्म क्षेत्र के विशेषज्ञों, महात्माओं से यह इच्छा भी प्रकट करते हैं कि क्या भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है? इस बारे में अलग-अलग तरह के आश्वासन दिए जाते हैं। बोध-कथाओं के जरिये धर्मगुरु लोगों को अलग-अलग तरीके से समझाते और संतुष्ट करते हैं।

वैसे देवी-देवता के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु, महादेव, मां काली यदि सच में पूजा-पाठ के दौरान आ जाएं तो उपासक खुद ही थर-थर कांपने लगेगा। भगवान के किए गए कार्यों को अपने जीवन में अपना कर खुद भगवान का दर्जा हासिल करना धर्मग्रंथों का मूल उद्देश्य है। श्रीराम कथा में प्रसंग है कि भगवान श्रीराम जन्म लेने के बाद जैसे ही अपना सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुजी रूप माता कौशल्या को दिखाते हैं तो वह घबरा-सी गईं और तत्काल उनसे शिशु रूप धारण करने की प्रार्थना करने लगीं। भगवान श्रीराम धर्मग्रंथों में वर्णित अनेक राजाओं की तरह ही सामान्य राजा ही रह जाते यदि वह वनवास के लिए न जाते। प्रायः यह कहा जाता है, 'श्रीराम वन जाकर बन गए।'

वस्तुतः कोई भी अपने कार्यों से भगवान बन जाता है और दैत्य भी बन जाता है। गौतम बुद्ध ने मानवता की सेवा करने के लिए ऐश्वर्यपूर्ण राजमहल छोड़ दिया। इसके बाद अपने आचरण से न जाने कितने दैत्य प्रवृत्ति के लोगों को देव-श्रेणी में खड़ा कर दिया। कोई भी व्यक्ति सड़क पर घायल व्यक्ति को जब अस्पताल पहुंचाकर उसका जीवन बचाता है तब उस क्षण वह जीवनदाता की श्रेणी में तो आ ही जाता है। इसलिए मानवता की सेवा कर देवस्वरूप हासिल करना ज्यादा सरल और सहज मार्ग है।

सलिल पांडेय

तथ्य-कथ्य — लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (1990 के बाद से अब तक)

राजीव गांधी	अटल बिहारी वाजपेयी	शरद पवार	सोनिया गांधी	लालकृष्ण आडवाणी	सुषमा स्वराज	राहुल गांधी
(दिसंबर 1989 - दिसंबर 1990)	(जून 1997 - दिसंबर 1997)	(मार्च 1998 - अप्रैल 1999)	(अक्टूबर 1999 - फरवरी 2004)	(मई 2004 - दिसंबर 2009)	(दिसंबर 2009 - मई 2014)	(जून 2024- ...)

भूलने में कुछ वक्त तो लगेगा

कुछ दौर ऐसे होते हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन दिनों कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। वैसे तो अब उन्हें केंद्र सरकार में बड़ा पद मिला गया है। उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन अभी भी वह बात-बात में मुख्यमंत्री का जिक्र कर ही जाते हैं। हाल में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (आइसीएआर) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते समय वह खुद को मुख्यमंत्री बोल गए। हालांकि तुरंत ही मामा ने अपनी इस गलती को सुधारा और ठहाका लगाते हुए कहा कि 'चार बार मुख्यमंत्री रहा हूं, ऐसे में कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में। वहां भी हमें यह गुमान नहीं था कि हम सब कुछ जानते हैं। यहां भी नहीं है। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सभी विशेषज्ञों की सूची तैयार करवा रहे हैं। जल्द ही सभी से मिलेंगे।'

बारिश में माननीय

दिल्ली में रिकार्ड बारिश ने आम दिल्लीवासियों को परेशान तो किया ही, सांसदों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लुटियंस जोन में स्थित कई सांसदों के

राजरंग

घरों में पानी भर गया, जिसकी शिकायत वे संसद के गलियारे में एक-दूसरे से करते नजर आए। सपा सांसद राम गोपाल यादव के घर के बाहर ऐसी स्थिति थी कि उन्हें उनके गार्डों ने हाथ से उठा कर गाड़ी में बैठाया। शशि थरूर भी यह शिकायत करते दिखे कि उनके घर का सारा सामान गीला हो गया। थरूर और उनके साथ कुछ कांग्रेसी सांसदों ने सदन के गलियारे में भाजपा के कुछ सांसदों को घेर लिया और उनसे शिकायत करने लगे कि कैसे पहली बारिश में ही दिल्ली डूब रही है, क्या इंतजाम है आप लोगों का? भाजपा सदस्यों ने भी चुटकी ली कि यह तो 'आप' का काम है। दिल्ली में सरकार तो आप की ही है।

अबकी बार कितना पार

लोकसभा चुनाव में अबकी बार 400 पार के लक्ष्य से काफी पीछे रह जाने के बाद भाजपा में सदस्यता अभियान के लक्ष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 17 करोड़ वोट मिले थे और इसके बाद चले सदस्यता अभियान में वह 11 करोड़ सदस्य बनाने में सफल रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 22.90 करोड़ वोट मिले थे और उसके बाद पार्टी 18 करोड़ सदस्य बनाने में सफल रही थी। 2024 में भाजपा पिछली बार से महज 70 लाख अधिक वोट पाने में सफल रही है। भाजपा के संगठन चुनावों के पहले जुलाई से सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और इसकी तारीखों का एलान जल्द किया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस बार कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित करती है और उसे कितना हासिल कर पाती है।

हम साथ-साथ हैं

लोजपा (आर) के सांसदों की एकता इस बार चर्चा का विषय है। इस बार लोकसभा में चिराग पासवान समेत इसके पांच सदस्य जीतकर आए हैं। संसद परिसर में पांचों साथ-साथ दिखते हैं। सदन में सब एक साथ जाते हैं। मंत्री होने के चलते चिराग सदन में भले ही अलग बैठते हैं, किंतु बाहर आते समय फिर एक साथ हो जाते हैं। मीडिया से बातचीत में भी अलग नहीं होते। पिछली बार लोकसभा में लोजपा के छह सदस्य थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक एक नहीं रह पाए थे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने बड़ा झटका देते हुए पांच सांसदों को तोड़कर अलग दल बना लिया था, किंतु इस बार आम चुनाव के पहले से ही चिराग ज्यादा सजग-सतर्क नजर आ रहे हैं। टिकट बंटवारे में भी ऐसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी थी, जो टूट-फूट की राजनीति से अलग रह सकें।

पोस्ट

बिहार में एक और पुल ढह गया, लेकिन किसी को परवाह नहीं और कोई जवाबदेह नहीं है। क्या ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों/मंत्रियों के बीच कोई साठगांठ है? इन पुलों के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री की खराब गुणवत्ता और खराब रखरखाव के कारण करदाताओं के करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे हैं।

मारिया शकील@maryashakil

जिंदगी की कीमत क्या है? आप सड़क पर चल रहे हैं और फ्लाई ओवर गिर जाता है। आप पुल पार कर रहे हैं और पुल गिर जाता है। आपको यह भरोसा नहीं है कि कौन-सी होर्डिंग कब आपके सिर पर चलते-फिरते गिर जाए। ऐसी घटनाओं का कोई अंत नहीं है।

ऋतिका चंदोला@RitikaChandola

भारत का विरोधाभास देखिए- चंद्रमा पर यान उतारने में सक्षम, लेकिन अंग्रेजों के जाने के लगभग 80 वर्ष बाद भी जल निकासी जैसी बुनियादी चीज में महारत हासिल करने में असमर्थ है।

सदानंद धूमे@dhume

सपा की मांग है कि सेंगोल की जगह संसद में संविधान की बड़ी सी मूल प्रति स्थापित की जाए। कर दो, लेकिन संविधान की मूल प्रति में न सेक्युलर शब्द है, न सोशलिस्ट।

दिव्य कुमार सोती@DivyaSoti

जनपथ

पहली बारिश में धंसा दिखे अयोध्या धाम,
कितना भ्रष्टाचार है! देख रहे प्रभु राम।
देख रहे प्रभ राम दिखे गड्ढा ही गड्ढा,
जहां होय निर्माण वहीं खाने का अड्डा!
धुआंधार बरसात देखकर जनता दहली,
अपना रूप दिखाय गई जब बारिश पहली।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 79

****

दैनिक जागरण

सुख व्यक्ति के अहंकार और दुख धैर्य की परीक्षा लेता है

नए आपराधिक कानून

अंग्रेजों के जमाने की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने और न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर अमल की तैयारी के बीच विरोध के स्वर उभरने पर हैरानी नहीं। अपने देश में सदैव ऐसा ही होता है। पिछले कुछ समय से ऐसा कुछ ज्यादा ही होने लगा है। सुधार के हर कदम का विरोध किया जाता है। कई बार तो उस कदम के गुण-दोष का संज्ञान लिए बिना। ऐसा विरोध के लिए विरोध की राजनीति के तहत किया जाता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि जहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। विपक्षी दलों के कुछ और नेताओं ने भी इन नए आपराधिक कानूनों को लागू किए जाने का विरोध करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। विरोध के लिए वही घिसे-पिटे तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे यह कि नए कानूनों को लागू करने के पहले पूरी तैयारी नहीं की गई है। स्पष्ट है कि यह तर्क देने वाले जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि इन कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद से लाखों पुलिस कर्मियों समेत जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं।

इससे इन्कार नहीं कि तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के क्रम में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो हर नई व्यवस्था पर अमल करते समय होता है। जितना बड़ा बदलाव होता है, चुनौतियां भी उतनी ही अधिक होती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि चुनौतियों से बचने के लिए पुरानी और कष्टकारी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। कोई भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि अंग्रेजी सत्ता की ओर से बनाए गए आपराधिक कानून न्याय देने में सहायक नहीं बन रहे। छोटे-छोटे मामलों में भी न्याय पाने में आवश्यकता से अधिक समय और संसाधन खपाना पड़ता है। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनमें से कुछ का तो अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिनके बारे में अभी किसी को आभास न हो। ऐसे में सरकार को आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ताकि लोगों को समय पर सुगम तरीके से न्याय मिल सके। इन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का मूल उद्देश्य भी यही है। नए आपराधिक कानूनों के लागू करने के क्रम में यह प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा कि वे न्यायिक तंत्र के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी छवि को सुधारने में सक्षम होते हैं या नहीं?

शिक्षकों की जिम्मेदारी

गर्मी की छुट्टी के बाद उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूल खुल तो गए हैं, लेकिन विधिवत शिक्षण कार्य एक जुलाई से शुरू होगा और बच्चे भी आने लगेंगे। किसी भी विद्यालय में बच्चों का मन तभी रमेगा जबकि वहां पर उनकी रुचि के अनुकूल वातावरण हो और उनकी आवश्यकता की सभी चीजें उपलब्ध हों। ऐसा न होने पर विद्यालय से उनका मन उचाट होने लगता है और ड्राप आउट बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। इसलिए शिक्षकों को व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदारी लेते हुए बच्चों की पढ़ाई और अन्य सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। अधिकारियों ने यह निर्देश तो जारी कर दिया है कि दो दिनों के भीतर साफ-सफाई और रंगरोगन आदि करा लिया जाए, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी देखना होगा कि विद्यालयों ने ऐसा किया है या नहीं। सबसे बड़ी जरूरत तो पुस्तकों की ही है। यह विडंबना ही है कि सत्र का समय निश्चित होने के बाद भी कक्षा एक और दो के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। स्कूल में बच्चों के पास किताबें ही नहीं होंगी तो वे पढ़ेंगे क्या, यह गंभीर प्रश्न है। प्रदेश में कुल 1.34 लाख परिषदीय विद्यालय हैं जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। गांव-गिरांव के कई विद्यालय भवनों की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिनकी मरम्मत अविलंब कराई जानी चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह की परेशानियों के चलते हर साल ही बड़ी संख्या में छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं और इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग को अभियान चलाना पड़ता है। बच्चे विद्यालय में रुके रहें, इसके लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व विकास की नींव तैयार करती है इसलिए ग्राम प्रधानों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे गांव के हर बच्चे को स्कूल भेजें। नवप्रवेशी छात्रों के लिए इस तरह का वातावरण बनाया जाए कि उनकी विद्यालय आने में रुचि लगातार बनी रहे। यह जिम्मेदारी शिक्षकों की है।

विपक्ष की अनावश्यक आक्रामकता

संजय गुप्त

आखिर कोई दल आपातकाल के स्मरण का विरोध करते हुए यह दावा कैसे कर सकता है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है?

अवधेश राजपूत

नई लोकसभा के गठन के साथ ही नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार की तीसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। इस सरकार का नेतृत्व संभालने के पहले से कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार बनी, उसे बहुमत हासिल नहीं है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है कि जनता ने भाजपा के चार सौ पार के नारे को ठुकरा दिया, इसलिए यह प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक और राजनीतिक हार है। यह सही है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस का यह दावा भी तो सही नहीं साबित हुआ कि उसके नेतृत्व वाले गठबंधन यानी आइएनडीआइए को 295 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस नेता इस तथ्य की अनदेखी कर रहे हैं कि भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ बहुमत हासिल किया। भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर वैसे ही चुनाव लड़ा था, जैसे कांग्रेस ने अपने घटक दलों के साथ।

चूंकि कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले लगभग दोगुनी सीटें मिली हैं, इसलिए उसका उत्साहित होना समझ में आता है, लेकिन आखिर वह यह माहौल क्यों बना रही है कि लोकसभा चुनावों में आइएनडीआइए की जीत हुई और राजग अर्थात एनडीए की हार? अपने संख्याबल में वृद्धि के चलते कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, लेकिन यह जताना उसकी एक राजनीतिक भूल है कि उसने भाजपा को मात दे दी है। यह माहौल बनाने में वह राहुल गांधी भी जुटे हुए हैं, जो लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष बन गए हैं। यदि मोदी की हार हुई है तो फिर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों स्वीकार कर लिया? लगता है राहुल गांधी यह मानकर चल रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जितना अधिक हमलावर होंगे और राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए आक्रामक बने रहेंगे तो इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। यदि राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यही रवैया रहा तो इसके आसार कम ही हैं कि वह अपनी इस नई भूमिका में कोई सकारात्मक राजनीति कर सकेंगे और सरकार को रचनात्मक सहयोग देने में कोई सार्थक भूमिका निभा सकेंगे।

जैसी आशंका थी, नई लोकसभा का कार्यकाल विपक्ष की आक्रामकता के साथ शुरू हुआ। विपक्ष का आक्रामक रवैया लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी दिख रहा है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सभापति के आसन के समक्ष पहुंच गए। लोकसभा में भी विपक्ष ने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। इससे आने वाले दिनों में संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल के आसार नहीं। इसकी एक झलक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के संबोधन के समय भी मिली। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के उन बिंदुओं पर भी आपत्ति जताई, जिन पर आपत्ति का कोई मतलब नहीं बनता था। सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव की झलक तब भी मिली, जब लोकसभा स्पीकर के चुनाव की नौबत आ गई। यह नौबत कांग्रेस के अनावश्यक आक्रामक रवैये के कारण ही आई। नई लोकसभा में नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विपक्षी नेताओं ने जिस तरह संविधान की प्रतियां लहराते हुए उसे बचाने का नैरेटिव गढ़ा, उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संविधान को कोई खतरा नहीं।

यह ठीक है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने यह जो झूठा नैरेटिव गढ़ा कि यदि राजग को 400 सौ से अधिक सीटें मिल गईं तो भाजपा संविधान बदल देगी, उससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिला, लेकिन झूठ की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। कांग्रेस की झूठ की राजनीति की तब पोल भी खुल गई, जब कांग्रेस संविधान बचाने का दावा करने के साथ ही आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति जताने लगी। संविधान तब खतरे में पड़ा था जब 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी संसद सदस्यता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया था। विपक्ष और मीडिया का जमकर उत्पीड़न किया गया। इससे भी खराब बात यह हुई कि संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया गया। यह हैरानी की बात है कि जिस कांग्रेस को आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों और संविधान से की गई छेड़छाड़ को इंदिरा गांधी की एक बड़ी राजनीतिक भूल के तौर पर देखना चाहिए था, वह उसका दबे-छिपे स्वरों में बचाव कर रही। उसने पहले लोकसभा अध्यक्ष की ओर से आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर हंगामा किया, फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल की चर्चा का भी विरोध किया।

कांग्रेस आपातकाल को लेकर किस तरह चोरी और सीनाजोरी वाले रवैये का परिचय दे रही है, इसका पता लोकसभा अध्यक्ष की ओर से सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव लाने के फैसले का राहुल गांधी की ओर से विरोध करना रहा। अच्छा तो यह होता कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा साबित हुए आपातकाल को गलत ठहराती। यदि वह ऐसा करने का साहस नहीं जुटा सकी तो अच्छा होता कि वह आपातकाल के स्मरण पर मौन साधे रहती। आपातकाल के स्मरण पर कांग्रेस ने जिस तरह अपनी आपत्ति जताई, उससे यह और भी आवश्यक हो जाता है कि आपातकाल को कभी भूला नहीं जाना चाहिए। आखिर कोई दल आपातकाल के काले कारनामों के स्मरण का विरोध करते हुए यह दावा कैसे कर सकता है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है? कांग्रेस ने अपने रवैये से यही साबित किया कि उसके नेता जिस संविधान की प्रतियां लहरा रहे हैं, उसके प्रति उनके मन में कोई आदर भाव नहीं।

कांग्रेस इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया, उसका उसके ही कुछ सहयोगी दलों ने समर्थन किया। उनके लिए इस प्रस्ताव का विरोध करना संभव ही नहीं था, क्योंकि आपातकाल के दौरान उनके भी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को यह आभास होना चाहिए कि तमाम प्रयासों के बाद भी वह 99 सीटें ही हासिल कर सकी है, जबकि भाजपा ने दस साल सत्ता में रहने के बाद भी 240 के आंकड़े को छू लिया। अब जब कांग्रेस को विपक्षी दल का दर्जा हासिल हो गया है, तब फिर अच्छा यह होगा कि वह संसदीय कार्यवाही के संचालन और देश के विकास में सकारात्मक योगदान दे।

response@jagran.com

चिंतन की तलाश में भटकते चिंतक

हास्य-व्यंग्य

अतुल कुमार राय

बहुत सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि आस-पास का माहौल ही मौलिक चिंतन लायक नहीं है

चिंतक जी के पास एक छोटी-सी सरकारी नौकरी थी। जहां सरकार उनको काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपना काम दूसरे से करवाने के लिए पैसे दे रही थी और चिंतक जी का जीवन मजे में कट रहा था। एक दोपहर चिंतक जी के एक शुभचिंतक मित्र उनसे मिलने सरकारी कार्यालय पधारे और गर्मी से नहीं, बल्कि चिंतक जी की आराम की नौकरी से जलते हुए बोले, 'भाई साहब, सातों जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है, तब जाकर आदमी को आप जैसी आराम की नौकरी मिलती है। कहिए तो एक नेक सलाह दूं?' चिंतक जी ने बेमुरव्वत भरे लहजे में पान खाकर कहा, 'पहली बात तो यह है कि कार्यालय में हम किसी की सलाह नहीं मानते हैं, पर आप ठहरे शुभचिंतक आदमी इसलिए आपको बोलने की अनुमति देता हूं।' शुभचिंतक जी ने कहा, 'प्रिय चिंतक, आप इस तरह से कार्यालय की कुर्सी पर निकम्मे की तरह बैठकर सरकार का बजट क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस खाली समय का उपयोग बौद्धिक चिंतन-मनन में कीजिए। देश की आपको बड़ी जरूरत है। देश रसातल में जा रहा है।'

शुभचिंतक जी द्वारा दिया गया चिंतन-मनन का यह विचार बड़ा ही मौलिक और क्रांतिकारी था। हाथ के इशारे से कार्यालय का हर काम करने वाले चिंतक जी ने सिगरेट बुझाकर झट से पूछा, 'तो बताओ मैं किस चीज का चिंतन करूं?' शुभचिंतक जी ने बताया, 'गुरु, आप ठहरे ज्ञानी आदमी। अपने ज्ञान की सिगरेट के धुएं में उड़ाकर देश की हवा और आसपास के लोगों के फेफड़े खराब करना बंद कीजिए और ज्ञान का धुआं उड़ाइए। देखिए कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। महंगाई रोकने से नहीं रुक रही है। नेता तिकड़मबाजी में व्यस्त हैं, अफसर जुगाड़ में। इस कठिन समय में आप आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा?'

चिंतक जी ने अपनी कुर्सी थोड़ी आगे खिसका ली और पूछा, 'यह सब तो ठीक है गुरु, पर मुझे चिंतन करने के लिए क्या करना होगा?' शुभचिंतक जी ने कहा, 'भीड़ से दूर एकांत में बैठकर मनन करना होगा। अपने मौलिक विचार हर कहीं और खासकर एक्स, फेसबुक आदि पर रखने होंगे।' चिंतक जी ने कहा, 'लेकिन मुझे तो ये सब प्लेटफार्म चलाने नहीं आते। मैंने तो अपने खाते तक नहीं बना रखे।' शुभचिंतक जी ने कहा, 'कोई बात नहीं, जिनको साइकिल चलानी नहीं आती, वे सरकार तक चला रहे हैं। मैं आपका इंटरनेट मीडिया चला लूंगा। आप बस चिंतन पर फोकस कीजिए।'

शुभचिंतक मित्र की इस सलाह के बाद चिंतक जी के ज्ञान चक्षु खुल गए। घर लौटे तो देखा कि तमाम डिग्रियां, मेडल, फेलोशिप और पुरस्कार रो रहे हैं। किताबें तो खुलने के इंतजार में धूल फांककर मुरझा गई हैं और पूछ रही हैं कि हे चिंतक, हमारा अंतिम संस्कार अपने ही साथ करोगे या पहले करोगे? चिंतक जी को अपनी बौद्धिक संपदा का हश्र देखकर रोना आ गया। ऐसा लगा सरकारी नौकरी की टूटी कुर्सी ने सच में उनके बौद्धिक चश्मे को तोड़ दिया है। आलस्य-प्रमाद और भौतिकवादी जीवन ने उन्हें आत्मकेंद्रित बना दिया है, लेकिन अब नहीं। अब चिंतन करना होगा, देश बदलना होगा।

चिंतक जी चिंतन की तलाश में देर रात तक बालकनी में टहले फिर भी चिंतन न उपजा। छत पर टहले, फिर भी कोई मौलिक विचार न आया। अलबत्ता पत्नी ने जरूर देख लिया और अपना पत्नी धर्म निभाते हुए ऊंची आवाज में ताना मारा, 'आपको घर की चिंता छोड़कर देश की इतनी ही चिंता है तो हिमालय क्यों नहीं चले जाते हैं?' पत्नी के तानों की त्वरा देखकर चिंतक जी का कलेजा कांप गया। वह हिमालय जाने के बजाय सीधे बेडरूम में आ गए। तब समझ में आया कि उनके आस-पास का माहौल ही मौलिक चिंतन लायक नहीं है। इस उबाऊ माहौल में कहां से मौलिक विचार आएंगे? अगर चिंतन करना है तो माहौल को ढंग का बनाना पड़ेगा। तभी मौलिक विचार आएंगे।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (1990 के बाद से अब तक)

राजीव गांधी	अटल बिहारी वाजपेयी	शरद पवार	सोनिया गांधी	लालकृष्ण आडवाणी	सुषमा स्वराज	राहुल गांधी
(दिसंबर 1989-दिसंबर 1990)	(जून 1997-दिसंबर 1997)	(मार्च 1998-अप्रैल 1999)	(अक्टूबर 1999-फरवरी 2004)	(मई 2004-दिसंबर 2009)	(दिसंबर 2009-मई 2014)	(जून 2024-...)

ऊर्जा

ईश्वर दर्शन

धर्मग्रंथों में देवता और दानव, दोनों का उल्लेख है। अधिकांशतः लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, व्रत-उपवास रखते हैं एवं यज्ञ-अनुष्ठान आदि भी करते रहते हैं। कभी-कभी बहुत से लोग धर्म क्षेत्र के विशेषज्ञों, महात्माओं से यह इच्छा भी प्रकट करते हैं कि क्या भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है? इस बारे में अलग-अलग तरह के आश्वासन दिए जाते हैं। बोध-कथाओं के जरिये धर्मगुरु लोगों को समझाते और संतुष्ट करते हैं।

वैसे देवी-देवता के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु, महादेव, मां काली यदि सच में पूजा-पाठ के दौरान आ जाएं तो उपासक खुद ही थर-थर कांपने लगेगा। भगवान के किए गए कार्यों को अपने जीवन में अपना कर खुद भगवान का दर्जा हासिल करना धर्मग्रंथों का मूल उद्देश्य है। श्रीराम कथा में प्रसंग है कि भगवान श्रीराम जन्म लेने के बाद जैसे ही अपना सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुजी रूप माता कौशल्या को दिखाते हैं तो वह घबरा-सी गईं और तत्काल उनसे शिशु रूप धारण करने की प्रार्थना करने लगीं। भगवान श्रीराम धर्मग्रंथों में वर्णित अनेक राजाओं की तरह ही सामान्य राजा ही रह जाते यदि वह वनवास के लिए न जाते। प्रायः यह कहा जाता है, 'श्रीराम वन जाकर बन गए।'

वस्तुतः कोई भी अपने कार्यों से भगवान बन जाता है और दैत्य भी बन जाता है। गौतम बुद्ध ने मानवता की सेवा करने के लिए ऐश्वर्यपूर्ण राजमहल छोड़ दिया। इसके बाद अपने आचरण से न जाने कितने दैत्य प्रवृत्ति के लोगों को देव-श्रेणी में खड़ा कर दिया। कोई भी व्यक्ति सड़क पर घायल व्यक्ति को जब अस्पताल पहुंचाकर उसका जीवन बचाता है तब उस क्षण वह जीवनदाता की श्रेणी में तो आ ही जाता है। इसलिए मानवता की सेवा कर देवस्वरूप हासिल करना ज्यादा सरल और सहज मार्ग है।

सलिल पांडेय

समुद्र की चट्टानों में जमा होगा कार्बन

मुकुल व्यास

समुद्र तल पर स्थित बेसाल्ट की चट्टानों के भंडार में कार्बन डाईआक्साइड को जमा करने की क्षमता है

कुछ विज्ञानियों ने जलवायु संकट का समाधान समुद्र तल की चट्टानों में खोजा है। उनका मानना है कि समुद्र तल पर स्थित बेसाल्ट की चट्टानों के भंडार में कार्बन डाईआक्साइड को जमा करने की क्षमता है। ये ज्वालामुखीय चट्टानें हमारे वायुमंडल से गर्मी को कैद करने वाली गैसों को हटाने में मदद कर सकती हैं। विज्ञानी समुद्री तटों के निकट फ्लोटिंग रिग बनाना चाहते हैं। ये रिग समुद्र तल से तेल निकालने के बजाय उसमें कार्बन डाईआक्साइड प्रविष्ट करेंगे। अपने स्वयं के विंड टर्बाइनों द्वारा संचालित फ्लोटिंग प्लेटफार्म आकाश या समुद्री जल से कार्बन डाईआक्साइड को खींचेंगे और उसे समुद्र तल में पंप करेंगे। इस परियोजना को 'सालिड कार्बन' कहते हैं। अगर यह परियोजना उम्मीद के मुताबिक काम करती है तो तल में प्रविष्ट कार्बन डाईआक्साइड हमेशा के लिए समुद्र के तल पर एक चट्टान बन जाएगी। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कनाडा के विज्ञानियों ने कहा कि इससे कार्बन भंडारण बहुत टिकाऊ और सुरक्षित हो जाएगा। इस तकनीक से अन्य भंडारण तकनीकों की तरह हमें कार्बन के वायुमंडल में वापस लौटने और वैश्विक तापमान वृद्धि के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया भर में बेसाल्ट चट्टानें पृथ्वी के समस्त जीवाश्म ईंधन से निकलने वाले कार्बन को स्थाई रूप से जमा कर सकती हैं।

इस तरह की तकनीक को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि जीवाश्म ईंधन को अंधाधुंध तरीके से जलाना सुरक्षित है। फिर भी विज्ञानियों का कहना है कि कुछ रिग ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कनाडा के पश्चिमी तट से दूर वैंकूवर द्वीप के पास कैस्केडिया बेसिन में विश्व के 20 साल के कार्बन उत्सर्जन को कैद करने की गुंजाइश है। बेसाल्ट चट्टान अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है। वह धातुओं से भरी होती है, जो आसानी से कार्बन डाईआक्साइड को पकड़ लेती हैं और कार्बोनेट खनिजों का निर्माण करने के लिए रासायनिक रूप से इसके साथ जुड़ जाती हैं। बेसाल्ट भी टूट जाता है और छिद्रपूर्ण हो जाता है, जिससे नए कार्बोनेट के भरने के लिए पर्याप्त जगह बच जाती है। इसके लिए पानी में कार्बन डाईआक्साइड को घोला जाता है। फिर उसे भूमिगत बेसाल्ट चट्टान में इंजेक्ट किया जाता है।

ये समुद्री कार्बन-भंडारण कारखाने बहुत महंगे उपक्रम होंगे, लेकिन यदि हम पृथ्वी को पूर्व-औद्योगिक तापमान पर वापस लाना चाहते हैं तो हमें इसका सहारा लेना पड़ सकता है। सालिड कार्बन उन बुनियादी तात्कालिक उपायों का विकल्प नहीं है, जिनकी दुनिया भर के जलवायु विशेषज्ञ मांग कर रहे हैं। इन उपायों में जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा में बदलना और खाद्य प्रणालियों के कार्बन उत्सर्जन को कम करना शामिल है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

भूलने में कुछ वक्त तो लगेगा

कुछ दौर ऐसे होते हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन दिनों कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। वैसे तो अब उन्हें केंद्र सरकार में बड़ा पद मिला गया है। उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन अभी भी वह बात-बात में मुख्यमंत्री का जिक्र कर ही जाते हैं। हाल में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम को संबोधित करते समय वह खुद को मुख्यमंत्री बोल गए। हालांकि तुरंत ही मामा ने अपनी इस गलती को सुधारा और ठहाका लगाते हुए कहा कि 'चार बार मुख्यमंत्री रहा हूं, ऐसे में कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में। वहां भी हमें यह गुमान नहीं था कि हम सब कुछ जानते हैं। यहां भी नहीं है। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सभी विशेषज्ञों की सूची तैयार करवा रहे हैं। जल्द ही सभी से मिलेंगे।'

बारिश में माननीय

दिल्ली में रिकार्ड बारिश ने आम दिल्लीवासियों को परेशान तो किया ही, सांसदों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लुटियंस जोन में स्थित कई सांसदों के

राजरंग

घरों में पानी भर गया, जिसकी शिकायत वे संसद के गलियारे में एक-दूसरे से करते नजर आए। सपा सांसद राम गोपाल यादव के घर के बाहर ऐसी स्थिति थी कि उन्हें उनके गार्डों ने हाथ से उठा कर गाड़ी में बैठाया। शशि थरूर भी यह शिकायत करते दिखे कि उनके घर का सारा सामान गीला हो गया। थरूर और उनके साथ कुछ कांग्रेसी सांसदों ने सदन के गलियारे में भाजपा के कुछ सांसदों को घेर लिया और उनसे शिकायत करने लगे कि कैसे पहली बारिश में ही दिल्ली डूब रही है, क्या इंतजाम है आप लोगों का? भाजपा सदस्यों ने भी चुटकी ली कि यह तो 'आप' का काम है। दिल्ली में सरकार तो आप की ही है।

अबकी बार कितना पार

लोकसभा चुनाव में अबकी बार 400 पार के लक्ष्य से काफी पीछे रह जाने के बाद भाजपा में सदस्यता अभियान के लक्ष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 17 करोड़ वोट मिले थे और इसके बाद चले सदस्यता अभियान में वह 11 करोड़ सदस्य बनाने में सफल रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 22.90 करोड़ वोट मिले थे और उसके बाद पार्टी 18 करोड़ सदस्य बनाने में सफल रही थी। 2024 में भाजपा पिछली बार से महज 70 लाख अधिक वोट पाने में सफल रही है। भाजपा के संगठन चुनावों के पहले जुलाई से सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और इसकी तारीखों का एलान जल्द किया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस बार कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित करती है और उसे कितना हासिल कर पाती है।

हम साथ-साथ हैं

लोजपा (आर) के सांसदों की एकता चर्चा का विषय है। इस बार लोकसभा में चिराग पासवान समेत इसके पांच सदस्य जीतकर आए हैं। संसद परिसर में पांचों साथ-साथ दिखते हैं। सदन में एक साथ जाते हैं। मंत्री होने के चलते चिराग सदन में भले ही अलग बैठते हैं, किंतु बाहर आते समय फिर एक साथ हो जाते हैं। मीडिया से बातचीत में भी अलग नहीं होते। पिछली बार लोकसभा में लोजपा के छह सदस्य थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक एक नहीं रह पाए थे। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने बड़ा झटका देते हुए पांच सांसदों को तोड़कर अलग दल बना लिया था, किंतु इस बार आम चुनाव के पहले से ही चिराग ज्यादा सजग-सतर्क नजर आ रहे हैं। टिकट बंटवारे में भी ऐसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी थी, जो टूट-फूट की राजनीति से अलग रह सकें।

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

हेमंत सोरेन की जमानत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और हेमंत कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल से बाहर भी आ गए। भूमि घोटाले के आरोप में उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। जनवरी में ही सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू करने लग गए थे। चुनावों के दौरान वह जेल की दीवारों के पीछे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की तरह चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी। चुनाव बीत गए तब जाकर उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जमानत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि हेमंत सोरेन प्रथम दृष्टया दोषी नहीं हैं।

कोर्ट ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि भानु प्रताप प्रसाद के परिसर से बरामद कई रजिस्टरों और रेवेन्यू रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता (हेमंत सोरेन) या उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है।" "अगर व्यापक संभावनाओं पर भी जाएं तो स्पेसिफिक या अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता शांति नगर, बारागैन, रांची में 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्ज़े में शामिल नहीं लगते और ना ही 'अपराध से की गई आय' को छिपाने में शामिल दिखते हैं।" "किसी भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त ज़मीन के अधिग्रहण और कब्ज़े में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई ज़िक्र नहीं है।" "इस कोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर इस अदालत ने पाया है कि पीएमएलए की धारा 45 की शर्त पूरी करते हुए ये मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है।"

अरविन्द केजरीवाल मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी बीच हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध का मामला कहते आ रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी हेमंत सोरेन ने यही कहा कि एक मनघढ़ंत कहानी बनाकर उन्हें जेल में 5 महीने तक रखा गया। देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन की चम्पई सोरेन सरकार बनी थी। ईडी की अदालत ने हेमंत सोरेन को सदन में उपस्थित होकर चम्पई सोरेन के विश्वासमत में मतदान में भाग लेने की इजाजत दी थी।

न्यायालय की यह टिप्पणियां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईडी इस पर क्या रुख अपनाती है यह देखना अभी बाकी है क्योंकि अरविन्द केजरीवाल मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी बीच हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध का मामला कहते आ रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी हेमंत सोरेन ने यही कहा कि एक मनघढ़ंत कहानी बनाकर उन्हें जेल में 5 महीने तक रखा गया। देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन की चम्पई सोरेन सरकार बनी थी। ईडी की अदालत ने हेमंत सोरेन को सदन में उपस्थित होकर चम्पई सोरेन के विश्वासमत में मतदान में भाग लेने की इजाजत दी थी। चम्पई सोरेन द्वारा रखे गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हेमंत सोरेन ने जो अपनी व्यथा रखी थी वह इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने सदन के भीतर चुनौती दी कि यदि उन पर लगा जमीन हड़पने का आरोप सही सिद्ध हुआ तो वह न केवल राजनीत से संन्यास ले लेंगे बल्कि झारखंड छोड़ कर चले जाएंगे।

ewsPaperPaid

अब सवाल यह है कि क्या ईडी ने जिन आरोपों में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था वह उचित है या अनुचित। इसका फैसला तो अंततः न्यायालय को ही करना है। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसे लेकर झारखंड मुक्ति मर्चा और अन्य सियासी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनावों में पार्टी की कमान सम्भाल रखी थी। ''हेमंत हैं तो हिम्मत है'' का नारा देते हुए कल्पना सोरेन ने पार्टी समर्थकों में जोश भर दिया था। लोकसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 5 सीटें जीतीं जबकि 2019 के चुनावों में कांग्रेस और झामुमो को एक-एक सीट मिली थी। हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद राज्य की राजनीति में सियासी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। हेमंत सोरेन मतदाताओं की सहानुभूति लेने की हर सम्भव कोशिश करेंगे।

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर आदिवासी क्षेत्रों में पड़ता दिखाई दे रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन ने भी हेमंत सोरेन को जमानत देने के आदेश को सत्य की जीत बताया और यहां तक कह दिया कि उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर संगठन जो भी फैसला करेगा वह उन्हें स्वीकार्य होगा, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। इस तरह उन्होंने यह संकेत भी दे दिया है कि हेमंत सोरेन जब चाहे मुख्यमंत्री पद सम्भाल सकते हैं। चम्पई सोरेन को हेमंत सोरेन का अतिविश्वस्त माना जाता है। इस तरह की सम्भावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि हेमंत सोरेन सत्ता से दूर रहकर जनता के बीच विधानसभा चुनावों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय गुजारने पर फोकस करेंगे। हेमंत सोरेन राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वे पूरी ताकत विधानसभा चुनाव में लगाएंगे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी अब एनडीए के सामने जबरदस्त चुनौती पेश करेगी।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

नरबलि और पशुबलि भला किस...

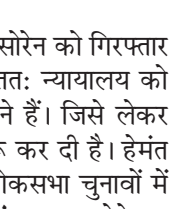

धार्मिकता की आड़ में यहां आज भी आंडबरों की भरमार है,
नरबलि और पशुबलि भला किस महजब के ईश्वर को स्वीकार है,
प्रत्येक समाज के धर्मगुरुओं से बस एक ही गुहार है,
सत्य, अहिंसा, प्रेम, धैर्य का बढ़-चढ़कर कीजिए प्रचार है...!!

नायडू और भाजपा में कैसे बैठा सामंजस्य

नई दिल्ली, (एनटीआई): बड़े कयास लग रहे थे कि इस दफे के लोकसभा स्पीकर चुनाव में चंद्रबाबू नायडू भाजपा की नाक में दम कर देंगे, पर नायडू थे जो भाजपा के समक्ष नतमस्तक थे, न तो उन्होंने केंद्र में किसी भारी-भरकम मंत्रालय की मांग की और न ही अपनी पार्टी के लिए स्पीकर पद ही मांगा। सूत्रों की मानें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बिजनेस संचालित करने वाले गुजरात व तेलुगु बिजनेस लॉबी दोनों की एक राय थी कि नायडू को भाजपा के साथ सामंजस्य बिठा कर काम करना चाहिए। वैसे भी ओडिशा व आंध्र दोनों ही राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस जिन महत्वपूर्ण पोर्ट से जुड़ा है उस पर देश के एक खास औद्योगिक घराने का वर्चस्व है, यह वही बड़े थैलीशाह हैं जो हमेशा से राहुल गांधी के निशाने पर रहे हैं। सनद रहे कि ओडिशा का धामरा, आंध्र का गंगावरम और कृष्णापट्टनम पोर्ट इसी समूह के पास है, वैसे भी ओडिशा के चुनावों को ईस्ट कोस्ट हमेशा से प्रभावित करता रहा है।

● गुजरात व तेलुगु बिजनेस लॉबी चाहती थी कि नायडू को भाजपा के साथ ही सामंजस्य बिठा कर काम करना चाहिए

भाजपा के लिए क्यों अनुत्तरित है महाराष्ट्र का यक्ष प्रश्न

मिर्च मसाला
त्रिदीब रमण
gossipguru.in

'अपना दिन बुझाकर अभी-अभी
तो लौटा हूं तेरे पहलू में
हसरत है कि ये रात जले धू-धू
और एक नया सवेरा हो'

हालिया लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य से जो दंश मिला है भाजपा उससे उबरने की कोशिशों में जुट गई है। भगवा खेमे में एक नई आशा का सूत्रपात हो चुका है, जब से महाराष्ट्र के चुनाव की बागडोर भाजपा चाणक्य अमित शाह ने थाम ली है। राज्य में आने वाले इसी अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव आहूत हैं, सो वक्त कम बचा है, शाह के नेतृत्व में मैराथन तरीके से नई चुनावी रणनीतियों को धार दी जा रही है। सियासी शह-मात की बिसात पर प्यादों को भी उनकी असली औकात बताने की तैयारी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए

भाजपा चाणक्य के निर्देशन में सीट दर सीट जनमत सर्वेक्षण का काम चल रहा है, मुद्दों की फेहरिस्त तैयार की जा रही है, उन्हें लोकल, राज्यवर व नेशनल स्तर पर मार्क किया जा रहा है।

भाजपा से जुड़े भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर कल्याणकारी योजनाओं का मेगा स्वरूप बन कर तैयार है, जिसे विशेष कर युवा, महिला व कृषक वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसी शुक्रवार को पेश राज्य के बजट में भाजपा के इन्हीं इरादों की बानगी दिख जाती है। इस बजट में 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता, गरीब परिवारों को साल में तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, किसानों के बिजली बिल माफी, खेती के लिए 5 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस व युवाओं को 10 हजार रुपए मासिक भत्ता देने जैसी क्रांतिकारी घोषणाएं शामिल हैं। यह और बात है कि इन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने से राज्य के बजट पर 80 हजार करोड़ रुपयों का अतिरिक्त बोझ आएगा, भाजपा पूर्व में भी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे अपनी डूबती उतराती चुनावी नैया पार लगा चुकी है, अब इसी फार्मूले को महाराष्ट्र में भी आजमाने की तैयारी है।

क्या महाराष्ट्र में अकेले चुनाव में जा सकती है भाजपा

भाजपा से जुड़े बेहद भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र को लेकर अब तक पार्टी ने जितने जनमत सर्वेक्षण करवाए हैं उसके नतीजे भगवा पार्टी के लिए किंचित उत्साहजनक नहीं हैं। माहौल लोकसभा चुनाव काल से भी धुंधला नज़र आ रहा है। ऐसे में भाजपा अपनी सहयोगी पार्टियों की अतिरिक्त डिमांड झेलने को तैयार नहीं दिखती। मसलन, अगर बात करें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तो लोकसभा में 7 सीटें जीतने के बाद पार्टी के हौंसले बम-बम हैं, सो अतिरेक उत्साह के घोड़े पर सवार शिंदे भाजपा से अपनी पार्टी के लिए 50 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि भाजपा के अपने सर्वेक्षण शिंदे की पार्टी की संभानाओं पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।

भाजपा रणनीतिकारों का साफ तौर पर मानना है कि शिंदे की पार्टी ने जो 7 लोकसभा सीटें इस बार जीती हैं वह सिर्फ भाजपा कैडर की वजह से ही संभव हो पाया है, क्योंकि शिंदे के उम्मीदवार ज्यादातर उन सीटों से चुनाव जीत गए जो भाजपा के वर्चस्व वाली सीटें हैं या यूं कहें कि शिंदे ने बड़ी चतुराई से भाजपा से गठबंधन धर्म के तहत वैसे सीटें हासिल कर ली जहां भाजपा का 'स्ट्रांग होल्ड' था।

अजित पवार की राकांपा को लेकर भाजपा का अपना सर्वे हैरान करने वाला है, सूत्र बताते हैं कि इन सर्वेक्षण नतीजों में अजित पवार की पार्टी हर सीट पर पिछड़ती नज़र आ रही है। सो भाजपा रणनीतिकारों ने एक बीच का रास्ता निकाला है और वे अजित से कह रहे हैं कि अपने उम्मीदवारों को वे भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा दें। सूत्रों की मानें तो भाजपा सर्वेक्षणों के नतीजे व जनता के मूड को भांपते महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी ले सकती है।

राहुल को अपनों से दगा

एक ओर जहां राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा-मोहरा बदलने की कवायदों में जुटे हैं वहीं उनके कई प्रादेशिक सिपहसालार ऐसे भी हैं जिनकी पार्टी के प्रति निष्ठा सवालों के घेरे में हैं। शायद इसीलिए अब यह संकेत मिलने लगे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने कई प्रदेश अध्यक्षों को बदल सकती है। इस

जनवरी माह में ही कांग्रेस शीर्ष को उनके ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष सरत पटनायक को लेकर कई शिकायतें मिली थीं कि वे कांग्रेस विरोधी दलों के हाथों में खेल रहे हैं। वैसे भी सरत पटनायक के बारे में चर्चा पूरे ओडिशा में आम थी कि उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में वीके पांडियन की एक महती भूमिका थी।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खासी नाराज़गी थी, खास कर उसके टिकट बंटवारे के तरीकों को लेकर। पर इतने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान के कानों में जूं

नहीं रेंगी, जिसका खामियाजा उसे ओडिशा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। एक और प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह, जिन्हें घोषित तौर पर लालू का 'नॉमिनी' कहा जाता है। इस लोकसभा चुनाव में कहते हैं दो प्रमुख कांग्रेस उम्मीदवारों का पर्चा रद्द होते-होते रह गया, जब आखिरी वक्त पर इन दोनों उम्मीदवारों को पता चला कि उनके फॉर्म 'बी' पर अध्यक्ष के गलत जगह दस्तखत हो गए हैं।

सूत्र बताते हैं कि आनन-फानन में फिर अगली सुबह हेलीकॉप्टर द्वारा सही 'बी' फॉर्म अध्यक्ष के सही जगह दस्तखत के साथ इन्हें भेजा गया, तब जाकर इनका नॉमिनेशन संभव हो पाया। आज ये दोनों कांग्रेस के टिकट पर विजयी सांसद हैं, एक हैं कटिहार से जीत दर्ज कराने वाले तारिक अनवर और दूसरे हैं किशनगंज से कांग्रेस की विजयी पताका लहराने वाले डॉ. जावेद।

हरियाणा में कांग्रेस के हौंसले बुलंद

हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र इलेक्शन के साथ अक्टूबर माह में कराए जा सकते हैं। सनद रहे कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव के चुनावी नतीजों से हरियाणा में कांग्रेस के हौंसले बम-बम हैं। कांग्रेस द्वारा कराए गए हालिया चुनावी सर्वेक्षणों के नतीजे इस बात की चुगली खाते हैं कि 'अगर आज की तारीख में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो गए तो कांग्रेस पार्टी यहां अकेले अपने दम पर 55 से 60 सीटें जीत सकती है।' कांग्रेस अपने सर्वे में इतनी बड़ी जीत का दावा महज़ इसीलिए कर रही है कि

उसके सर्वे में खुलासा हुआ है कि राज्य के जाट, दलित व मुस्लिम वोट उसके पक्ष में गोलबंद हुए हैं।

वहीं राज्य में 'भाजपा हटाओ' वोटरों की भी एक बड़ी तादाद है जो जाति-संप्रदाय से बाहर निकल कर भाजपा को हराने वाले प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस बहुत पहले से कई गुटों में बंटी नज़र आती है। हाल के दिनों तक इसे 'एसआरके' यानी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला व किरण चौधरी के गुटों में बंटी कांग्रेस के तौर पर जाना जाता था। पर बीते दिनों किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़ भगवा दामन थाम लिया है।

कांग्रेस का अपना आकलन है कि किरण के जाने से उसे भिवानी-महेंद्रगढ़ की कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, खास कर तोशाम सीट पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए इस बार सोनिया व राहुल दोनों व्यक्तिगत तौर पर सक्रिय हैं, समझा जाता है कि सोनिया ने सैलजा को तलब कर उन्हें समझाया है। वहीं राहुल व प्रियंका इस दफे हरियाणा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 'फ्री-हेंड' देने की पहल कर चुके हैं।

संसद को कटुता भरे आचरण में लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी

खरी-खरी बात
-वीरेन्द्र कपूर

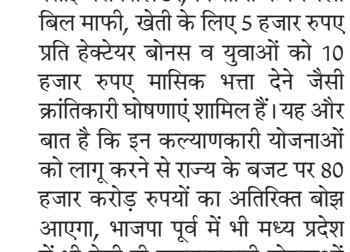

नवगठित 18वीं संसद को कटुता, संघर्ष और सरासर बुरे आचरण की 'सामान्य' स्थिति में वापस आने में देर नहीं लगी। सत्तारूढ़ दल द्वारा बिना किसी परेशानी के राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में चुनने के बाद लोकसभा शोर-शराबे और अव्यवस्थित दृश्यों की अपनी पुरानी स्थिति में लौट आई।

इस बार संख्या में अपेक्षाकृत बड़े विपक्षी दल ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाने के सवाल पर खुद को विभाजित पाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जून, 1975 के संदर्भ में स्वत: संज्ञान लेते हुए एक बयान दिया, यह वही दिन था जिस दिन देश विपक्षी नेताओं की राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारियों और मीडिया पर व्यापक सेंसरशिप की खबरों से जगा था। उन्होंने देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले कृत्य की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, यह संविधान पर खुला हमला था। लोगों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को रातों-रात ख़त्म कर दिया गया था और एक निरंकुश शासन स्थापित कर दिया गया था।

ओम बिरला ने सदन को हजारों भारतीयों के बलिदान की याद दिलाई, जिन्होंने आपातकाल का बहादुरी से विरोध किया और 19 महीने तक जेल में रहे, जिसके दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपमान और यातना का सामना करना पड़ा। जब बिरला आपातकाल के निंदात्मक संदर्भ को पढ़ रहे थे तब बड़ी संख्या में विपक्षी सदस्य सहमति में सिर हिला रहे थे, जबकि कांग्रेस के सदस्यों ने पचास साल पहले की घटनाओं के संदर्भ में कुछ विरोध के साथ खुद को अलग-थलग पाया। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के जिक्र पर कांग्रेस की बेचैनी समझ में आ सकती थी। आखिर वो राहुल गांधी की दादी थीं। बिरला के आपातकाल के लंबे संदर्भ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी को तत्कालीन विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए वीरतापूर्ण संघर्ष की याद दिलाई। आख़िरकार इंदिरा गांधी को इस ग़लत धारणा के साथ संसदीय चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा कि देश में अपेक्षाकृत शांति आपातकाल शासन से खुशी का सुझाव देती है। वह हार गईं और लोकतंत्र बहाल हो गया।

राहुल ने खुद को तब और अधिक उजागर कर दिया जब उन्होंने

आपातकाल के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उनके सामने इमरजेंसी के प्रस्ताव पर अपनी नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा था कि ऐसे राजनीतिक प्रस्तावों से हमें बचना चाहिए लेकिन यह कैसे एक राजनीतिक कृत्य था जबकि पूरा देश एक व्यक्ति के रूप में इंदिरा गांधी द्वारा संविधान पर हमले की निंदा करता है। ऐसे में यह किसी भी सच्चे लोकतंत्रवादी की समझ से परे है। इस बीच नए 'इंडिया' गठबंधन की विपक्षी एकता का दावा भी पूरी तरह से उस वक्त उजगार हो गया जब विपक्ष स्पीकर के चुनाव पर मत विभाजन कराने में विफल रहा। साथ ही कांग्रेस ने अपने सदस्य के. सुरेश के नामांकन दाखिल करने के बाद सांसद ओम बिरला को बिना किसी मतविभाजन के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष बनने की अनुमति दी। क्योंकि विपक्ष को डर था कि चुनाव से विपक्षी एकता कि खटास सबके सामने आ जाएगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उनसे सलाह लिए बिना के. सुरेश को मैदान में उतारने के एक तरफा फैसले का विरोध किया था। वह इस मामले को हल्के में लेने को तैयार नहीं थी और उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस कोई भी निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह जरूर लें। इसके आगे विपक्ष में चल रहे और भी मतभेद जल्द ही जनता के सामने आ जाएंगे इसका मुख्य कारण यह है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों की ही प्रधानमंत्री पद के महत्वाकांक्षी हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा के स्थगन की मांग करने से लगता है कि उन्होंने लंबे समय तक एक विधायक व संसद सदस्य के रूप में अपने अनुभव से जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गांधी परिवार के प्रति वफादारी को दिखाते हुए केवल नीट पर अपना पक्ष रखने के लिए सभापति की अवहेलना की और राज्यसभा सदन के वेल में आकर हंगामा किया। जब भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो उस वक्त उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से खड़गे का हस्तक्षेप भी मुद्दा विहिन था, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी के बयान भी औचित्यहीन थे जिस कारण सभापति ने उन्हें जोर देकर बैठने को कहा था। हमें आने वाले हफ्तों में आगामी बजट सत्र के दौरान इस तरह का अप्रिय माहौल और भी देखने को मिल सकता है।

पहली बारिश और....

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
f/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

50 डिग्री की गर्मी झेलने के बाद जब मानसून का इंतजार कर रहे थे और जिस तरीके से उसका दिल्ली में प्रवेश हुआ वह काफी हद तक घातक रहा। हमारे यहां सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि गर्मी में जब हम झुलसते हैं तो इसी मानसून का बेसबरी से इंजतार होता है लेकिन मानसून का पानी जब दिल्ली में विशेष रूप से आसपास के इलाकों में जमा होने लगता है तो फिर व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगते हैं। महज 48 घंटे पहले की बारिश ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की छत को ध्वस्त किया और एक कैब चालक की जान चली गई। इसके अलावा जिस तरह से दिल्ली, गुरुग्राम, सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा तक जिस तरह सड़कों पर पानी रहा और लोगों को चार-चार घंटे जाम का सामना करना पड़ा उससे व्यवस्था पर सवाल तो उठते ही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में छह-सात लोग घायल हुए हैं। जिस छत के नीचे आम टैक्सी वाले रोजी-रोटी की तलाश में यात्रियों की एक कॉल की प्रतिक्षा कर रहे होते हैं वहीं अगर उन पर ऐसी जानलेवा छत गिर जाए तो इसे क्या कहेंगे।

मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बदलते समय में इस बात का अहसास करना बहुत जरूरी है कि दिल्ली पर आबादी और वाहनों का बोझ बहुत बढ़ रहा है। शहर की सीवरेज व्यवस्था आज से नहीं कम से कम 30 साल पहले से ही लड़खड़ा चुकी है। यद्यपि इस बार मानसून ने पहले ही दिन जिस तरह से दिल्ली में एंट्री की उससे 88 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूटा लेकिन व्यवस्था के मामले में हमारा प्रशासन आज भी वहीं है जहां वह कम से कम तीस साल पहले था। दिल्ली से गुरुग्राम या नोएडा या गाजियाबाद,मेरठ, सोनीपत जाना हो तो मामूली सी बरसात में ही हाइवे तक पानी के दरिया बन जाते हैं। शहर में पानी के भराव की हालत यह है कि कनाट प्लेस और वीआईपी क्षेत्रों में जहां नेताओं के बंगले हैं उनके वहां तक पानी जमा है। आम आदमी जो निचले क्षेत्रों और अन्य इलाकों में रहता है वहां पानी की हालत यह है कि सड़कों पर ही चाहे वह रिंग रोड हो या अन्य सड़कें वहां इसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं है, ऐसा लगता है कि हर साल मानसून जिस तरह से दिल्ली पर बरसता है हमारे प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया।

जो लोग अपने घरों से कामकाज के लिए और व्यापार के लिए बस से या टैक्सी से या फिर अपने वाहन से एनसीआर इलाके में कहीं के लिए भी निकलते हों तो उनको दैनिक जीवन में भी सड़कों पर जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। दिल्ली के कनाट प्लेस, रिंग रोड, धोलाकुआं, आउटर रिंग रोड, रोहतक रोड या पंजाबी बाग हो, आजाद पुर हो आखिकार जाम से निपटने के लिए स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं है। बारिश के दिनों में अभी चार साल पहले दिल्ली से गुरुग्राम और गुरुगाम से दिल्ली आने-जाने वालों को छह से सात घंटे लग गए थे। पूरा हाइवे जाम था। आखिकार अगर व्यवस्था नहीं होगी तो लोग सवाल उठाएंगे ही। पुराने वर्षों की तरह हर मानसून में व्यवस्था को लेकर चर्चा करना मैं जरूरी समझती हूं लेकिन लोगों को कोई दिक्कत ना हो यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। बेचारी महिलाएं जो कामकाज को निकलती हैं वे अपने दफ्तरों में तीन-चार घंटे देरी से पहुंची होंगी और रास्ते में उन्हें कितने भारी जाम का सामना करना पड़ता होगा। यह सचमुच मानसिक रूप से ही तकलीफ देता है लेकिन और भी दुखदायक बात यह है कि ठोस व्यवस्था नजर नहीं आती।

अब जबकि मानसून के आने के पहले ही दिन हम इसके रोद्र रूप को देख चुके हैं तो इसे एक चेतावनी मानकर ठोस व्यवस्था भी करनी होगी। दो दिन पहले जो कुछ बारिश की वजह से दिल्ली में घटित हुआ उम्मीद की जानी चाहिए कि वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम अपने हाइवे, रिंग रोड या अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर जलभराव के मौके पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें दिल्ली को पैरिस बनाने के सब्जबाग दिखाने बंद करने होंगे। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, सफर में सुरक्षित रहें यह व्यवस्था प्रशासन का काम है और सरकार के प्रतिनिधियों को इसकी व्यवस्था करनी होगी। देश सेवा का मतलब बड़े-बड़े वादे करना नहीं बल्कि ठोस व्यवस्था करना है ताकि नागरिकों को बाढ़ की सूरत में दिक्कतें न हों।

आरोपबाजी में कुछ नहीं रखा। किसी समस्या पर राजनीतिकरण की बजाए व्यवस्था को लेकर सत्तापक्ष हो या विपक्ष सबको मिलकर काम करना होगा। बाढ़ की विभिषीका का असर हम हर साल देखते हैं। प्रशासन कब जागेगा, कब आरोप-प्रत्यारोप की परंपरा तोड़कर ठोस व्यवस्था का इंतजार लोगों को है, यह सब हम सोशल मीडिया पर उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। मानसून ने चेतावनी दे दी है अब समय रहते इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मुसीबत आने से पहले ही ठोस व्यवस्था करना आपके विवेक को दर्शाता है। विश्वास है कि दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार और प्रशासन मिलजुल कर लोगों को मानसून और बारिश के खतरे और इसके असर से बचाकर आगे बढ़ेगा।

नये कानूनों का तमिल में अनुवाद जारी

चेन्नई, (पंजाब केसरी): नये आपराधिक कानूनों का तमिल में अनुवाद जारी है और इसके जल्द पूरा होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि एक जुलाई 2024 से नये आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पुलिसकर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि पुलिसकर्मियों को विभिन्न अपराधों के लिए उपयुक्त धाराएं लगाने में कोई कठिनाई न हो। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तीनों नये आपराधिक कानूनों का अनुवाद कार्य जारी है और जल्द ही इसके पूरा होने की संभावना है। इसके पूरा होने के बाद तमिल संस्करण को अंग्रेजी में कानूनों के प्रामाणिक अनुवाद के रूप में अनुमोदन और प्रमाणन के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

सज्जनों के साथ खड़ा रहता हूं तो दुष्टों के त्राण के लिए कदम भी उठाता हूं: मुख्यमंत्री

● कहा, मैं भी बचपन में इंजीनियर बनने की सोचता था

सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित, उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संन्यास लेने पर शुरू-शुरू में लोग मुझे टोकते थे। आज मैं उन लोगों को देखता हूं तो पाता हूं कि कोई संतुष्ट नहीं है। भौतिक उपलब्धि व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। ये ठीक है कि मैं आज मुख्यमंत्री हूं। मगर मैंने संन्यास लिया, ये पलायन का नहीं परिश्रम और संघर्ष का मार्ग है। आज भी 16-18 घंटे काम करता हूं, इसलिए नहीं कि कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने संन्यास की सार्थकता को साबित कर सकूं। भारत की ऋषि परंपरा ने संन्यास की जो व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था सही है, इसे साबित कर सकूं। आज मैं भगवान श्रीकृष्ण के सिद्धांतों पर चलते हुए सज्जनों के साथ खड़ा रहता हूं और दुष्टों के त्राण के लिए कदम भी उठाता हूं। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में छात्र-छात्राओं के विभिन्न रोचक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र-छात्राओं की ओर से पूछे गये सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि संन्यास का फैसला लेना उनके और उनके माता-पिता के लिए चुनौती थी। कोई अभिभावक नहीं चाहता कि उसका बच्चा सन्यासी बन जाए। अभिभावक रिटर्न चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में वह भी वही सोचते थे, जो आज के बच्चे सोचते हैं। वह चाहते थे कि एक अच्छा इंजीनियर बनें। बाद में अहसास हुआ कि कोई इंजीनियर या पद प्राप्त करने से अच्छा है कि पीड़ितों के साथ खड़ा रहूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही मेरे जीवन की सार्थकता है।

उन्होंने कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जितना परिश्रम करेंगे उसका परिणाम हमारे पक्ष में जरूर आएगा। कहा कि किसी कार्य में अगर बाधाएं नहीं हैं तो मानकर चलिए कि आपकी दिशा ठीक नहीं। जितने शुभचिंतक हैं उतने ही दुश्मन भी होने चाहिए। तब जो सफलता मिलती है उसका आनंद भी अलग होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर छात्र छात्रा को प्रधानमंत्री मोदी की किताब एग्जाम वारियर्स जरूर पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए एक टीम की जरूरत होती है, जो बिना रुके, बिना झुके लगातार आगे बढ़े। यकीन है कि मेरी युवा पीढ़ी इसके लिए तैयार है। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को राजनीति में अपना आदर्श बताते हुए कहा कि पॉलिटिक्स फुल टाइम जॉब नहीं है। राजनीति में अलग-अलग फील्ड से जुड़े विशेषज्ञों को आना चाहिए। इसमें अच्छे शिक्षाविद, अच्छे पत्रकार, अच्छे चिकित्सक, किसान सबको योगदान देना होगा। जब ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा आगे बढ़ेगी। केवल इसलिए कि हम राजनीति में आ जाएं और जाति, परिवार क्षेत्र के नाम पर विभाजन करके सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करें तो देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी कुछ और नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि ये जानते हुए कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही जाति वैमनस्यता थी, क्योंकि क्या नहीं था भारत के पास। बल, वैभव, विद्या सबकुछ था यहां। दुनिया में तूती बोलती थी भारत की, लेकिन जाति वैमनस्यता ने इतनी गहरी खाई को चौड़ा किया कि चंद विदेशी आक्रांता आए और हमपर शासन करने लगे। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का जो काम इतिहास में किया गया, आज वही काम ये जातिवादी और वंशवादी नेता कर रहे हैं। सीएम ने छात्र-छात्राओं को सलाह दी कि वे अच्छे अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी बनें और आपकी वहां की अच्छाई की चमक आपको स्वत: राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर सकती है। राजनीति खुद आपकी डिमांड करेगी। आपको उसके पीछे नहीं जाना होगा। राजनीति, पद प्रतिष्ठा हमारे पीछे आएगी, हमें इतना परिश्रम करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि जब आप कक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त करते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से ये आपका परिश्रम है, मगर इसके पीछे, आपके विद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारीगण और परिजनों का भी परिश्रम शामिल है। हर प्रकार के सार्थक प्रयास जब सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें 2047 में पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप एक विकसित भारत बनाना है। यह तभी संभव होगा जब हम एक अच्छा नागरिक बनेंगे और सामूहिक प्रयास से आगे बढ़ेंगे। मेधावी छात्र-छात्राओं को हृदय से बधाई देते हुए कहा कि यहां छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है। बालिकाओं ने बोर्ड की परीक्षा में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। ये बताता है कि बालिकाएं तनाव में कम रहती हैं और मेहनत ज्यादा करती हैं।

मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछने वाले छात्र-छात्राओं में कृष्णा तिवारी, सोनम पाठक, इशान पचौरी, शांभवी द्विवेदी और कृष्णा शामिल रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने विभिन्न परीक्षाओं में मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

सीडीओ और एसडीएम को मिलने वाली शिकायतें भी आईजीआरएस पर होंगी दर्ज

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● जनसुनवाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए शासन स्तर से लगातार हो रही है मॉनीटरिंग

जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान जैसे जिलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने वाली जनशिकायतों/समस्याओं की मॉनीटरिंग की तरह ही अब मुख्य विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी कार्यालयों में आने वाली शिकायतों की भी मॉनीटरिंग होगी। नई व्यवस्था के तहत सीडीओ और एसडीएम कार्यालयों में प्राप्त जन शिकायती प्रार्थना पत्रों की फीडिंग जनसुनवाई-समाधान प्रणाली (आईजीआरएस) पर होगी। इससे न केवल समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी।

बता दें कि शिकायतों के निस्तारण हेतु आमजन द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सम्पूर्ण समाधान दिवस (तहसील दिवस), थाना समाधान दिवस, जन सुविधा केंद्र, भारत सरकार (पीजी पोर्टल), मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पोर्टल एवं ऐप आदि के माध्यम से आवेदन पत्र दिए जाते हैं। शिकायतों का निस्तारण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई-समाधान प्रणाली के माध्यम से करने की व्यवस्था है। हाल ही में जब मुख्यमंत्री द्वारा जनसुनवाई की समीक्षा की गई तो पाया गया कि जनपदों में ऐसे भी कार्यालय हैं, जहां जन शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होतें हैं, लेकिन ऐसे पत्रों को जनसुनवाई-समाधान प्रणाली पर फीडिंग कराते हुए निस्तारण किए जाने की व्यवस्था लागू नहीं है। उप जिलाधिकारी कार्यालयों एवं मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों में प्रतिदिन महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। जिन्हें अब आईजीआरएस से जोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीते दिनों फील्ड में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ़ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम एक बार फिर प्रारंभ हो चुका है और अब जिला, तहसील, ब्लाक, रेंज, जोन में तैनात वरिष्ठ अधिकारी भी जनसुनवाई का नियमित कार्यक्रम प्रारंभ कर दें। प्रति दिन सुबह 10 से 12 बजे तक अधिकारियों को जनसुनवाई के लिए उपस्थित रहना होगा। अधिकारीगण संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याएं/ शिकायतें सुनें और एक तय समय सीमा के भीतर उसका यथोचित निराकरण कराएं।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 14 को

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में होगी। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों की संदर्भ में शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने बैठक कर चर्चा की। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्षों सहित अन्य प्रमुख जन सम्मिलित होगें। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, अभियानों व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने किया 'टेम्पल ट्रेजर्स: ए जर्नी थ्रू टाइम' पुस्तक का विमोचन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने शनिवार को अपने लखनऊ स्थित मंत्री आवास पर 'टेम्पल ट्रेजर्स: ए जर्नी थ्रू टाइम' नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने पुस्तक के लेखक अमित अग्रवाल को बधाई देते हुए कहा कि यह पुस्तक देश के प्राचीन मंदिरों और उनके ऐतिहासिक खजानों के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करेगी। मंत्री ने कहा कि यह पुस्तक न केवल प्राचीन भारतीय संस्कृति और धरोहर को जानने का माध्यम बनेगी, बल्कि नई पीढ़ी को हमारे समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि 'टेम्पल ट्रेजर्स: ए जर्नी थ्रू टाइम' शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और मंदिर प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगी।

आभा आईडी से एक करोड़ टोकन जेनरेट करने वाला पहला राज्य बना यूपी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

हेल्थ सेक्टर में लगातार कीर्तिमान बना रहे उत्तर प्रदेश ने अब एक और उपलब्धि अपने नाम की है। प्रदेश ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी के माध्यम से एक करोड़ टोकन जेनरेट करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इतनी बड़ी संख्या में टोकन जेनरेट करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला और एकमात्र राज्य है। उत्तर प्रदेश ने अब तक कुल एक करोड़ 43 टोकन जेनरेट किए हैं। टोकन जेनरेशन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, जिसने 60 लाख 33 हजार 104 टोकन जेनरेट किए हैं। वहीं, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, जिसने कुल 42 लाख 57 हजार 944 टोकन जेनरेट किए हैं। इस क्रम में जम्मू और कश्मीर (38,87,226), दिल्ली (22,28,079), बिहार (15,65,332), मध्य प्रदेश (12,53,722), महाराष्ट्र (7,96,938), छत्तीसगढ़ (7,34,781), ओडिशा (5,06,580) और गुजरात (3,83,789) जैसे राज्यों का स्थान आता है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आभा आधारित ओपीडी रजिस्ट्रेशन में 80 लाख के आंकड़े को पार कर भी नया रिकार्ड बनाया था। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश ने 10 करोड़ आभा आईडी बनाने का भी कीर्तिमान बनाया था। आभा टोकन जेनरेशन और आईडी बनाने की यह उपलब्धियां सीएम योगी द्वारा प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रति लोगों में जागरूकता और सक्रिय भागीदारी के लिए किए गए प्रभावी प्रयासों का नतीजा है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की पहल है। यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत शुरू किया गया एक स्वास्थ्य बचत खाता है। इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उनकी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आभा आईडी नागरिक के आधार या मोबाइल नंबर से जुड़ी एक अद्वितीय 14 अंकों की पहचान संख्या है। यह उन्हें सभी सूचनाओं को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने और उन तक पहुंचने में मदद करता है। इसमें उनकी हेल्थ हिस्ट्री, परामर्श विवरण, मेडिकल रिकॉर्ड और नुस्खे शामिल हैं।

सपा एक जुलाई से करेगी 'पीडीए पेड़' वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 तक प्रदेशव्यापी 'पीडीए पेड़' वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के प्रत्येक गांव में किया जाएगा।

यह प्रदेशव्यापी कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलेगा। समाजवादी पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता मिलकर उत्तर प्रदेश के हर गांव में पीडीए पेड़ लगाएंगे। पीडीए पेड़ के रूप में बरगद, पीपल और नीम का पौधारोपण किया जाएगा। जो पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में सामाजिक समानता-समता की प्राणवायु हर दिन देंगे। सपा प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में हर तरफ फैले हुए तरह-तरह के प्रदूषण को दूर करने के लिए आवश्यकता पेड़ की है, शाखाओं की नहीं। जब पौधे की जड़ें जमीन पकड़ लेती हैं तो शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल सब अपने आप प्राप्त होता है। वे शाखाएं अप्राकृतिक होती हैं जिनकी न तो जड़ों का पता होता है, और न ही इस बात का कि उनका फल किसको मिल रहा है। इसीलिए आवश्यकता जमीन से जुड़ें पेड़ों की है, मनुष्य निर्मित शाखाओं की नहीं। उन्होंने बताया कि पीडीए पेड़ पौधारोपण के इस पर्यावरणीय, सामाजिक आंदोलन को समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के गांवों से शुरू करके आगामी चरणों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का प्रयास किया जाएगा।

यूपी के वैश्य व व्यापारी समाज का उत्पीड़न हो रहा: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भामाशाह का पूरा जीवन त्याग और सत्यनिष्ठा का उदाहरण है। उनका मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था। उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अपनी सम्पूर्ण धन सम्पदा अर्पित कर दी थी। इस धनराशि से महाराणा प्रताप ने नया सैन्य बल गठित कर मेवाड़ की रक्षा की। मातभूमि के प्रति अगाध प्रेम और दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम इतिहास में अमर है। उनके जीवन से निष्ठा, समर्पण और त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वैश्य व व्यापारी समाज का उत्पीड़न हो रहा है। आज वैश्य व व्यापारी समाज भाजपा शासन में सबसे ज़्यादा पीड़ित है। जीएसटी से बड़े पैमाने पर व्यापार का नुकसान हुआ है। व्यापारी व वैश्य समाज भी अब ये मानता है कि व्यापारी और वैश्य समाज का सम्मान केवल सपा सरकार में ही सम्भव है। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि सपा सरकार बनने पर व्यापारी व वैश्य समाज को उनका खोया हुआ सम्मान मिलेगा। उन्होंने लोकसभा में जीत के लिए बधाई दी और कहा कि हमें भाजपा की साजिशों में नहीं फंसना है। 2027 विधानसभा चुनाव की लड़ाई बड़ी है। इसमें नहीं चूकना है। इस अवसर पर सर्वश्री शिवपाल यादव, बलराम यादव, राजेन्द्र चौधरी, श्याम लाल पाल, लाल बिहारी यादव, आर.के. वर्मा, उदयवीर सिंह, मौलाना नज़र मोहम्मद, डॉ. राजपाल कश्यप, कृष्ण कन्हैया पाल एडवोकेट, सरदार हरदीप सिंह लाखड़ा की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रवक्ता श्री अभिमन्यु गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय सूद, प्रदेश उपाध्यक्ष वोट सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय जायसवाल, अंशुल गुप्ता, श्यामकृष्ण गुप्ता, हरदीप सिंह राखड़ा, राम बाबू रस्तोगी, बृजेश गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, सुजीत जायसवाल, ऋषि राज अग्रवाल, संजय यादव, दीपू श्रीवास्तव, प्रीयतेश सिंह तोमर, रवि गुप्ता, साहिल खान, मो साकिफ, कमलेश गुप्ता, पवन यादव, अंकित गुप्ता आदि ने भी अखिलेश यादव के साथ ही भामाशाह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

सपा प्रमुख से मिला प्राथमिक शिक्षामित्र संघ का प्रतिनिधिमंडल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर शिक्षामित्रों की समस्याओं को लोकसभा के सदन में उठाने की मांग की है। प्रतिनिधिमण्डल ने अखिलेश यादव को एक ज्ञापन सौपा। जिसमें 2014 में सरकार ने शिक्षामित्रों को बीटीसी कराकर सहायक अध्यापक बनाया गया था लाखों शिक्षामित्र परिवार खुशहाल हो गये थे। लेकिन 2017 में भाजपा की निर्दयी सरकार ने सहायक अध्यापकों को फिर शिक्षामित्र बनाकर शिक्षामित्रों को आर्थिक, मानसिक व सामाजिक रूप से बर्बाद कर दिया है जिससे हजारों शिक्षामित्रों की असमय मौत हो गयी और लाखों शिक्षामित्र अवसाद में है। शिक्षामित्र संघ ने श्री अखिलेश यादव से लोकसभा में शिक्षामित्रों की समस्याये उठाने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमण्डल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने पर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने कहा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुई लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जीत से छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, बेरोजगार व संविदाकर्मियों सहित समस्त जनमानस में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ और लाखों शिक्षामित्रों की ओर से इस बड़ी जीत पर समाजवादी पार्टी एवं अखिलेश यादव के नेतृत्व को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयी है।

कांग्रेस प्रदेशभर में संविधान व सामाजिक न्याय गोष्ठियों और सम्मेलन का करेगी आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला व शहर कमेटी के अध्यक्षों की बैठक हुई। जिसमें विभिन्न प्रस्तावों और कार्यक्रमों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित हुए तथा आगामी कार्यक्रमों की घोषणा हुई।

पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों ने लोकसभा चुनाव में भागीदारी न्याय के मुद्दों की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा प्रदेश भर की जनता को बधाई दिया। बैठक में निम्न सामाजिक राजनीतिक प्रस्तावों पर संघर्ष करने की सहमति व प्रस्ताव पेश सर्वसम्मति से पारित किया और सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ निम्न मुद्दों पर निम्न लिखित मुद्दों द्वारा संघर्ष जारी रहेगी। जिसमें प्रदेश भर में ब्लॉक/ तहसील/ विधानसभा व जिला स्तर पर संविधान एवं सामाजिक न्याय गोष्ठियां व सम्मेलन का आयोजन करेगी। सामाजिक न्याय की धार को और मज़बूत करेंगे जिसमें विभिन्न तात्कालिक मुद्दे जैस नीट की परीक्षा रद्द करना और जखनिया विधायक बेदी राम और उन्हें समर्थन देने वाले सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अध्यक्ष मनोज यादव ने पिछड़ों के हक़ अधिकार के हर सवाल पर सम्मलेन धरना आयोजित करने हेतु संगठन के पदाधिकारीगणों को तैयार रहने का निर्देश देते हुए कहा कि सीएसडीएस के आंकड़े बता रहे हैं कि ओबीसी समाज अब आरएसएस बीजेपी के गुमराह तंत्र में फसने वाला नहीं है और बीजेपी अपने पतन की ओर बढ़ रही है जिसका परिणाम आपको आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्टरूप से दिखेगा।

बैठक में बतौर अतिथि शामिल अल्पसंख्यक कांग्रेस के चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने भी सामाजिक न्याय की पार्टी की रणनीति को सफल बताया और सीएसडीएस के आकड़ों के हवाले से सवर्ण वोटर की बीजेपी को एकतरफा कट्टरता से वोट देने के आकड़ों पर बात रखी।

पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या वाराणसी व गोरखपुर में चलेगा बड़ा अभियान

● दो महीने तक तीनों जिलों में वृहद जागरूकता अभियान का होगा संचालन, 2 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय से कार्यों को किया जाएगा पूर्ण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने के लिए कृत संकल्प योगी सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़े स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूं तो कई कार्यक्रम व विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है, मगर अयोध्या, वाराणसी व गोरखपुर में 'पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना' के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान का संचालन किया जाएगा। यह जागरूकता अभियान इन्टीग्रेटेड मार्केटिंग कम्यूनिकेशंस (आईएमसी) मॉड्यूल पर बेस्ड होगी। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सीएम योगी के विजन अनुसार जो कार्ययोजना तैयार की गई है उस पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (यूपीनेडा) ने कार्य शुरू कर दिया है। इस 2 महीने चलने वाले वृहद अभियान के उचित संचालन के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए बाकायदा एक फर्म को इम्पैनल किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति व कार्यावंटन की प्रक्रिया यूपीनेडा द्वारा शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) जन जागरूकता बढ़ाकर प्रदेश के प्रमुख शहरों अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना की स्वीकार्यता में बढ़ावा और योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या में तेजी लाना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा जनता तक पहुंच बढ़ाने के लिए आईएमसी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा।

इसमें बैनर प्रदर्शित करना, रणनीतिक स्थानों पर बिलबोर्ड लगाना, बूथ कैंप लगाना, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ-साथ पैम्फलेट वितरण जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। यूपीनेडा द्वारा अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी में रेडियो और समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के साथ ही अन्य कई माध्यमों से प्रचार-प्रसार को लक्षित किया जा रहा है। इस क्रम में, विकास भवन, डिस्कॉम बिलिंग ऑफिस, डिविजनल ऑफिस व सब स्टेशन, नगर निगम समेत ज्यादा फुटफॉल वाले रणनीतिक रूप से प्रमुख स्थानों पर बैनर, स्टैंडीज, बिलबोर्ड और बूथ कैंप लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 150 ऑटो रिक्शा व 150 ई-रिक्शा व व्हीकल्स के बैकसाइड को कवर किया जाएगा। वहीं, अयोध्या में 4, गोरखपुर में 4 व वाराणसी में 2 वेंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा।

चैंबर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, रेड क्रॉस व सीए सोसाइटीज में कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। वहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू), अयोध्या यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा अन्य प्रसिद्ध कॉलेजों व स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टाफ व स्टूडेंट्स का सहयोग लिया जाएगा। वहीं, अयोध्या में 3, गोरखपुर में 4 तथा वाराणसी में सोलर एनर्जी इनेबल्ड मोबाइल व्हीकल (सूर्य रथ) को शहर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। जरूरत के अनुसार इनके जरिए जरिए डोर टू डोर कैंपेन जैसी प्रक्रियाओं को भी पूर्ण किया जा सकता है। वहीं, तीनों चिह्नित शहरों में सोलर मेला का भी आयोजन किया जाएगा जिसके जरिए केंद्र व राज्य की सौर व अन्य स्वच्छ ऊर्जाओं को बढ़ावा देने वाली योजनाओं से आम जनता को अवगत कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अयोध्या और वाराणसी को पहले से ही सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में व्यापक अभियान के जरिए अब गोरखपुर में भी सोलर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और व्यापक प्रचार-प्रसार का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कौन था कौशलेंद्र यादव

गरीबी-उन्मूलन के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं जरूर चलाई हैं, पर कुवैत में जल मरे भारतीय और नोएडा की एक आलीशान इमारत के बाहर जानलेवा गर्मी से तड़पकर मरे कौशलेंद्र यादव के साथ जो हुआ, वह कई सवाल भी खड़े करता है। संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र को इनके उत्तर का इंतजार है।

शशि शेखर

'मृतक कौशलेंद्र यादव, पुत्र : विनोद कुमार, उम्र : करीब 27 वर्ष, निवासी : ग्राम मिलिक, थाना- कुर्रा, जिला- मैनपुरी। हाल पता : कोंडली गांव में अमित यादव के मकान में किराये पर। थाना- नॉलेज पार्क, गौतमबुद्ध नगर।'

इस थाने की फर्द आगे बताती है- '18 जून को कौशलेंद्र के जीजा अभिषेक ने बताया कि उसे पहले बुखार आया था। वह घर पर ही दवा लेता रहा। दूसरे गार्ड ने बताया कि कौशलेंद्र की तबीयत ज्यादा खराब थी। पहले सोसायटी के पास ही एक बंगाली डॉक्टर को दिखाया, तो ज्यादा खराब हालत बताई गई। उसके बाद कौशलेंद्र को जिम्स ले गए, जहां पर तीन घंटे तक इलाज चला और उसकी मौत हो गई, जिसे डॉक्टरों ने हीटस्ट्रोक बताया था।'

आजकल

ये चंद पंक्तियां देश के बेहद बड़े वर्ग की बेबसी की करुण-गाथा सामने लाती हैं।

कौशलेंद्र यादव जवान था। उसकी शादी हो चुकी थी। पत्नी गांव में रहती है और वह इस उम्मीद से इस महानगर में आया होगा कि दिन-रात खटकर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकूंगा। शायद उसने यह भी सोचा हो कि बहुत न कर सका, तो इतना कर ही लूंगा कि मुझ जैसी जिंदगी उनकी न हो। कौशलेंद्र की आज तेरहवीं है। *गरुड़ पुराण* के अनुसार, तेरहवीं के बाद आत्मा इस संसार से विदा ले लेती है। लोग मरने के बाद कहां जाते हैं? कोई परमात्मा या आत्मा होती है या नहीं, मैं इस बहस में पड़े बिना बस इतना पूछना चाहूंगा कि क्या कौशलेंद्र को अपने बच्चों की बेहतरी का ख्वाब बुनने का हक नहीं था?

उसकी मौत उन तमाम गुलाबी आंकड़ों का उपहास उड़ाती है, जो सियासी शोशेबाजी के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

कौशलेंद्र नोएडा आकर किसी तरह गार्ड की नौकरी हासिल कर सका था। एक आलीशान सोसायटी के मुख्य दरवाजे पर उसकी ड्यूटी थी। बिना किसी छत अथवा आड़ के लगातार 12 घंटे उसे वहीं बिताने होते थे। उस दिन तापमान 45 डिग्री पार कर गया था। भयंकर लू सांसों को वजनी बना रही थी। उसकी जर्जर देह इस दाहक ताप को बर्दाश्त न कर सकी। वह पिछले बीस बरसों में हमारे बीच पनपी उस गार्ड बिरादरी का सदस्य था, जिससे हर मौसम में हमेशा सजग और सतर्क रहने की उम्मीद की जाती है।

लोग उन्हें 'हायर' कर खुद की नींद और चैन जुटाना चाहते हैं, पर बदले में इन्हें क्या मिलता है? बमुश्किल पंद्रह हजार रुपये महीना।

कौशलेंद्र और उस जैसे लोग जिस वर्ग से आते हैं, उसी वर्ग से हमारी माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आते हैं। वह जिस यादव जाति में जन्मा था, उत्तर प्रदेश और बिहार में उसकी तूती बोलती है। बरसों तक स्वर्गीय मुलायम सिंह मैनपुरी के सांसद रहे और अब डिंपल यादव उसका प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करती हैं। हमारे राजनेता प्रतीकवाद पर चुनाव लड़ते हैं। जो लोग उन पर भरोसा कर वोट देते हैं, उनकी हालत कैसी है?

कौशलेंद्र और उस जैसे हजारों का हतभागी हश्र इस सवाल का मुकम्मल जवाब है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पहली मार्च से 20 जून के बीच में चालीस हजार से अधिक लोग लू की चपेट में आए। इनमें से 143 को नहीं बचाया जा सका। इनमें से अधिकांश गरीब-गुरबा रहे होंगे। क्यों? जवाब जान लीजिए। गए रविवार को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तापलहरी के 75 शिकार भर्ती थे। इनमें से अधिकांश दैनिक श्रमिक, डिलीवरी ब्वॉय अथवा बुजुर्ग थे। हमने मौसमी रोजगारों के रूप में मौसम के नए शिकार जन दिए हैं।

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2014 से 2023 के बीच के नौ बरसों में 'बहु-आयामी गरीबी' की खाई से 24.82 करोड़ भारतीय उबर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी 'बहु-आयामी गरीबी' में गिरावट दर्ज की गई। यहां आपके मन में यकीनन सवाल उभर रहा होगा कि क्या है बहु-आयामी गरीबी? बहु-आयामी गरीबी की सरकारी परिभाषा के तहत एक ऐसा व्यक्ति, जो आय ही नहीं, बल्कि भूमि-आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और बिजली जैसी कई चीजों तक पहुंच के लिहाज से भी वंचित है।

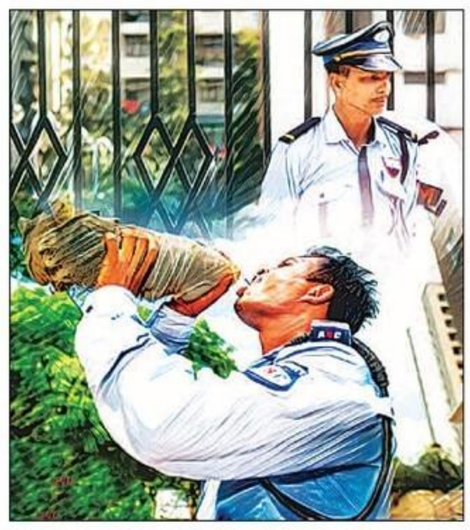

कौशलेंद्र इस हिसाब से 'बहु-आयामी निर्धन' नहीं था।

इसमें कोई दोराय नहीं कि हम संसार की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक हैं, लेकिन इस गुनगुने सच के पीछे एक गम भरा अंधेरा भी छाया हुआ है। 'वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत आर्थिक विषमता के मामले में भी नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। हिन्दुस्तान की शीर्ष एक फीसदी अमीर आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 53 फीसदी हिस्सा है। अगर आमदनी की सबसे ऊंची सीढ़ियों पर बैठे लोगों की इस सूची को थोड़ा-सा विस्तार दे दिया जाए, तो और अधिक चौंकने की बारी आती है। देश की कुल मिल्कियत का 77 प्रतिशत इसके दस प्रतिशत धनाढ्य अपने हक-हुकूक में रखते हैं।

क्या वे उतना ही खर्च भी करते हैं, ताकि सरकार को अधिक आमदनी हो और वह बेहतर कल्याणकारी योजनाएं चला सके?

ऑक्सफैम की रिपोर्ट 'सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया स्टोरी' के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह का लगभग 64.3 प्रतिशत हिस्सा उस आधी आबादी की जेब से आया, जो कमाई के मामले में कतार की पिछली तरफ खड़ी थी। जिन दस प्रतिशत धनाढ्य लोगों के पास 77 प्रतिशत संपत्ति है, उनका जीएसटी में योगदान पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। यही रिपोर्ट बताती है कि कुछ महीने पहले खत्म हुए वित्तीय वर्ष में विषमता की यह खाई अधिक चौड़ी होने की आशंका है।

अभी तक उसके आंकड़े सामने नहीं आ सके हैं।

गरीबों और वंचितों की एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि उनमें से बहुतों को अपना व अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 'परदेस' जाना ही होता है। पिछली जनगणना बताती है कि देश के भीतर एक से दूसरे राज्य में जाकर आजीविका कमाने वाले भारतीयों की तादाद तब की आबादी का 33 प्रतिशत, यानी 45.36 करोड़ थी। एक अन्य शोध के अनुसार, एक करोड़ अस्सी लाख भारतीय देश के बाहर काम कर रहे हैं। इनमें से हरेक तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का सीईओ या बड़ा एग्जिक्यूटिव बनता नहीं। नतीजतन, उन्हें वहां भी कुआं खोदकर पानी पीने का अभिशाप झेलना पड़ता है। बदले में मिलता क्या है? कुवैत की घटना इसका उदाहरण है। तबेले जैसी रिहाइश की आग में 45 भारतीय पिछले पखवाड़े जल मरे थे।

गरीबी-उन्मूलन के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं जरूर चलाई हैं, पर कुवैत में जल मरे भारतीय और नोएडा की एक आलीशान इमारत के बाहर जानलेवा गर्मी से तड़पकर मरे कौशलेंद्र यादव के साथ जो हुआ, वह कई सवाल भी खड़े करता है। संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र को इनके उत्तर का इंतजार है।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

स्कैन करें
आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

जीना इसी का नाम है

अब्दुल्लाही मिरे
पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता

हर शरणार्थी बच्चे के हाथों में किताब थमाने का इरादा

होदान बशीर नाम की लड़की ने एक दिन कुछ झिझकते हुए उनसे कहा- 'भाई, क्या मेरे लिए जीव विज्ञान की किताब खरीद देंगे?' होदान डॉक्टर बनना चाहती थीं। उनकी लरजती आवाज के पीछे की उत्कंठा, शर्म और बेबसी को अब्दुल्लाही मिरे से बेहतर भला कौन पढ़ सकता था?

क्या कभी आपने यह सोचा है कि जिन देशों या इलाकों पर अचानक कोई आक्रांता टुकड़ी धावा बोलती है या जहां बागी गुट कहर बरपाने लगते हैं, वहां सबसे ज्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ता है? ऐसी हर स्थिति के सबसे निर्मम शिकार मासूम बच्चे बनते हैं। जिंदगी को जानने से कब्ल मौत उन पर झपट्टा मारती है और अगर जिंदा बच गए, तो आगे दशकों का उनका सफर लावारिस या शरणार्थी के रूप में ही तय होता है। अब्दुल्लाही मिरे ऐसे हजारों मासूमों के लिए किसी रहबर से कम नहीं, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें 2023 के 'नानसेन शरणार्थी पुरस्कार' से नवाजा है।

साल 1991 में मिरे के माता-पिता जब सोमालिया में भड़के भीषण गृहयुद्ध से जान बचाकर भागे, तब वह बमुश्किल तीन साल के थे। उनके माता-पिता को लगा था कि कुछ महीनों में शांति स्थापित हो जाएगी, तो वे अपने घर लौट आएंगे। मगर विरोधी कबाइली गुट ने उनके कस्बे 'कोरीओली' पर कब्जा उसे खाली कर देने के लिए नहीं किया था, वह इलाका खेती-किसानी के लिहाज से काफी समृद्ध जो था। जाहिर है, घरेलू जंग बढ़ती चली गई और सोमालिया विफल राष्ट्र का दामन फिर कभी न छोड़ पाया। बहरहाल, मिरे के माता-पिता को केन्या के दादाब शरणार्थी शिविर में पनाह मिल गई थी, पर कहां कोरीओली की आजाद जिंदगी और कहां तरह-तरह की बंदिशों में घिरा शरणार्थी जीवन! सुकून सिर्फ इतना था कि हतभागियों की उस बस्ती में ज्यादातर सोमालियाई थे, जिनके साथ जुबान और दर्द की साझेदारी थी। तीन साल के अबोध मिरे के लिए यह अनोखी जगह थी, जहां वह अपने माता-पिता के साथ 'प्लास्टिक शीट' की छत वाली झोंपड़ी में रह रहे थे। उन प्लास्टिक की पन्नियों पर कुछ शब्द छपे थे, जो फर्श पर लेटे मिरे के ऊपर सूरज की रोशनी में जादुई असर डालते। बालक मन में जिज्ञासा पैदा होने लगी थी कि आखिर ये कैसी आकृतियां हैं?

पिता ने उन अक्षरों के मतलब बता दिए थे, मगर वह यह भी जानते थे कि इल्म तक पहुंचने के लिए उनके बेटे को मुकम्मल तालीम की जरूरत होगी। बतौर शरणार्थी उन्हें जो थोड़ी-बहुत सहूलियतें हासिल थीं, उनमें से एक शिविर में संचालित स्कूल में बेटे को पढ़ा सकने की सुविधा भी थी।

मिरे का दाखिला हो गया और चंद सालों में उन्हें यह एहसास भी हो गया कि शरणार्थी शिविर की चुनौतियों से बाहर निकलने की एक ही राह है- शिक्षा! जाहिर है, जरूरत और दिलचस्पी, दोनों ने मिरे को गढ़ना शुरू कर दिया।

हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बस्ती के ज्यादातर बच्चे किसी न किसी काम की तलाश में जुट जाते थे, ताकि वे अपने परिवार का बोझ बांट सकें, मगर मिरे की इच्छा ऊंची तालीम हासिल करने की थी। लिहाजा, उन्होंने स्कॉलरशिप

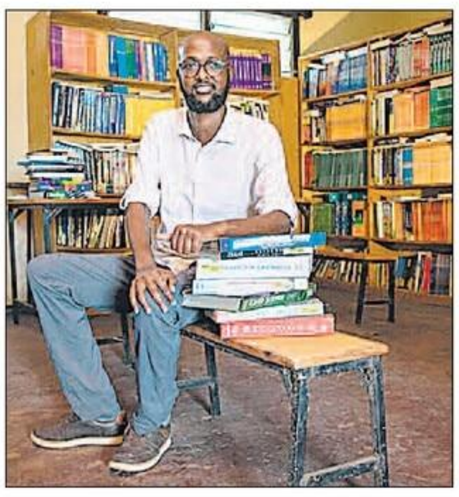

के लिए प्रतियोगी परीक्षा दी और वह उसमें कामयाब भी हो गए। मिरे पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते थे, क्योंकि दादाब शिविर की रिपोर्टिंग करते पत्रकारों से वह बहुत प्रभावित थे। केन्याता विश्वविद्यालय से 2014 में 'पीआर, कम्यूनिकेशन ऐंड मीडिया स्टडीज' में स्नातक करने के बाद मिरे के पास काम की कभी कमी नहीं रही। अंशकालिक पत्रकार के तौर पर उन्होंने *अल-जजीरा, एएफपी, बीबीसी* आदि कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए काम किया। इसी कारण वह नॉर्वे चले आए थे और वहीं बसने का विचार करने लगे थे।

साल 2017 की बात है। एक रिपोर्ट तैयार करने के सिलसिले में मिरे हागडेरा माध्यमिक स्कूल पहुंचे थे। वहां होदान बशीर नाम की लड़की ने एक दिन कुछ झिझकते हुए उनसे कहा- 'भाई, क्या मेरे लिए जीव विज्ञान की किताब खरीद देंगे?' होदान डॉक्टर बनना चाहती थीं। उनकी लरजती आवाज के पीछे की उत्कंठा, शर्म और बेबसी को मिरे से बेहतर भला कौन पढ़ सकता था? अब्दुल्लाही मिरे को लगा अपने नाम और जीवन को सार्थक करने का इससे बेहतर जरिया दूसरा नहीं हो सकता। अब्दुल्लाही का मतलब ही होता है- खुदा का खिदमतगार! उन्होंने होदान के लिए न सिर्फ किताब खरीदी, बल्कि उन जैसे सभी शरणार्थी बच्चों की मदद का प्रण भी उसी पल कर लिया। नॉर्वे में बसने का ख्याल त्यागकर वह अपनों के बीच नैरोबी लौट आए।

लगभग तीन लाख की आबादी वाले दादाब शरणार्थी शिविर के बच्चों के बीच किताबों की किल्लत थी। होदान जैसी 15 लड़कियों को जीव विज्ञान की एक किताब से काम चलाना पड़ रहा था। लड़के तो फिर भी रातों में 'ग्रुप स्टडी' कर सकते थे, मगर सुरक्षा के लिहाज से लड़कियों के लिए यह मुमकिन न था। इसलिए मिरे ने सोशल मीडिया पर 'किताब के लिए दान' मुहिम शुरू की और अपने दूसरे संपर्कों के जरिये करीब 20 हजार किताबें एकत्र कीं। बच्चों में उनको बांटकर मिरे को काफी सुकून मिला। उसने उन्हें 2018 में 'शरणार्थी युवा शिक्षा केंद्र' शुरू करने को प्रेरित किया।

इसी संगठन के जरिये उन्होंने दादाब के तीन सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए लगभग 60,000 किताबें जुटाईं। आज संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, कतर और अफ्रीका की मदद से मिरे के इस संगठन के सात पूर्णकालिक शिक्षक-कर्मचारी और सौ से अधिक स्वयंसेवक शरणार्थी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहां की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं। मिरे की इस पहल ने कई शरणार्थी बच्चों को प्रिंस्टन जैसी प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पहुंचा दिया है। यहां के कई बच्चे आज अच्छे शिक्षक, लेखक व पत्रकार हैं। तालीम ने उनके लिए कई दरीचे खोल दिए हैं।

प्रतिष्ठित नानसेन शरणार्थी पुरस्कार के रूप में संयुक्त राष्ट्र से मिरे को 83 लाख रुपये से अधिक की जो धनराशि मिली है, वह उस रकम से दादाब शिविर के हर उस मासूम बच्चे को किताब थमाना चाहते हैं, जिसे किसी अब्दुल्लाही मिरे की तलाश है।

नानसेन शरणार्थी पुरस्कार के रूप में अब्दुल्लाही मिरे को 83 लाख रुपये से अधिक की धनराशि मिली है। वह इस रकम से दादाब के हर उस मासूम को किताब थमाना चाहते हैं, जिसे किसी अब्दुल्लाही मिरे की तलाश है।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

बाहिया बाकरी
प्रसिद्ध फ्रांसीसी छात्रा

मुसीबत कैसी भी हो हिम्मत न हारिए

मां का भय सागर के एकांत में भी काम कर रहा था। घना अंधेरा था, कभी-कभी कोई सितारा चमक उठता था। वह कभी सिर उठाकर देखती थी, तो हर तरफ पानी ही पानी था, पता नहीं कहां तक पानी होगा, पर मां जब नाराज होगी, तो कुछ नहीं सुनेगी।

जिंदगी हिम्मत और अलहदा सोचने की बुनियाद पर खड़ी हो जाए, तो कामयाब हो जाती है। अफसोस, इस दौर में डर-डरकर जीने वाले इतने हो गए हैं कि गिनना मुश्किल है। कई लोग यही सोचकर हिम्मत हार जाते हैं कि आगे एक मुश्किल मुकाम है। बहुत से लोग बिल्कुल छुई-मुई से होते हैं, किसी मुसीबत की सुगबुगाहट भी मिल जाए, तो पसीने से पस्त हो जाते हैं।

पर यहां तो बहुत ही भयानक मंजर था, एक पूरा हवाई जहाज हिंद महासागर के हवाले हो गया था। न जाने क्या हुआ, मशीन में क्या खराब आई? आधी रात में सब सो रहे थे और जहाज सैकड़ों किलोमीटर ऊपर नाकाम हो चुका था। पता नहीं, कितनों की नींद खुली, पर जब इस 12 वर्षीय लड़की की आंख खुली, तो वह बीच समुद्र में लहरों के बीच गोते खा रही थी। ज्वार का ऐसा जोर था कि लपेटे में आने से बचना मुश्किल था। मुसीबत यह भी कि उसे तैरना नहीं आता था। जब दिमाग को कुछ सूझ नहीं रहा था, तब हाथ को एक ऐसी चीज नसीब हुई, जो शायद हवाई जहाज से ही टूटकर जुदा हुई थी। लड़की ने दोनों हाथों से उसे थाम लिया। खूब खारा पानी और पेट्रोलियम की तेज गंध थी। लड़की को कहां पता था कि यह उसी विमान का टुकड़ा है, जिसमें बैठकर वह फ्रांस से कोमोरोस जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियों को शानदार अंदाज में जीने का इरादा था, पर विमान में तो मां भी थीं! अब मां कहां है? शायद मां विमान से कोमोरोस पहुंच गई होगी। वहां पहुंचकर वह बहुत नाराज हो रही होगी।

आधी रात के अंधेरे में अकेले तिनका के सहारे तैरती उस लड़की का पूरा दिमाग मां की नाराजगी पर जा टिका। मां तो यही सोच रही होगी कि लापरवाह लड़की ने विमान में सीट बेल्ट तक नहीं बांधा था, बेल्ट खोलकर आराम फरमा रही थी, तभी तो एक झटका लगा और खिड़की से बाहर समुद्र में जा गिरी। वह चिंता में पड़ गई कि अब मां को क्या जवाब दूंगी? मां बहुत फटकारेगी, हो सकता है, एकाध थप्पड़ भी जड़ दे। अब तो छुट्टियां भी खराब हो गईं, इसका भी मां को गुस्सा होगा।

मां का भय सागर के एकांत में भी काम कर रहा था। घना अंधेरा था, कभी-कभी कोई सितारा चमक उठता था। वह कभी सिर उठाकर देखती थी, तो हर तरफ पानी ही पानी था, पता नहीं कहां तक पानी होगा, पर मां जब नाराज होगी, तो कुछ नहीं सुनेगी। मां ने विमान में चढ़ने से पहले समझाया भी था, पर पता नहीं क्या हुआ, एक झटका लगा और ऐसा हो गया?

कहा जाता है कि मुसीबत हर जिंदगी में आती है, पर जो लोग मुसीबत से परे भी कुछ सोच पाते हैं, वे ज्यादा आसानी से बच निकलते हैं। उस लड़की के साथ यही हुआ। आधी रात के बाद सुबह हुई, उम्मीद का कुछ उजाला हुआ, धूप खिली, पर तब भी हर तरफ लहरों का तांडव था। सागर में तिनका सहारे नौ घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था, तभी किसी देवदूत की तरह एक नाव नजर आई। लड़की को इतनी खुशी हुई कि उसने हाथ ऊपर कर दिए और जिसके सहारे वह बिना प्रयास तैर रही थी, वह तिनका भी छूट गया। तभी एक ऊंचा ज्वार आया और वह बचावकर्मियों की नजर से ओझल हो गई। ज्वार जब गुजरा, तब वह फिर नजर आई। इस बार उसे देखते ही एक साहसी बचावकर्मी ने छलांग लगा दी और कुछ ही पल में उसे नाव पर बचा लाया। नाम-गांव पूछा गया, पर वह नाव से अस्पताल तक बार-बार बस यही पूछती रही कि मम्मी कहां है?

बहरहाल, दूसरे दिन दुनिया के तमाम अखबारों में खबर थी, यमनिया एयरलाइन का जेट मंगलवार, 30 जून, 2009 तड़के समुद्र में गिर गया, उसमें सवार 152 लोगों की मौत हो गई, पर कुदरत का कमाल देखिए कि बस एक फ्रांसीसी बच्ची बच गई है। चमत्कारी बच्ची बाहिया बाकरी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कंधे की हड्डी टूट गई है, घुटने पर ज्यादा चोट है और शरीर व चेहरे पर खरोंच हैं। बाहिया के पिता को बुलाया गया, तो पिता से भी उसने यही सवाल पूछा कि मम्मी कहां है?

खैर, दो-तीन दिन बाद ही उसे बताया गया कि विमान हादसा हुआ है, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं बचा है। उससे मिलने फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए। पूरी दुनिया को संदेश मिला कि बेहिसाब मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारा करते। भले कहर टूटे, पर जिंदगी की जंग जारी रहनी चाहिए। जिस दौर में मामूली जलभराव भी जानलेवा हो जाता है, उस दौर में बाहिया एक जीवंत मिसाल हैं। उनकी किताब *आई एम बाहिया : द मिरेकल गर्ल* जब आई, तब ख्यात फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने संपर्क किया। बाहिया ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उस भयानक मंजर को याद करना और फिल्माना बेहद डरावना होगा, तो अच्छा है कि उन लम्हों को लफ्जों में ही रहने दिया जाए।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

जहां रस ही नहीं, वहां रसिक कहां

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

अब न कोई सुनता है और न सुनना चाहता है, सब कहना-बोलना चाहते हैं। आज बोलने वाले अधिक हैं और श्रोता कम। कवि हो या वक्ता, सबकी परेशानी यही है कि अब न कोई किसी की कविता सुनता है, न किसी वक्ता को सुनने का धैर्य रखता है, सब बस अपनी सुनाना चाहते हैं और इस चक्कर में यह भूल जाते हैं कि जब आप किसी की नहीं सुनते, तो कोई आपकी क्यों सुने? जब आप ही के पास सुनने का वक्त नहीं, धीरज नहीं, तो दूसरे के पास भी नहीं। यह इन दिनों का नया 'आकाशभाषित' है।

कुछ समय पहले तक हर शहर में साहित्य के श्रोता, साहित्य रसिक, यानी साहित्यानुरागी हुआ करते थे, पर अब न वैसे श्रोता बचे हैं, न रसिक बचे हैं और न साहित्यानुरागी ही बचे हैं। आह! वे दृश्य अब लगभग खत्म हो चले हैं, जब हिंदी साहित्य के किसी विद्वान वक्ता को सुनने हुजूम पहुंचता था, हर हिंदी वाला पहुंचता था!

दिल्ली में ही किसी दिन जैनेंद्र बोलते होते, तो उनको सुनने वाले साहित्य रसिक पहुंचते, किसी दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते होते, तो उनको सुनने वाले साहित्यानुरागी पहुंचते और अज्ञेय को सुनने उनके चाहने वाले पहुंचते थे। यही हाल रामविलास शर्मा को सुनने वालों का था। श्रोता नामवर सिंह को सुनने भी पहुंचा करते थे। ऐसा ही एक दौर वह भी रहा, जब दिनकर, बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन और नीरज काव्य रसिकों के 'हीरो' हुआ करते थे।

एक साहित्यिक मित्र का कहना था, वह इनमें से किसी को भी सुनने के लिए दूर तक जा सकते हैं और उनके लिए किसी से भी भिड़ सकते हैं। ऐसा था कभी हिंदी साहित्य का जलवा! तब साहित्य को 'पॉपुलर' बनाने वाले ऐसे बहुत से कवि-लेखक रहे। कई कवियों की कविता अपने रसिक खुद बनाती थी। वे अपनी कविताओं से, वक्तव्यों से हिंदी वालों को साहित्य में संस्कारित करते थे। हिंदी साहित्य का ऐसा चस्का था कि हर रसिक को अपने प्रिय कवि की दो-चार कविताएं कंठस्थ होतीं। ऐसे लोग स्वयं साहित्य करें या न करें, लेकिन साहित्य का आनंद अवश्य लेते।

वह हिंदी साहित्य का अपना 'पॉपुलिस्ट' दौर था, जब साहित्य जनता के आनंद का, रुचि का विषय बना। उदाहरण के लिए, एक दिन जब कवि राजकमल चौधरी की मृत्यु की खबर हाथरस जैसे शहर में पहुंची, तो पता नहीं क्यों, हमें महसूस हुआ कि कोई अपनी ही बिरादरी का आदमी चला गया है। न तब हम उनको जानते थे, न एक 'बड़े अकवि' के रूप में पहचानते थे, पर खबर मिली, तो लगा कि हिंदी साहित्य का कोई सगा-सहोदरा सिधारा है!

तब हिंदी में एमए करने वाले हमारे जैसे मामूली विद्यार्थी के लिए हिंदी साहित्य एक जादू की तरह था। हम उसे अपनी पूंजी, अपनी ताकत, अपना माल समझते। उस पर हम अपना एकाधिकार समझते। हिंदी साहित्य पर हमें गर्व होता। हम कवियों की दुनिया में हैं, ऐसा महसूस करके इतरा भी सकते थे। ऐसा करके हम अपने को सामान्य आदमी से कुछ विशिष्ट समझते।

ऐसा साहित्यानुराग आज संभवतः बिहार में कहीं बचा हो, तो बचा हो, बाकी कहीं नहीं बचा दिखता। दिल्ली में तो एकदम नहीं। अब हिंदी छात्र का दिल साहित्य में नहीं लगता। कलम-कॉपी की जगह उसके पास मोबाइल, लेपटॉप है, कान में ईयरफोन हैं। टीचर क्या बोलता है, क्या समझाता है, उसे परवाह नहीं। इम्तिहान आएं, तो गूगल है, कुंजियां हैं, गेस पेपर्स हैं और 'पेपर लीक कल्चर' है। जब साहित्य में ही रस नहीं, तो कोई कैसे रसिक बने?

लेखक-कवि की जगह अब हमें ब्लॉगर, पोस्ट राइटर, ट्वीट लेखक, इंस्टाग्रामर और यू-ट्यूबर मिलते हैं। रसिक तो छोड़िए, अब साहित्य का सहृदय तक नहीं मिलता, जो कुछ देर के लिए साहित्य-चर्चा करे, किसी कवि की लाइन को बोले, उसे खुलकर सराह सके। ऐसा सहृदय है, तो साहित्य है; ऐसा रसिक है, तो साहित्य है, वरना सिर्फ साहित्यकारों से साहित्य नहीं बनता!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

लगता है कि मोदी वैसे ही शासन चलाना चाहते हैं, जैसे चलाते रहे हैंः एजेंसियों की मदद से और स्पीकर वगैरह जैसे मुद्दों पर कोई समझौता नहीं। लेकिन विपक्ष अब जोरदार जवाब दे रहा है, और सरकार की असल समस्या हैं कमजोर सरकार, ट्रेन हादसे, परीक्षा घोटाले आदि

— वीर सांघवी, पत्रकार@virsanghvi

कृषि

भारत डोगरा

बहुत अहम है परंपरागत बीज की रक्षा

कभी-कभी बहुप्रचारित विकास के दौर में कुछ बहुत बड़ी क्षति भी हो जाती है जिसके दुष्परिणामों को उस समय नहीं समझा जा सकता है, और इस कारण रोकने का प्रयास भी नहीं किया जाता है। 1965 के आसपास जब हरित क्रांति का आगमन हुआ तब कुछ ऐसा ही हुआ। तेजी से ऐसे बाहरी बीज गांवों में फैलाए गए जो केवल रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के आधार पर बेहतर उत्पादकता दे सकते थे। इसे कृषि विकास का मुख्य आधार मान लेने के कारण उन विभिन्न फसलों की (सबसे अधिक चावल की) हजारों किस्मों का विस्थापन होने लगा जो सैकड़ों, संभवतः हजारों वर्षों के पूर्वज किसानों के अनुभव, ज्ञान और प्रयोगों के फलस्वरूप देश की जलवायु और अन्य जरूरतों के अनुरूप विकसित की गई थीं।

जब तक जैव-विविधता की इस बड़ी क्षति का अहसास हुआ, तब तक असहनीय क्षति हो चुकी थी। एक तरह से देश के सही कृषि विकास के लिए जैव-विविधता का जो आधार सैकड़ों वर्षों के प्रयास से संचित किया गया था, वह नीतिगत गलतियों के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। भूल-सुधार के लिए अनेक सरकारी प्रयोगशालाओं और जीन-बैंकों में लुप्त हो रही अनेक फसलों की किस्मों और उप-किस्मों को बचाने का प्रयास किया गया, पर बीजों की वास्तविक रक्षा तो किसानों के खेतों पर ही होती है। यह ध्यान में रखते हुए अनेक जन-प्रयासों के माध्यम से भी बीजों की रक्षा का प्रयास आरंभ हुआ और इनमें से अनेक प्रयासों को उल्लेखनीय सफलता भी मिली। ऐसा ही एक प्रयास राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मिलन स्थल के जिलों में वागधारा संस्था ने किया। इस संस्था ने महात्मा गांधी के स्वराज के विचार को विशेषकर ग्रामीण आत्म-निर्भरता के रूप में आगे बढ़ाया है। आदिवासी किसानों में इन विचारों को विशेष स्वीकृति मिली है। इसका एक कारण यह है कि वे अपने स्वास्थ्य और पोषण के अधिक अनुकूल मानी जाने वाली अनेक फसलों विशेषकर मोटे अनाजों और मिलेट फसलों को उगाते रहे हैं और इन फसलों के बहुत कम हो जाने के कारण उनके स्वास्थ्य और पोषण की क्षति हो रही थी जिसे वे महसूस भी कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उनके परंपरागत बीजों में कम और अनिश्चित वर्षा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में पनपने की जो क्षमता थी, वह प्रायः बाहरी बीजों में नहीं थी और इस कारण भी इन किसानों की कठिनाइयां बढ़ रही थीं।

इन स्थितियों में वागधारा और उससे जुड़े किसान-समूहों और महिला समूहों ने परस्पर विमर्श कर ऐसी पदयात्राएं निकालीं जिनसे गांव-गांव में परंपरागत बीजों की रक्षा का संदेश फैलाया जा सके। इस विषय पर जनचेतना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

आयोजन किया गया ताकि बीजों की विभिन्न किस्मों की सही पहचान कर उनकी रक्षा का कार्य अधिक नियोजित ढंग से किया जा सके। गांववासियों में यह चेतना अधिक विकसित की गई कि हमारे जिन बुजुर्गों के पास परंपरागत बीजों, लुप्त हो रही फसलों और उनकी विभिन्न किस्मों का ज्ञान बचा हुआ है, उन बुजुर्गों को इसके लिए उचित सम्मान देते हुए यह ज्ञान हमें उनसे प्राप्त करना है ताकि भावी पीढ़ियों के लिए इस ज्ञान की रक्षा की जा सके। ऐसे अनेक किसानों की पहचान की गई जिन्होंने बीज रक्षा के लिए विशेष रुझान दिखाया है। उन्हें बीज-मित्र और बीज-माता के रूप में सम्मानित किया गया। कनु देवी और कनी बहन जैसी अनेक महिलाओं ने बीज-संरक्षण के कार्य में विशेष योगदान दिया। जैमली बहन ने वृक्ष और फल आधारित जैव-विविधता की रक्षा का कार्य किया और इसके लिए नर्सरी भी विकसित की।

इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में जून के महीने में पांच दिनों के बीज उत्सव का आयोजन भी किया गया। बीज उत्सव के अंतर्गत राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी पट्टी के गांवों में विशेष जनसभाओं का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 1000 गांवों के लोगों ने भागेदारी की। इन जनसभाओं में कृषि और उद्यान विभागों के सरकारी अधिकारियों तथा स्थानीय कर्मचारियों और निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की भागेदारी भी प्राप्त की गई।

इस तरह की लगभग 90 जनसभाओं का आयोजन विभिन्न गांवों में किया गया। इनमें विभिन्न किसान अपने साथ विभिन्न फसलों की प्रजातियों के बीज लेकर आए विशेषकर उन मोटे अनाजों के बीज जो हाल के दशकों में कम हो गए हैं। इन बीजों की प्रदर्शनी लगाई गई और विभिन्न किसानों और वागधारा के कार्यकर्ताओं ने इसके बारे में जानकारी दी। जिन किसानों को इनकी जरूरत थी, वे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इन बीजों को अपने खेत में उगाने के लिए ले गए। इस तरह प्रायः सभी किसान अपने साथ कुछ किस्मों के बीज लाए तो कुछ अन्य किस्मों के बीज वे अपने साथ ले गए। यह आदान-प्रदान किसानों के लिए बहुत उपयोगी भी रहा और इससे उनकी बीज और कृषि संबंधी जानकारी में वृद्धि भी हुई। इस तरह के विभिन्न किसानों के छोटे-छोटे सम्मेलनों के समाप्त होने पर यहां उपस्थित किसानों ने परंपरागत देशीय बीजों को बचाने की शपथ भी ली। विजयपाल नामक एक किसान ने कहा कि देशीय बीजों की रक्षा के बारे में बहुत कुछ कहने-करने की इच्छा होती थी, अब हमें इसके लिए उपयुक्त मंच मिल गया है। अब हम इसके माध्यम से युवाओं को इस प्रयास से अधिक जोड़ेंगे। परंपरागत देशीय बीजों को प्रायः बुजुर्गों के ज्ञान से जोड़ा जाता है, पर यदि युवा भी इस प्रयास से जुड़ेंगे तो इस विरासत का नया उपयोग ऐसे अनेक खाद्यों में जुड़ी आजीविका और उद्यम में कर सकते हैं जो स्वास्थ्य और पोषण के महत्त्व को अधिक समझने वाले ग्राहकों के आधार पर पनप सकते हैं। बड़े-बड़े शहरों में ऐसे उपभोक्ता अब स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण मिलेट और अन्य खाद्यों के लिए बेहतर कीमत देने की तैयार हैं।

इस तरह परंपरागत बीजों की रक्षा केवल परंपरा और विरासत की रक्षा का कार्य ही नहीं है, अपितु आधुनिक समय के अनेक स्वास्थ्यवर्धक और बेहतर पोषण गुणों के उद्यम भी इन परंपरागत बीजों की रक्षा के आधार पर पनप सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि परंपरा और आधुनिकता के इस संबंध को भली-भांति, तथ्यों और तर्कों के आधार पर प्रतिष्ठित किया जाए ताकि इसके नीतिगत महत्त्व और इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन, दोनों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। इस कार्य को परंपरा और आधुनिक ज्ञान के सुंदर मिलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। जहां बीजों संबंधी बहुत सा परंपरागत ज्ञान और पूर्वजों का ज्ञान ऐसे अभियान के लिए बहुत जरूरी है, वहां बीजों की पहचान और वर्गीकरण के नये वैज्ञानिक तौर-तरीके भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस तरह वैज्ञानिकों और किसानों, तकनीकी विशेषज्ञों और बुजुर्गों के आपसी सहयोग से यह कार्य भली-भांति आगे बढ़ सकता है।

इस तरह परंपरागत बीजों की रक्षा केवल परंपरा और विरासत की रक्षा का कार्य ही नहीं है, अपितु आधुनिक समय के अनेक स्वास्थ्यवर्धक और बेहतर पोषण गुणों के उद्यम भी इन परंपरागत बीजों की रक्षा के आधार पर पनप सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि परंपरा और आधुनिकता के इस संबंध को भली-भांति, तथ्यों और तर्कों के आधार पर प्रतिष्ठित किया जाए ताकि इसके नीतिगत महत्त्व और इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन, दोनों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। इस कार्य को परंपरा और आधुनिक ज्ञान के सुंदर मिलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। जहां बीजों संबंधी बहुत सा परंपरागत ज्ञान और पूर्वजों का ज्ञान ऐसे अभियान के लिए बहुत जरूरी है, वहां बीजों की पहचान और वर्गीकरण के नये वैज्ञानिक तौर-तरीके भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस तरह वैज्ञानिकों और किसानों, तकनीकी विशेषज्ञों...

बाजार, विज्ञापन और सेक्सिज्म

मीडिया

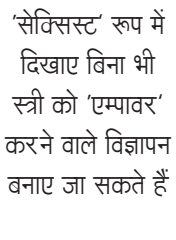

सुधीश पचौरी

इन दिनों खास ब्रांड के ट्रक का विज्ञापन दिखता है जिसमें लड़की ड्राइवर बन ट्रक चलाती दिखती है। यह अकेला विज्ञापन है जिसमें औरत को उपभोग्य की तरह नहीं दिखाया जाता, बल्कि नये 'प्रोफेशनल कर्मी' की तरह दिखाया गया है। यह बताता है कि औरत को 'सेक्सिस्ट' रूप में दिखाए बिना भी स्त्री को 'एम्पावर' करने वाले विज्ञापन बनाए जा सकते हैं

टीवी व प्रिंट मीडिया में इन दिनों आते कुछ विज्ञापनों को छोड़ दें तो अधिकांश की प्रस्तुति 'सेक्सिस्ट' नजर आती है जिनमें औरत अधिकाधिक बेध्य नजर आती है। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंः एक खास ब्रांड की इलायची बेचनी होती है, वहां भी केसर फेंकने के लिए सुंदरी जरूरी होती है जो नाचती-गाती दिखती है। इसी तरह एक टूथपेस्ट बेचने के लिए एक हीरो नाचता हुआ आता है, और फिर कई लड़कों के साथ एक हीरोइन भी उसके साथ डांस करने लगती है, और वो ब्रांडेड टूथपेस्ट दिखने लगता है।

लेकिन इन दिनों कुछ विज्ञापन बहुत ही आगे निकल गए दिखते हैं जैसे एक ब्रांड 'कंडोम' का विज्ञापन जिसमें लड़का लड़की के साथ दर्शकों से कहता है कि अपने पार्टनर से बात करके कंडोम तय करो...। यह विज्ञापन उस कंडोम विज्ञापन से बहुत आगे का है जो बरसों पहले एक अंग्रेजी पत्रिका में छपा था जिसमें नग्न हीरो-हीरोइन के 'नग्न' शरीरों पर अजगर लिपटा हुआ दिखता था। तब उसे लेकर मीडिया में बड़ा हल्ला हुआ था। लेकिन अब कंडोम के विज्ञापन किसी को नहीं हिलाते। उनको तक नहीं जो अपने को 'स्त्रीत्ववादी' कहते हैं और स्त्री की देह को किसी 'उपभोग्य वस्तु' की तरह दिखाने पर ऐतराज किया करते थे। कारण यह है कि इन दिनों बाजार की अतियों के खिलाफ कोई बंदा बोलता नहीं दिखता।

आज का बाजार 'सेक्स संचालित' बाजार है। वस्तुओं के साथ हमको 'सेक्सिस्ट' नजरिया भी बेचा जाता है। यह अपने 'फ्री मारकेट' की 'सेक्सिस्ट कल्चर' की जीत है। बहुत कम विज्ञापन होते हैं जिनमें कोई सुंदर स्त्री या हीरोइन नहीं होती। इसका कारण 'मारकेटिंग की रणनीति' है जो मान कर चलती है कि स्त्री अगर 'सेल्स वूमन' हो तो चीज अच्छी बिकती है क्योंकि चीजों को खरीदने वाले अधिकतर मर्द ही होते हैं।

अब हम कुछ नये ब्रांडेड 'कच्छा बनियानों' की मारकेटिंग के उदाहरण देखेंः एक फिल्मी हीरो की शूटिंग का टाइम हो चुका है। सेट लगा है। वह लेट हो रहा है लेकिन वो येन केन दौड़ता-भागता किसी तरह सेट तक पहुंचता है तो वहां मौजूद लेडी बुदबुदाती है कि वो तो कभी लेट नहीं होता तो वो कहता है कि मैं हमेशा टाइम से पहुंचता हूं। अंत में लेडी कहने लगती हैः 'फिट है बॉस'! यह 'फिट है बॉस' यूं तो बनियान के लिए कहा जाता है लेकिन 'फिट' के मानी सिर्फ इतने नहीं दिखते। इसके भी 'डबल मानी' हैं। ऐसा ही एक विज्ञापन कुछ पहले आया करता था जो इस तरह से खुलता थाः हीरो को कोई बताता है कि डालर का भाव चढ़ रहा है तो वह दौड़ लगाकर एक खास ब्रांड के बक्से को छीन लेता है। उसकी इस फिटनेस पर लेडी मुग्ध हो जाती है...। ऐसे विज्ञापनों में सामान के साथ मर्द की बॉडी पर मरती औरत भी बेची जाती है। यह एक प्रकार का 'निर्लज्ज सेक्सिज्म' है।

ऐसे ही 'गरम इनर्स' का वो विज्ञापन याद आता है, जो इस तरह खुलता हैः किसी बर्फानी हिल स्टेशन पर एक मां अपनी लड़की के साथ दिखती है, जो ठंड से ठिठुर रही है। वहां एक लड़का आता है जो अपने गरम इनर्स को उतार कर लड़की को देता है, तो वह कहती है, हां, अब ये ठंड कट जाएगी...। इसके 'डबल मानी' साफ हैं। लड़की जिस मुद्रा में यह सब कहती है उसमें उसकी आंखों में वासना सी नजर आती है और लड़का तक उसके इशारे समझता है...। इसी तरह एक कच्छे का विज्ञापन आता है जिसमें लड़की लड़के को देखती है। लड़का अलमारी के ऊपर रखे कुछ सामान को उतारता है। इसी प्रक्रिया में उसके कच्छे का ब्रांड लड़की को दिखने लगता है, जिसे देख लड़की की आंखों में एक 'लस्ट', एक 'वासना' सी दिखती है। इसी तरह जब लड़का अपनी बाहें ऊंची करता है, तो उसके कच्छे का खास ब्रांड दिखने लगता है, और लड़की उसके कच्छे के ब्रांड को देख खुश हो जाती है और लड़के का ध्यान खींचने के लिए जोर से नारा लगाती है। लड़की को अपने कच्छे का ब्रांड देखते देख लड़का झेंपता दिखता है।

कच्छा बनियान बेचने के क्या यही तरीके बचे हैं और क्या यही भाषा बची है कि लड़की किसी लड़के के कच्छे को ही देखे और उसके ब्रांड को देख खुश होती दिखे? ऐसे सेक्सिस्ट विज्ञापनों के बीच इन दिनों खास ब्रांड के ट्रक का वो विज्ञापन दिखता है जिसमें लड़की ड्राइवर बन ट्रक को चलाती दिखती है। यह अकेला विज्ञापन है, जिसमें औरत को उपभोग्य पदार्थ की तरह नहीं दिखाया जाता, बल्कि नये 'प्रोफेशनल कर्मी' की तरह दिखाया गया है। यह बताता है कि औरत को 'सेक्सिस्ट' रूप में दिखाए बिना भी स्त्री को 'एम्पावर' करने वाले अच्छे विज्ञापन बनाए जा सकते हैं।

मोदी-पुतिन शिखर वार्ता

वैश्विकी

डॉ. दिलीप चौबे

प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा 8 और 9 जुलाई को संभावित है। इसी समय वाशिंगटन में नाटो सैन्य संगठन की शिखर वार्ता भी होने वाली है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक महत्त्वपूर्ण सैन्य सहयोग समझौता हो सकता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में घरेलू और विदेश मोर्चे पर चुनौतियों का सामना है। आशानुरूप जनादेश नहीं मिलने के कारण उन्हें घरेलू राजनीति में अपना जनाधार बनाए रखने और यथासंभव उसका विस्तार करने की चुनौती पेश है। कारगर विदेश नीति के लिए जरूरी है कि किसी नेता को अपने देश में जनता का भरपूर समर्थन मिले। भारत में आम तौर पर विदेश नीति को लेकर मतैक्य रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में राजनीतिक दलों में वैमनस्यता और अविश्वास बढ़ा है। इसका असर विदेश नीति पर भी दिखाई दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भारत के भरोसेमंद दोस्त रूस और उसके नेता ब्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की थी। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से भी यह आरोप लगाया गया था कि अमेरिका भारतीय चुनाव प्रक्रिया में दखलअंदाजी कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति की निरंतरता को कायम रखने के लिए बहुत चतुराई का प्रदर्शन किया। चुनाव परिणाम आने से पहले ही ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह समझौता किया गया। यदि चुनाव के बाद विपक्षी सरकार बनती तो यह समझौता होता या नहीं, यह अनुमान का विषय है। सरकार बनने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के रूप में रूस का चुनाव करना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही रूस के साथ अपने संबंधों को पुख्ता बनाना चाहते हैं। अमेरिका सहित पश्चिमी देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बेरुखी का रवैया अपनाने लगे हैं। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विरोध में बदल सकता है। ऐसे में मोदी की जवाबी रणनीति यह प्रतीत होती है कि रूस के साथ संबंधों को और मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की थी जिसके कारण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारत अमेरिका की चुनौती का सामना कर सका।

प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा 8 और 9 जुलाई को संभावित है। इसी समय वाशिंगटन में नाटो सैन्य संगठन की शिखर वार्ता भी होने वाली है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक महत्त्वपूर्ण सैन्य सहयोग समझौता हो सकता है। इसके अंतर्गत रूस के युद्धपोत भारतीय बंदरगाहों में ठहराव और मरम्मत आदि की सुविधा हासिल कर सकते हैं। भारत ने कुछ वर्ष ऐसा ही समझौता अमेरिका और कुछ अन्य देशों के साथ भी किया था। लेकिन मौजूदा रणनीतिक परिदृश्य में रूस की नौसेना को यह सुविधा दिया जाना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। रूस ने हाल में उत्तर कोरिया के साथ सैन्य गठबंधन किय है, जो जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसी तरह रूसी सैनिकों ने हिन्द महासागर और अरब सागर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। रूस और ईरान इस समुद्री क्षेत्र में अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे हिन्द प्रशांत क्षेत्र में रूस की मौजूदगी पिछले शीत-युद्ध वाले दौर की याद दिलाती है। इन हालात में रूस और भारत के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग पर अमेरिका क्या रवैया अपनाता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान ही दोनों देश एस-400 मिसाइल प्रणाली के साझा उत्पादन के संबंध में भी समझौता कर सकते हैं। मेक इन इंडिया मिशन की यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। कुछ महीनों बाद रूस में ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। लगातार व्यापक बन रहे ब्रिक्स संगठन के जरिए ग्लोबल साउथ आर्थिक मोर्चे पर घरेलू करंसी को मजबूत बनाने और अमेरिकी मुद्रा डॉलर का वर्चस्व समाप्त करने का फैसला भी कर सकते हैं।

मौलिक अधिकार हैं सुरक्षित फुटपाथ

विमर्श

अली खान

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब प्रधानमंत्री या कोई वीआईपी आता है, तो सड़कों और फुटपाथ को चकाचक कर दिया जाता है। यदि एक दिन यह हो सकता है, तो सभी लोगों के लिए हर रोज क्यों नहीं हो सकता। आखिरकार, नागरिक टैक्स देते हैं, और साफ-सुथरे और सुरक्षित फुटपाथ पर चलना उनका भी मौलिक अधिकार है।

बता दें कि जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ फुटपाथ मुहैया कराना राज्य प्राधिकरण का दायित्व है। राज्य सरकार के केवल यह सोचने से काम नहीं चलने वाला कि शहर में फुटपाथ घेरने वाले अनिधकृत फेरीवालों की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने शहर में अनिधकृत रेहड़ी-पटरी वालों की समस्या पर पिछले वर्ष स्वतः संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा कि उसे पता है कि समस्या बड़ी है, लेकिन राज्य और नगर निकाय सहित अन्य अधिकारी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हम अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलने को कहते हैं, लेकिन चलने को फुटपाथ ही नहीं होंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे? इस बीच आम-आदमी के मस्तिष्क में इस सवाल का कौंधना स्वाभाविक है कि आखिर, मूल अधिकार से क्या अभिप्राय है?

दरअसल, मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक (सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक) और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों के एक समूह को भी संदर्भित करते हैं। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला को भी निर्मित करते हैं तथा नागरिकों की राज्यों के मनमाने कार्यों एवं नियमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बुनियादी मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करते हैं। एक राष्ट्र के भीतर लोकतंत्र, न्याय और समानता को बनाए रखने के लिए ये अधिकार संविधान के अभिन्न अंग हैं। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, गरिमा और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इनके असंख्य महत्त्व के कारण ही उन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। ये अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित हैं, जो देश के मूलभूत शासन को संदर्भित करते हैं।

दरअसल, हकीकत यह है कि शहरी भारत में पैदल चलने के लिए वर्तमान में कई बाधाओं और रुकावटों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण अक्सर किसी की सुरक्षा को जोखिम में डालना पड़ता है। यहां तक कि कभी-कभी किसी की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। भारतीय शहरों में पैदलयात्रियों की उपेक्षा केवल पैदलयात्रियों की सुविधाओं को कम प्राथमिकता देने और उनके खराब क्रियान्वयन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक बड़े प्रणालीगत मुद्दे का भी प्रतिबिंब है। दरअसल, भारत में पैदलयात्रियों के लिए कानूनी अधिकारों और उपायों की व्यापक व्यवस्था का अभाव है। कमोबेश सभी शहरों की अधिकांश सड़कों पर अतिक्रमण का बोलबाला है। अतिक्रमण के चलते फुटपाथ गुम हो गए हैं। इन पर जनता का अधिकार है। मौजूदा वक्त में फुटपाथ की समस्या नासूर बन चुकी है। चिंता की बात है कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है। लिहाजा, सरकार को चाहिए कि जनता के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित फुटपाथ मुहैया करवाए। फुटपाथ पर बैनर लगाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।

झल्लन ने जारी किया शपथपत्र

बतंगड़ बेतुक

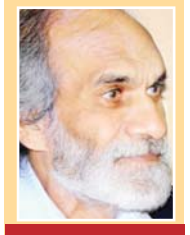

विभांशु दिव्याल

जब हम ठीये पर पहुंचे तो झल्लन पहले से पहुंचा हुआ था, हाथ में एक कागज था और वह पढ़ने में डूबा हुआ था। जब उसने कुछ देर तक हमारी उपस्थिति का संज्ञान नहीं लिया तो हमने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। झल्लन चौंककर अपनी डूब से बाहर आया और हमें जुहार बोलकर मुस्कुराया। हमने कहा, 'किसी ने वसीयतनामा लिख दिया है तेरे नाम जो तू लगातार पढ़े जा रहा है और सर तक नहीं उठा रहा है?'

झल्लन बोला, 'ददाजू, न तो हमारे पप्पा पूंजीपति थे जो अपनी वसीयत हमारे नाम कर जाते और न हमारे अब्बा नेता थे जो अपनी नेतागीरी की विरासत हमें सौंप जाते। दरअसल, चुनाव काल के बाद शपथ काल आया और न जाने किस-किसने शपथ ले ली पर हमें किसी ने न्योता तक नहीं भिजवाया।' हमने कहा, 'तू किसके शपथ लेने की बात कर रहा है जिसका न्योता न मिलने पर तेरा मन दुख से भर रहा है?' झल्लन बोला, 'देखिए ददाजू, बकौल इंडी गठबंधन चुनाव में मोदी जी की नैतिक हार हुई पर मोदी जी नैतिकता पर जरा भी ध्यान नहीं दिये और पूरी ठसक से अपने गठजोड़ियों के संग तीसरी बार शपथ ले लिये। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली तो उनके साथ हमारे एक्टर भाई पवन कल्याण भी शपथ ले लिये, उधर ओडिशा में मोहन चरण माझी ने शपथ ली तो अरुणाचल में प्रेमा खांडू शपथ ले लिये। लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो नाते-रिश्तेदारों की उपस्थिति में सारे सांसण शपथ ले लिये और न बुलाकर हमें फिर से गच्चा दे दिये।'

हमने कहा, 'तो इसमें तुझे क्या तकलीफ हो रही है, जो जीते हैं वे शपथ ले रहे हैं इसमें तेरी आत्मा क्यों रो रही है?' झल्लन बोला, 'ददाजू, बिना हमारी शपथ के यह शपथकाल समाप्त हो रहा है, बस इसी बात को लेकर हमारा मन रो रहा है। सोच रहे हैं कि हम भी कहीं शपथ ले रहे होते तो हमारे शपथ ग्रहण समारोह में नैतिक जीत के अगुआ राहुल बबुआ ही मुख्य अतिथि हो रहे होते।' हमने कहा, 'शपथ तो तू तब लेता जब कोई टिकट देकर तुझे चुनाव लड़ाता और तू ईवीएम के मुंह से अपनी जीत निकाल लाता।'

वह बोला, 'यही तो अफसोस है ददाजू, चुनाव न लड़ पाने का गम तो हमें भी सता रहा है पर शपथ लेने का भाव मन से नहीं जा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि कोई हमारा शपथपत्र तैयार नहीं करता सो अपना शपथपत्र खुद तैयार कर लाये हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमें शपथ दिलाने कोई राज्यपाल तो आएगा नहीं सो हम शपथ लेने आपके पास चले आये हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि हमें हमारे शपथपत्र के अनुसार शपथ दिलवाएं और हमारे दिल को राहत पहुंचाएं।'

हमने कहा, 'झल्लन, लगता है चुनावों के नंग नाच और गाली गलौज ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है इसी से तेरे दिमाग में शपथ लेने का खयाल भर गया है। अब थोड़ी सी शांति आयी है तो हम चाहते हैं कि तू सारे उलजुलूल राजनीतिक खयालों को अपने दिमाग से उलीचकर बाहर करे और खुद को सम पर लाने के लिए कुछ दिन तक थोड़ा सा मौन रखे और कुछ आराम करे।' झल्लन बोला, 'ददाजू, हम भी तो यही चाहते हैं पर जब तक आप हमें शपथ नहीं दिलवाएंगे हम चैन नहीं पाएंगे।' हमने कहा, 'ला दिखा, शपथ के नाम तू क्या कर लाया है, अपने शपथपत्र में तू क्या लिख लाया है?' वह बोला, 'देखिए ददाजू, आप तो बस शपथ दिलाने वालों की तरह सिर्फ 'मैं..' बोलते जाइए और हम क्या शपथ ले रहे हैं आराम से सुनते जाइए।' हमने हंसते हुए कहा, 'चल ठीक है, हम कहे रहे हैं 'मैं...', झल्लन मियां अब आप शपथ लें।' झल्लन ने शुरू किया, 'मैं झल्लन, ईश्वर के नाम पर झूठी शपथ नहीं ले सकता इसलिए अपनी शपथ अपने नाम पर ले रहा हूं और जो कह रहा हूं सच्चे मन से कह रहा हूं। जब भी चुनाव आएंगे तो किसी भी झूठे, चालाक, मक्कार, फरेबी नेता के झांसे में नहीं आऊंगा, इनके भद्दे वादों और झूठे आश्वासनों पर कान नहीं टिकाऊंगा, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को मुंह नहीं लगाऊंगा। जब ये ईवीएम-ईवीएम चिल्लाएं तो समझ जाऊंगा कि ये हार से डर रहे हैं, जब ये सद्भाव और मोहब्बत की बात करें तो जान लूंगा कि ये मेरे मन में नफरत भर रहे हैं। अगर ये कहें कि ये संविधान बचाना चाहते हैं तो समझूंगा कि खुद को बचाना चाहते हैं और जब ये देश को बचाने की बात कहें तो समझ जाऊंगा कि ये देश को चबा जाना चाहते हैं। जब टेलीविजन पर इनके चेहरे दिखाई दें तो आंख बंद कर लूंगा और जब बहस में इनके तीखे, कड़वे, जहरीले बोल सुनाई दें तो मैं कान बंद कर लूंगा।'

हमने फिर कहा, 'मैं'...', झल्लन ने शपथ आगे बढ़ाई, 'मैं झल्लन, कभी भी चुनावी नेताओं के बहकावों-फुसलावों में नहीं आऊंगा, इनसे बचने के लिए मैं सबसे पहले अपना दिमाग बचाऊंगा, वोट डालने से पहले मैं इंसान और उसकी फितरत को परखूंगा और अगर कोई भी पसंद नहीं आएगा तो नोटा का बटन दबाऊंगा और घर निकल जाऊंगा।'

वह बोला, 'देखिए ददाजू, आप तो बस शपथ दिलाने वालों की तरह सिर्फ 'मैं..' बोलते जाइए और हम क्या शपथ ले रहे हैं आराम से सुनते जाइए।' हमने हंसते हुए कहा, 'चल ठीक है, हम कहे रहे हैं 'मैं...', झल्लन मियां अब आप शपथ लें।' झल्लन ने शुरू किया, 'मैं झल्लन, ईश्वर के नाम पर झूठी शपथ नहीं ले सकता इसलिए अपनी शपथ अपने नाम पर ले रहा हूं और जो कह रहा हूं सच्चे मन से कह रहा हूं। जब भी चुनाव आएंगे तो किसी भी झूठे, चालाक, मक्कार, फरेबी नेता के झांसे में नहीं आऊंगा, इनके भद्दे वादों और झूठे आश्वासनों पर कान नहीं टिकाऊंगा, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को मुंह नहीं लगाऊंगा। जब ये ईवीएम-ईवीएम चिल्लाएं तो समझ जाऊंगा कि ये हार से डर रहे हैं, जब ये सद्भाव और मोहब्बत की बात करें तो जान लूंगा कि ये मेरे मन में नफरत भर रहे हैं। अगर ये कहें कि ये संविधान बचाना चाहते हैं तो समझूंगा कि खुद को बचाना चाहते हैं और जब ये देश को बचाने की बात कहें तो समझ जाऊंगा कि ये देश को चबा जाना चाहते हैं। जब टेलीविजन पर इनके चेहरे दिखाई दें तो आंख बंद कर लूंगा और जब बहस में इनके तीखे, कड़वे...

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 316 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewspaperPdf

वो रेवड़ी वाली राजनीति वाला ट्वीट करना है या रहने दूं? इस तरह के बजट ने हिमाचल, कर्नाटक को यदि बर्बाद किया है तो महाराष्ट्र उस राह पर क्यों जा रहा है? अवश्य ही कोई तर्क दे दिया जाएगा, परंतु फ्री-फ्री-फ्री की राजनीति उस राज्य को भी नहीं करना चाहिए। जेके पास बजट सरप्लस हो। आप जनता को पंगु बना रहे हो जहां कुछ किए बिना भी जीवन चल जाएगा!

—अजीत भारती, टिप्पणीकार @ajeetbharti

विमर्श

अंशुमाली रस्तोगी

सोशल मीडिया से संबंधों में तनाव

सोशल मीडिया, आधुनिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे खुले मंचों ने हमारी जीवनशैली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इन मंचों ने जहां हमें विश्व के किसी भी कोने से जोड़ने में मदद की है, वहीं इनका अत्यधिक उपयोग हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में तनाव भी ला रहा है।

आजकल, लोग दिन भर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। अपनी हर छोटी-बड़ी गतिविधि को पोस्ट करते हैं। दूसरों की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। इस प्रक्रिया में, वे अक्सर अपने वास्तविक जीवन के रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक समय था जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में विश्वास रखते थे। लेकिन अब, वही समय स्क्रीन के सामने बिताया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि संबंधों में व्यक्तिगत संपर्क कम से कमतर हो गया है।

सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से संबंधों में विश्वास की कमी भी बढ़ी है। कई लोग अपने पार्टनर की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जिससे शक और जलन की भावना उत्पन्न होती है। अगर किसी का पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति की पोस्ट पर अधिक ध्यान देता है, तब शक पैदा होता है कि उनके रिश्तों के बीच आखिर, क्या खास चल रहा है। इस प्रकार के शक संबंधों में तनाव और दूरी का कारण बनते हैं जिसकी परिणति किसी न किसी खराब रूप में सामने आती है।

सोशल मीडिया पर दिखावा भी एक बड़ी समस्या है। लोग अक्सर अपने जीवन के केवल सकारात्मक पहलुओं को ही पोस्ट करते हैं। यह एक आभासी वास्तविकता का निर्माण करता है, जो दूसरों के लिए ईर्ष्या और असंतोष का कारण बनता है। जब लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, तो अपने रिश्तों में कमियों को महसूस करने लगते हैं। यह स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वे मानने लगते हैं कि उनका जीवन और संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, जितने कि सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के कारण संबंधों में संचार का तरीका भी बदल गया है। जहां पहले लोग एक-दूसरे से मिल कर या फोन पर बात किया करते थे, अब वे व्हाट्सएप या मैसेंजर के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह डिजिटल संचार प्रायः गलतफहमी भी पैदा करता है, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज में भावनाओं की सही अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। कई बार छोटे-छोटे मुद्दे भी बड़े विवाद का कारण बन जाते हैं।

सोशल मीडिया पर बिताया गया समय भी कम गंभीर समस्या नहीं। जब लोग अपने फोन या कंप्यूटर पर घंटों बिताते हैं, तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताने वाले समय को कम कर देते हैं। इसका सीधा असर उनके संबंधों पर पड़ता है। परिवार के सदस्य या दोस्त महसूस कर सकते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे संबंधों में दूरियां बढ़ती हैं।

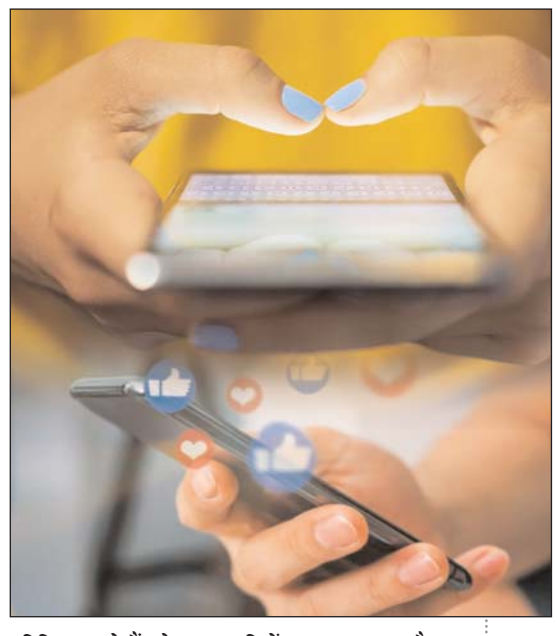

सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और अफवाहों का प्रसार भी संबंधों में तनाव बढ़ा रहा है। कभी-कभी लोग बिना सत्यापन के किसी जानकारी को सच मान लेते हैं, और इस पर

प्रतिक्रिया करते हैं, जो गलतफहमियों का कारण बनता है। यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील संबंधों, जैसे पति-पत्नी या करीबी दोस्तों के बीच तनाव बढ़ाती है। हालांकि, सोशल मीडिया का प्रभाव केवल नकारात्मक ही नहीं है। यह सही उपयोग के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। मसलन, लंबे समय से बिछड़े हुए दोस्तों या परिवार के सदस्यों से पुनः संपर्क स्थापित करना आसान हो गया है। मीडिया पर विभिन्न रुचियों और शौकों से संबंधित समूहों में शामिल होकर लोग नये दोस्त भी बना सकते हैं, और अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा सकते हैं।

फिर भी, यह महत्त्वपूर्ण है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित तरीके से करें। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने वास्तविक जीवन के संबंधों को प्राथमिकता दें और सोशल मीडिया का उपयोग केवल एक माध्यम के रूप में करें, न कि एक विकल्प के रूप में। समय प्रबंधन और व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है ताकि हमारे संबंध मजबूत और स्वस्थ बने रहें। सोशल मीडिया के प्रभाव को समझना और उसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है। अगर हम इसका सही उपयोग कर पाते हैं, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर इसका अत्यधिक और गलत उपयोग किया जाए, तो यह हमारे संबंधों में तनाव और असंतोष का कारण बन सकता है। बहुत हद तक बन भी रहा है। इसलिए, हमें अपनी डिजिटल आदतों पर पुनर्विचार करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित न हों। संबंधों को जीवंत और सकारात्मक बनाए रखें। ■

सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से संबंधों में विश्वास की कमी भी बढ़ी है। कई लोग अपने पार्टनर की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जिससे शक और जलन की भावना उत्पन्न होती है। अगर किसी का पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति की पोस्ट पर अधिक ध्यान देता है, तब शक पैदा होता है कि उनके रिश्तों के बीच आखिर, क्या खास चल रहा है। इस प्रकार के शक संबंधों में तनाव और दूरी का कारण बनते हैं जिसकी परिणति किसी न किसी खराब रूप में सामने आती है। सोशल मीडिया पर दिखावा भी एक बड़ी समस्या है

संजीव कुमार मिश्र

महिला सशक्तिकरण और पानी की पहल

गर्मी का पारा चढ़ते ही देश के कई प्रदेशों में जल संकट गहराने लगा है। इन प्रदेशों में महाराष्ट्र भी शामिल है। यहां के कई इलाके पानी के गंभीर संकट से लगातार जूझते रहे हैं। ऐसे में वहां से एक सकारात्मक खबर आई है। यह खबर व्यापार और कारोबार के बीच आकार ले रहे सामाजिक दायित्व की बड़ी मिसाल है। मिसाल इसलिए भी बाजार में जिस नाम और उत्पाद की धूम हो, वह जब सेवा और मानवीय सरोकार के क्षेत्र में उतरता है, तो कैसे इंसानी फिजा बदलने लगती है। बाजारवादी शोरगूल से दूर बदलाव की इस कहानी के एक छोर पर जहां पानी और उसका महत्त्व है, तो दूसरे छोर पर महिला सशक्तिकरण की गंभीर पहल।

मीडिया और सोशल मीडिया के कई मंचों पर पिछले कुछ समय से 'आनंदना' की चर्चा है। नाम के अनुरूप ही 'आनंदना' का प्रयास भी है। महाराष्ट्र के सुदूर इलाकों में यह प्रयास ग्रामीण जीवन में बदलाव और बेहतरी का सुलेख रच रहा है। बात करें इस पूरे अभियान की तो कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के तहत काम करने वाली अपनी शाखा 'आनंदना' के माध्यम से धुले और जलगांव के कई गांवों में चेक डैम और तलाबों के निर्माण की पहल की है। यह पहल 'आनंदना' के एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा है। गांवों में जल स्रोतों के निर्माण से एक तरफ जहां क्षेत्र के भूजल स्तर में वृद्धि हुई है, तो वहीं लोगों को पीने और दूसरे जरूरी कार्यों के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। कृषि गतिविधियों के लिए बढ़ी जल उपलब्धता से इलाके में कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है। एक ऐसे समय में जब कॉरपोरेट जगत की कुबेरी तरक्की पर बात करते हुए लोग इस बात की आशा करते हैं कि समृद्धि का यह पसारा बाजार और सेंसेक्स से आगे गांव-समाज तक पहुंचे, तो हमारे समय में सेवा और सरोकार का एक जरूरी और बड़ा अमल पूरी होगा। महाराष्ट्र के हिगांव, शिरपुर तालुका, हिवरखेड़ा, चोपडा तालुका का मोरचिडा गांव, सत्रसेन गांव, जलगांव और खामखेड़ा तालुका, धुले जिला के कई इलाकों में फाउंडेशन ने 6 चेक डैम और तालाब बना कर क्षेत्र के लोगों को संजीवनी दी है।

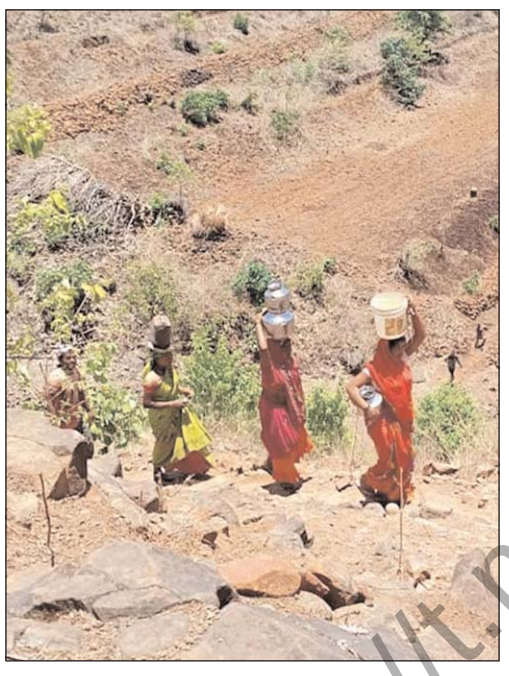

धुले और जलगांव के करीब स्थित इन जल स्रोतों से आसपास के कई गांवों को पीने और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। इस पहल से जल भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई जो वर्तमान में 69 करोड़ लीटर है। इस परियोजना से 1165 एकड़ भूमि को भी लाभ हुआ, जिससे 5000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। इस कदम से जहां क्षेत्र के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं महिलाओं को भी कोसों दूर से पानी लाने की समस्या से मुक्ति मिली है। यहां की महिलाएं बताती हैं कि उनका जो समय पहले पानी लाने में बर्बाद होता था, वह समय आज हुनरमंदी से अर्थ उपार्जन के काम आ रहा है। महिला सशक्तिकरण के इस मॉडल की चर्चा आज मिसाल के रूप में हो रही है। 'आनंदना' की इस पानीदार पहल ने इस पूरे क्षेत्र की महिलाओं के जीवन पर जो सकारात्मक प्रभाव डाला है, वह अब दिख रहा है। प्रयास के बीज फलदायी हो रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक यहां की महिलाओं को पेयजल के लिए जिस तरह के संकट से जूझना पड़ता था, वैसी स्थिति आज नहीं है। भूजल स्तर में सुधार से बोरवेल और घर में नल से पानी मिल रहा है। पानी की आमद से जीवन की शुष्कता ही नहीं मिटी है, लोगों के जीवन में समृद्धि और उल्लास के नये रंग भी बिखरे हैं।

धुले क्षेत्र की खामखेड़ा निवासी पूजा पावरा बताती हैं कि इलाके में चेक डैम और तालाब निर्माण से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। अब पानी के लिए उन्हें लंबी और कठिन यात्राएं नहीं करनी पड़तीं। घर में ही नल से जल की व्यवस्था हो गई है, जिसमें दिन में दो बार पानी आता है। इससे उनका समय तो बचता ही है, उनकी मुसीबत भी कम हुई है। इसी तरह शिरपुर, खामखेड़ा निवासी सुभाष साधारण किसान हैं। वे कबूलते हैं कि बांध बनने से पहले उनकी स्थिति बेहद खराब थी। पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिससे खेती करना कठिन था। बांध बनने से सुभाष को अब अच्छी उपज मिल रही है। सुभाष के ही शब्दों में कहें तो हम गन्ना और मक्का आसानी से उगाते हैं। पानी की उपलब्धता बढ़ने से हम अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। पहले उन्हें भी दिन भर पानी ढोने के काम में ही लगा रहना पड़ता था। गांव से पलायन भी कम हुआ है।

धुले के शिरपुर तालुका के हिगांव की निवासी लया भील मछली पकड़ने का काम करती हैं। अपने क्षेत्र के बारे में बताती हैं कि यहां ज्यादातर छोटी काली मछलियां ही होती हैं, वे भी सर्दी के दिनों में ही मिलती थीं। बांध निर्माण के बाद जल क्षेत्र बढ़ा और अब हमें ज्यादा मछलियां मिलने लगीं। सी द डिफरेंस हैशटैग के साथ आगे बढ़ रही यह पहल उस बड़ी सोच का हिस्सा है, जिसमें लैंगिक और सामाजिक बदलाव के कई कंगूरे खड़े हो रहे हैं। खास तौर पर पानी को लेकर ऐसे प्रयास का महत्त्व इसलिए भी है कि देश के कई राज्य विशेष रूप से महाराष्ट्र में जल संकट की गंभीर स्थिति है। महाराष्ट्र का लगभग 84 फीसद हिस्सा वर्षा जल पर निर्भर है। राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी कृषि पर निर्भर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 60 फीसद है। ऐसे में जल स्रोतों के विकास से कोका-कोला इंडिया न सिर्फ भारत के जल समृद्ध बनने के सपने को साकार करने में जुटी है, बल्कि देश की महिलाओं के लिए बढ़ने के नये रास्ते भी खोल रही है। ■

पुस्तक समीक्षा | डॉ. शारदा प्रसाद

रामगढ़ अधिवेशन का जीवंत दस्तावेज

बसंत हेतमसरिया की यह दूसरी पुस्तक है। रामगढ़ शहर के इतिहास-भूगोल के साथ ही यह आजादी की जंग और द्वितीय विश्व युद्ध की गहराई से पड़ताल करती है। रामगढ़ की माटी में जन्मे और रचे-बसे लेखक के मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण यह पुस्तक रूपाकार ग्रहण कर पाई। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि पुस्तक को स्वरूप ग्रहण करने में कोविड-19 का बड़ा हाथ है। लॉकडाउन के क्रम में घर पर रहने के दौरान उन्हें इसके लेखन का अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि गंभीर विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छाई की किरणें समाहित होती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ और यह पुस्तक हमारे सामने है।

पुस्तक 1940 में रामगढ़ में हुए कांग्रेस पार्टी के 53वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर केंद्रित है। अधिवेशन को आधार बनाकर तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और द्वितीय विश्व युद्ध के बढ़ते अलगाव के साए में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार परवान चढ़ा, इसकी पड़ताल की गई है। इस दौरान प्रमुख नेताओं के मतभेद उभर कर सामने आने का प्रामाणिक विवरण भी पुस्तक को महत्त्वपूर्ण बनाता है। रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन ही वह पहला अधिवेशन था, जब कांग्रेस के ही एक धड़े ने उसकी नीतियों के विरोध में समानांतर सम्मेलन आयोजित किया। 1940 का वर्ष इसलिए भी महत्त्वपूर्ण रहा कि इसी वर्ष लाहौर में मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन में पहली बार विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। इसके परिणामस्वरूप आजादी के समय देश का विभाजन और पाकिस्तान के रूप में नये राष्ट्र का निर्माण देखा गया। इसके अलावा, 1940 में ही जर्मनी की नाजी सेना को अधिक सफलता मिली। उसने इटली की फासीवादी ताकतों एवं इसके साथ शामिल अन्य देशों के साथ मिल कर यूरोप में भारी तबाही मचाई और यूरोप के अनेक देशों की आजादी छीन ली।

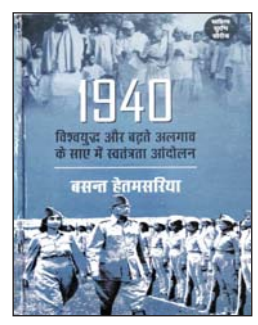

ब्रिटिश सरकार ने भी देश में किसी प्रकार के सलाह-मशविरे के बिना ही देश को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। इसका प्रभाव कांग्रेस पर भी पड़ा। नतीजा हुआ कि कांग्रेस में मतभेद के स्वर उभरने लगे। रामगढ़ अधिवेशन में देश के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण राजनेताओं का आगमन हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। महात्मा गांधी इससे पहले त्रिपुरी में आयोजित 52वें अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सके थे। लेकिन रामगढ़ अधिवेशन में आए। यहां वह लगातार रुके रहे तथा अपने भाषणों एवं दिशा-निर्देशों से एक नई राह प्रशस्त की। उस समय रामगढ़ जैसे अत्यंत छोटे से जंगलों-पहाड़ों से घिरे कस्बे में वृहद् आयोजन करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। किंतु यह सफल रहा। इस अधिवेशन में एक लाख से अधिक लोग उपस्थित हुए। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उस दिन 19 मार्च, 1940 को मूसलाधार वर्षा हुई थी। दामोदर तथा हुरहुरी नदी में बाढ़ आ गई थी।

इस कारण विपरीत परिस्थितियों में भी यह अधिवेशन सफल रहा था। नेताओं के ठहरने के लिए झोपड़ियों का निर्माण किया गया था, जिनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। बिजली की व्यवस्था भी चाक-चौबंद थी। कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया था। पदक के साथ-साथ नकद राशि भी पुरस्कार स्वरूप दी गई। अनेक नेताओं के भाषण, उनके क्रियाकलाप, ठहराव, अधिवेशन की तैयारियों का विस्तृत लेखा-जोखा पुस्तक में रोचक ढंग से किया गया है। लिहाजा, यह पुस्तक सिर्फ इतिहास की पुस्तक नहीं है वरन भारतीय राजनीति की नीतियों और उद्देश्यों का भी जीवंत दस्तावेज है। पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है। आकर्षक आवरण पृष्ठ, सुंदर छपाई, कुछ महत्त्वपूर्ण चित्रों के कारण सुंदर बन पड़ी है। स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिख, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत, विचारक डॉ. पुरुषोत्तम अग्रवाल, अरविंद मोहन और महेश दर्पण की टिप्पणी पुस्तक को गरिमा की ऊंचाई प्रदान करती है।

पुस्तक : 1940 : विश्व युद्ध और बढ़ते अलगाव के साए में स्वतंत्रता आंदोलन
लेखक : बसंत हेतमसरिया
प्रकाशक : सुरभि प्रकाशन (किताबघर प्रकाशन समूह, दिल्ली)
मूल्य : 450/-रुपये ■

राग रंग | आलोक पराड़कर

सामता प्रसाद की स्मृति

बनारस कई अर्थों में अनूठा है। परस्पर विरोधी बातें भी इसमें इस प्रकार रची-बसी हैं कि कई बार आश्चर्य हो उठता है लेकिन वास्तव में यह इसके स्वभाव में ही है। तभी तो प्रसिद्ध साहित्यकार हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसे एक टांग पर खड़ा कहा है जो अपनी दूसरी टांग से बेखबर है। परंपरा और विरासत की टांग पर टिका हुआ, विकास की ओर उठी हुई टांग से बेपरवाह। पक्के महाल में चले जाइए, गंगा किनारे टहल आइए तो लोग गमछा पहने घूमते मिल जाएंगे, किसी गंवई या कस्बाई जीवन का आभास मिलेगा तो तेजी से बनते मल्टीप्लेक्स और मॉल में घूमिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शो-रूम देखिए, किसी महानगर जैसी चकाचौंध मिलेगी। बनारस इस चकाचौंध में शामिल भी है, और इससे अलग भी है। वह कभी इनमें ठहाके लगाता है तो कभी भाग कर गंगा किनारे जाकर सुस्ताने लगता है। बनारस को जानना इसके अंतरविरोधों और विरोधाभासों को जानना भी है। कवि केदारनाथ सिंह ने भी इसे-'आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में'-कहा है।

कुछ वर्षों पूर्व तक तबले का बनारस घराना अपने जिन शिखर पुरुषों के कारण जाना जाता था, उनके जीवन और वादन को देखें तो वह भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। बनारस के जिस कबीरचौरा में हिन्दुस्तान शास्त्रीय संगीत के विख्यात कलाकारों का बसेरा रहा, आसपास की गलियों में रहने वाले पं. किशन महाराज अपने पड़ोसी पं. सामता प्रसाद, जिन्हें गुदई महाराज भी कहा जाता था, से थोड़े ही छोटे थे। पं. किशन महाराज 1923 में जन्मे थे जबकि पं. सामता प्रसाद के जन्म वर्ष को लेकर उनकी जन्मतिथि की तरह ही एकमत नहीं है। इसे 1920 या 1921 माना जाता है। उनकी जन्म को भी लेकर 18,19 या 20 जुलाई की तिथियां प्रचार में रही हैं। लेकिन किशन महाराज को सामता प्रसाद से 14 वर्ष लंबी आयु मिली। सामता प्रसाद का निधन 1994 में हो गया था। दोनों ही कलाकारों की शिष्य मंडली और प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हैं, दूसरे नगरों में रहने के तमाम आमंत्रण मिलते रहे, खूब समारोहों में गए, यात्राएं कीं, पुरस्कार और सम्मान से नवाजे जाते रहे लेकिन लौटकर बार-बार बनारस की अपनी गलियों में आते रहे, समस्याओं से जूझते हुए जिद की तरह इस प्राचीन नगर में रहे, इसे छोड़कर कहीं और बस जाने के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन तबला के ये दिग्गज वादक मिजाज में एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न रहे। पं. किशन महाराज बनारस की तंग गलियों में पूरी ठाठ से रहते थे। उनके दरवाजे तक कोई चार पहिया वाहन भले न पहुंच पाता हो लेकिन जब उनके घर का दरवाजा खुलता तो विश्वास करना मुश्किल होता कि हम बनारस के किसी सघन इलाके में हैं। आकर्षक और विविध सुंदर पुष्पों का बड़ा-सा बगीचा, तरह-तरह के कबूतरों के पिंजरे जिनके बारे में वे बड़े शौक से बताते थे, पं. कंठे महाराज की प्रतिमा और तबलों से भरे ताखे, खूबसूरत ड्राईंग रूम और गणेश की मूर्ति वाला विशाल गणेश कक्ष। महाराज का रहन-सहन उनके शौक और सुरुचि संपन्नता के प्रतीक थे। इसके उलट सामता प्रसाद का घर उनकी सादगी का प्रतीक था। मिलने वालों को अक्सर जमीन पर ही बैठना होता, सामता प्रसाद प्रायः गमछे में ही मिलते, किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के आने की सूचना पर काला कुर्ता डाल लेते। गमछे में उनके होने का एक किस्सा मेरा आंखों देखा है। वे पड़ोस के नागरी नाटक मंडली सभागार में मुख्य अतिथि थे। समय पर नहीं पहुंचे तो आयोजकों ने खोजबीन की। पास की पान दुकान पर मिल गए। मंच पर बैठाया गया लेकिन बोलने के लिए माइक पर आने से मना कर दिया। वास्तव में वे गमछे में ही थे। मेज पर चादर बिछाने से उनका पैर ढंक गया था लेकिन खड़े होकर बोलने से इसका पता चल सकता था। फिर जब मेज पर ही माइक लगा तो वे बैठे-बैठे बोल सके।

पं. सामता प्रसाद के तबला वादन में भी उनके व्यक्तित्व जैसी सादगी और सफाई तो थी ही, रियाज का गहरा असर भी था। तबले पर उनके हाथ के वजन और बोलों के निकास के सभी कायल थे। उनके तबले में बायां (डग्गा) का काम देखते ही बनता था। उन्होंने इसकी स्याही को घुमाकर अपने और करीब रखकर बजाने की परंपरा शुरू की और बाएं-दाएं का संतुलन विकसित किया। उनका तबला दिल का तबला था जबकि पं. किशन महाराज का तबला दिमाग का तबला था। पं. किशन महाराज कभी पं. रविशंकर के साथ खूब बजाते थे जबकि पं. सामता प्रसाद उस्ताद विलायत खान के करीब रहे। प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार सचिन देव बर्मन ने 'नाचे मन मोरा मगन...' गीत की रिकार्डिंग पं. सामता प्रसाद के न पहुंच पाने के कारण स्थगित कर दी थी। इस गीत में तबले और उसके बाएं को खास तौर पर सुना जा सकता है। उनके बेटे राहुल देव बर्मन पंडित सामता प्रसाद के शिष्य बन गए थे। 'शोले' फिल्म में बसंती के तांगे से भागने के दृश्य में पार्श्व संगीत के तौर पर उनके तबला का ही इस्तेमाल हुआ है। बनारस अपने इस प्रिय तबला वादक को बराबर याद करता है। पिछले महीने उनकी पुण्यतिथि पर नमो घाट पर संगीत समारोह का आयोजन भी हुआ। जुलाई में उनकी जयंती है। ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

संभावनाओं की अंतर्दृष्टि

कलाकार यथार्थ जगत को अपनी कल्पना से किसी न किसी रूप में गढ़ा करता है एवं कलाकृतियों के रूप में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समग्रता से आकार देने का प्रयास करता है। यह रूप ही उसकी पहचान बनता है जिसमें खुलती और बंद होती कला को जब समझने का प्रयास करते हैं, तो रूप विन्यास के स्तर पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि कैसे कलाकृतियां भाव के स्तर पर प्रेक्षक से संबंध बनाने लगती हैं जहां ठिठकी सी कृति बिन बोले उससे संवाद कर रही होती है। नई दिल्ली की श्रीधारणी कला दीर्घा में 'युवा संभव 12' शीर्षक से प्रदर्शित युवा कलाकारों की सिरेमिक माध्यम में गढ़ी गईं कलाकृतियां...कुछ इसी तरह से प्रेक्षक के साथ संबंध स्थापित करती हैं।

12 शिल्पकारों की सुक्ष्म संवेदनशील गहराई के इस पड़ाव पर हम पाते हैं कि कलाकार स्थूल से होती सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ पाते हैं। कलाकारों की कलाकृतियों में रहस्यवाद, भाववाद के प्रभाव के साथ यथार्थवाद जैसा अन्वेषण हम देख पाते हैं। कृतियों को देखकर प्रतीत होता है कि शिल्पों में गति और भाव व्यंजन पर जोर दिया है। कृतियों के बदलते स्वरूप में विचार तत्व बहुत गहराई लिए हुए जिसमें सौंदर्य के साथ-साथ तकनीकी और रचनात्मकता का संयोजन अद्भुत है। यह शिल्पकार सेरेमिक कला में विकास की संभावनाएं जागृत करते हैं।

अजय सिंह वैचारिक दृष्टिकोण, सोच और अंतर्मन से उपजे भाव की मार्मिकता को दर्शाते हैं। समकालीन कलाकार आरती पालीवाल के शिल्प में कलात्मकता और विचारों की गहराई को दर्शाता आकर्षक प्रयोग है। देवेश उपाध्याय का 'एक्सिस्टेंटीएल स्ट्रगल' मानव आकृतियों के कई रूपों में उनके अस्तित्व संघर्ष का लघु प्रतिरूप है। बीरेंद्र यादव का टैराकोटा के माध्यम से 'माइग्रेटिंग आब्जैक्ट' शीर्षक से प्रदर्शित शिल्प पलायन की वेदना दर्शाता है। कोपल सेठ की दृष्टि, रचनात्मकता ऊर्जा और कल्पना एक नये मनु लोक में ले जाती है। 'ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल' शीर्षक की कृतियों में मूलभूत तकनीकों की अच्छी समझ है। अपनी कला को अगले स्तर तक ले जाने को कृतिका सोनी बखूबी जानती हैं। मौलिक ओजा का 'वार्फ एंड वेफ्ट' शीर्षक के माध्यम में रचा गया शिल्प प्रगतिवादी स्वरूप है। ओवांका भट्टाचार्जी ने अपनी भाव-प्रवण कृति 'व्हिस्पर ऑफ द अबैंडंड' को टैक्चर आदि के माध्यम से सिरेमिक में उकेरा है। श्रीनिया चौधरी का शैंडवेयर क्ले पर रचा गया शिल्प दर्शकों से संवाद करता सा दिखता है। सुवाजीत मंडल का 'आउट साइड विंडो' मर्मस्पर्शी है। रेवती जयकृष्णन का टैराकोटा दर्शक को आकर्षित करता है। सरबन चौधरी की कृतियां कलाकार की रचनात्मक और संवेदनशील सोच को दर्शाती हैं। रजा फाउंडेशन के अंतर्गत प्रदर्शनी का क्यूरेशन सुप्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार पीआर दारोज ने किया है।10 जुलाई तक प्रदर्शित यह प्रदर्शनी विचारशील प्रदर्शनियों में एक है।

गहरी संवेदनाओं की संभावना को किसी कलाकार की कलाकृति को निरखते-परखते वक्त दर्शक उसे स्वीकारने के लिए स्वतंत्र होता है क्योंकि किसी कलाकृति को वह तभी स्वीकार करेगा या करता है जब वह उस दर्शक की सौंदर्य क्षुधा को तृप्त कर सके। इसीलिए जब कोई कलाकार अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शकों से रूबरू होता है, तब उसके सामने दर्शकों या कलाप्रेमियों की सौंदर्य क्षुधा को तृप्त करने की चुनौती होती है। यहां यह चुनौती सरल सहज **रफीक शाह** के समक्ष भी रही होगी। युवा कलाकार रफीक की एकल कलाकृतियों की प्रदर्शनी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ऐनेक्सी कला दीर्घा में कलाप्रेमियों को प्रभावित करती है। कलाकृतियों का जो पक्ष उल्लेखनीय है, वह है रंग संयोजन। कहने को तो लाल, हरा, पीला, नीला, धूसर एवं स्याह सभी रंग उनके कैनवस में हैं, किन्तु अपने चटखपने के साथ खास तरह की सौम्यता के साथ। रफीक अपने चित्रों की बुनावट के लिए ज्यामितीय आकारों को खूब अपनाते हैं किन्तु इस क्रम में संयोजन की मौलिकता और अपने सहज अंदाज को बखूबी बरकरार रखते हैं।

देश के वरिष्ठ कलाकार अखिलेश द्वारा क्यूरेट 'ए पेंटर ऑफ साइलेंस' शृंखला के चित्रों में रफीक शाह कहीं-कहीं रंगों के स्वच्छंद प्रवाह को जहां बचाए रखते हैं वहीं कैनवस के किसी बड़े हिस्से में सपाट धरातल का भी इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है इस प्रक्रिया से कैनवास पर रंगों और आकारों का वह आरोह-अवरोह दृष्टिगत होता है, जो उनके चित्रों को सुखद सांगीतिक लयबद्धता से सराबोर कर देता है। रफीक शाह की प्रदर्शनी सुखद चाक्षुष अनुभूतियों से ओतप्रोत करती है जिसे 5 जुलाई तक देखा जा सकता है। ■

https://t.me/AllNewsPaperPaid